



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date:18/05/2024

**Documents of Clarification 1 for 5.1.4:
Proof of Internal Committees
/Grievances Committee formation/other
Committees as per UGC norms**


(Tridib Santapa Kundu)
Principal
Principal
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan

देव स्वरूप
Dr. Dev Swarup

संयुक्त सचिव
Joint Secretary



दूरभाष PHONE कार्यालय OFF : 011-23231273

फैक्स FAX : 011-23231291

E-mail : dev@ugc.ac.in

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह ज़फर मार्ग,

नई दिल्ली-110 002 (भारत)

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

BAHADUR SHAH ZAFAR MARG

NEW DELHI-110 002 (INDIA)

No.F.1-16/ 2009(CPP-II)

September, 2009

Registered

All Universities

12 OCT 2009

Subject: UGC Regulations on curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009.

Sir,

In continuation to this office letter of even no. dated 7th July, 2009 on the above subject, I am enclosing a copy of the UGC Regulations on curbing the menace of ragging in educational institutions, 2009 published in the Gazette of India dt.4th July,2009 in (i) English and (ii) Hindi) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रेगिंग निषेध से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009 for your information and necessary action.

The above regulations are mandatory and shall apply to all Universities established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State/Union Territory Act and all Institutions recognised by or affiliated to such Universities and all Institutions deemed to be Universities under Section (3) of the UGC Act, 1956 with effect from 4th July, 2009 i.e. the date of its Publication in the official Gazette.

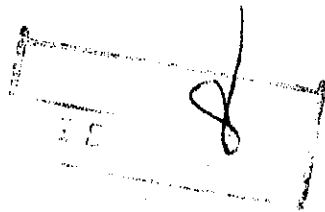
It is requested that these regulations may please be brought to the notice of the Colleges affiliated to your Universities/Institution.

Yours faithfully,

Dev Swarup

(Dev Swarup)
Joint Secretary

Encl: As above



o/c

Copy to:-

1. All States/ U.Ts Higher. Education Secretaries (List attached).
2. The Secretary, Govt. of India Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
3. Shri V. Umashankar, Director, Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
4. The Secretary, Association of Indian Universities (AIU), 16, Comrade Inderjit Gupta Marg (Kotla), New Delhi-110002
5. All Professional Councils.
6. Ps to Chairman/Ps to Vcm/Ps to Secretary, UGC, New Delhi
7. JS (Web site) UGC for posting on UGC website.
8. All Regional Offices, UGC.
9. Guard file

[Handwritten signature]
(V.K. Jaiswal)
Deputy Secretary
20.10.200
O/c

[Handwritten signature]
22/10/09



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 4—जुलाई 10, 2009 (आषाढ़ 13, 1931)
No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 4—JULY 10, 2009 (ASADHA 13, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून 2009

सं. एन-15/13/14/8/2008-यो. व वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम--1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा निगम--1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

केन्द्र

बढ़ते हुए निम्नलिखित क्षेत्र

उत्तमपालयम

जिला तेनी तालुक उत्तमपालयम के राजस्व गाँव

उत्तमपालयम तालुक जिला तेनी

उत्तमपालयम (दक्षिण), उत्तमपालयम (उत्तर), रायप्पनपट्टी, मल्लिंगपुरम्, कोहिलापुरम्, कोम्बै (पूर्व), कोम्बै (पश्चिम) तथा हनुमंथन पट्टी।

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं व.)

दिनांक 10 जून 2009

सं. एन-15/13/14/6/2008-यो. व वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम--1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा निगम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

केन्द्र

कंबम उत्तमपालयम जिला तेनी

बढ़ते हुए निम्नलिखित क्षेत्र/तेनी जिले के राजस्व गाँव

1. उत्तमपालयम तालुक के कंबम नगरपालिका क्षेत्र

2. उत्तमपालयम तालुक जिला तेनी के राजस्व गाँव

कामयकउण्डनपट्टी, नारायनतेवनपट्टी (दक्षिण), नारायनतेवनपट्टी (उत्तर)

उत्तमपुरम और सी. पुदुपट्टी

आर. सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं व.)

सं. एन-15/13/14/2/2009-यो. व वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम--1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा निगम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

केन्द्र

शिवागरी जिला में

देवकोट्टी तालुक के कारैकुडी उपनगरों

परेट्टकोट्टे

आदि के अन्तर्गत आने वाले राजस्व गाँव.....

आर. सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं व.)

सं. एन-15/13/10/2/2008-यो. व वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम--1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा उड़ीसा कर्मचारी राज्य बीमा निगम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

'डैकानाल जिला के डैकानाल तहसील में नरेन्द्रपुर शिबपुर, वरुंटी, खडग प्रसाद, तूलसीदिह एवं निमिधा के राजस्व गाँव।'

आर. सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं व.)

सं. एन-15/13/14/10/2009-यो. व वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम--1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में

महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा निगम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

केन्द्र

तुतुकोरिन जिला के पुदुक्कोट्टै क्षेत्र

1. मरवनमडम
2. कूत्तलुंगाडु
3. अल्लिकुलम
4. कुमरगिरी
5. साउत सिलुककानपट्टी
6. सेवैक्कडमडम
7. पेस्वरणी
8. सेन्तिलम्पणै आदि के अन्तर्गत आने वाले राजस्व गाँव.....

आर. सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं व.)

दिनांक 12 जून 2009

सं. एन-15/13/1/10/2008-यो. व वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम--1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा निगम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

'आन्ध्र प्रदेश राज्य के महबूबनगर जिले के फारूखनगर मण्डल में स्थित वेलजर्ला-1, 2, 3, और 'केशमपेट' मण्डल में स्थित 'थापीरेड्डीगुडा' के राजस्व ग्रामों की सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी क्षेत्र।'

आर. सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/14/7/2008-यो. व वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम--1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा निगम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

केन्द्र

चिन्नमनूर

निम्नलिखित बढ़ते हुए क्षेत्र तेनी जिले के राजस्व गाँव

1. उत्तमपालयम तालुक का चिन्नमनूर नगरपालिका क्षेत्र
2. उत्तमपालयम तालुक जिला तेनी के राजस्व गाँव, पूलानन्तापुरम, करुंकाट्टनवुलम चिन्नावेलापुरम मुत्तलापुरम, मरकायनकोट्टै, पुलिकुत्ति, कुच्चानुर, ओडैपट्टी।

आर. सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से सम्बन्धित विश्वविद्यालय
अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 धारा 26 (1) (जी) के अन्तर्गत)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 17 जून 2009

मि०सं० 1-16/2007(सी.पी.पी.-II)

उद्देशिका

माननीय उच्चतम न्यायालय के केरल विश्वविद्यालय बनाम काउंसिल प्रिंसिपल कॉलेज तथा अन्य, एस०एल.पी० सं० 24295, 2006 के 16-5-2007 तथा दिनांक 08-5-2009, सिविल अपील नं. 887 से प्राप्त निर्देशों तथा केन्द्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग निषेध तथा रैगिंग रोकने के संकल्प को ध्यान में रखते हुए। छात्र अथवा छात्रों द्वारा मौखिक शब्दों अथवा लिखित कार्य द्वारा नए अथवा अन्य छात्र को उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, छात्र को उत्पात अथवा अनुशासनहीनता की गतिविधियों में संलिप्त करना जिससे नए अथवा किसी अन्य छात्र को कष्ट, परेशानी, कठिनाई अथवा मनोवैज्ञानिक हानि हो अथवा उसमें भय की भावना उत्पन्न हो अथवा नए या अन्य किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में करे तथा जिससे उसमें लज्जा की भावना उत्पन्न हो अथवा घबराहट हो जिससे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किसी छात्र पर दुष्प्रभाव पड़े अथवा कोई छात्र नए अथवा अन्य छात्र पर शक्ति प्रदर्शन करें। देश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में समुचित विकास हेतु शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अन्य समितियों से विचार विमर्श के पश्चात् ये अधिनियम बनाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 धारा 26 उप खण्ड (जी) उपखण्ड (1) के अधिकारों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, जिसका नाम है—

1. शीर्षक, प्रारम्भ और प्रयोज्यता

- 1.1 ये अधिनियम "विश्वविद्यालय अनुदान के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के अधिनियम, 2009" कहे जाएँगे।
- 1.2 ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा (2) उपखंड (एफ) के अनुसार / विश्वविद्यालय की परिभाषा के अन्तर्गत आनेवाली सभी संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 धारा 3 के अनुसार सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा अन्य सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं तथा इस प्रकार के विश्वविद्यालय के सम्बन्धित तत्वों से युक्त संस्थाओं, विभागों, इकाइयों तथा अन्य सभी शैक्षिक, आवासीय, खेल के मैदान, जलपान गृह तथा विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं चाहे वे परिसर के भीतर हों अथवा बहार तथा छात्रों के सभी प्रकार के परिवहन चाहे वे सरकारी हों अथवा निजी छात्रों द्वारा इस प्रकार के विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे।

2. उद्देश्य

किसी छात्र अथवा छात्रों के द्वारा दूसरों को मौखिक अथवा लिखित शब्दों द्वारा प्रताड़ित करना, उसे छेड़ना किसी नए छात्र के साथ दुर्व्यवहार करना अथवा उसे अनुशासनहीन गतिविधियों में लगाना जिससे आक्रोश, कठिनाई, मनोवैज्ञानिक हानि हो अथवा किसी नए अथवा अन्य किसी छात्र में भय की भावना उत्पन्न हो अथवा किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में नहीं करे अथवा ऐसा कार्य कराना जिससे उसमें लज्जा की भावना उत्पन्न हो, पीड़ा हो घबराहट हो अथवा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दुष्प्रभाव पड़े अथवा शक्ति प्रदर्शन करना अथवा किसी छात्र का वरिष्ठ होने के कारण शोषण करना। अतः सभी विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा देश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में इन अधिनियम के अन्तर्गत रैगिंग रोकना। इस तरह की घटनाओं में संलिप्त व्यक्तियों को इन अधिनियम तथा विधि के अनुसार दण्डित करना।

3. रैगिंग कैसे होती है—

निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य रैगिंग के अन्तर्गत आएँगे—

- क किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आनेवाले छात्र का मौखिक शब्दों अथवा लिखित वाणी द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार करना।
- ख छात्र अथवा छात्रों द्वारा उत्पात करना अथवा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना जिससे नए छात्र को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।
- ग किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे नए छात्र में लज्जा, पीड़ा, अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।
- घ वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए शैक्षिक कार्य में बाधा पहुँचाएँ।
- ङ नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिए गए शैक्षिक कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना।
- च नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना।
- छ शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य/किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे।
- ज मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई-मेल, डाक, पब्लिकली किसी को अपमानित करना, किसी को कुमार्ग मार्ग पर ले जाना, स्थानापन्न अथवा कष्टदाय देना या सनसनी पैदा करना जिससे नए छात्र को घबराहट हो।
- झ कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े। नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले लाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।

4. परिभाषाएँ

- 1 इन अधिनियमों में जब तक कि कोई अन्य संदर्भ न हो।
- क अधिनियम का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956/3) है।
- ख शैक्षिक वर्ष का तात्पर्य किसी संस्था में किसी छात्र का किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश तथा उस वर्ष की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति है।
- ग रैगिंग विरोधी हैल्पलाईन का तात्पर्य इन अधिनियमों के अधिनियम 8.1 की धारा (ए) है।
- घ आयोग का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है।
- ङ समिति (कौंसिल) का तात्पर्य संसद अथवा राज्य के विधानमंडल द्वारा नियमित उच्चतर शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग तथा स्तर बनाए रखने हेतु गठित समिति है। यथा आल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नीकल एजुकेशन (ए.आई.सी.टी.ई.) बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बी.सी.आई.) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डी.सी.आई.) डेन्टिस एजुकेशन काउंसिल (डी.ई.सी.) दी इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (आइ.सी.ए.आर.) इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आई.एन.सी.) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एम.सी.आई.) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) प्राइमरी काउंसिल ऑफ इंडिया (पी.सी. आई.) इत्यादि तथा राज्यों के उच्चतर शिक्षा काउंसिल इत्यादि।
- च जिला स्तरीय रैगिंग विरोधी समिति का तात्पर्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा रैगिंग रोकने के लिए जिले की परिसीमा में गठित समिति है।
- छ संस्थाध्यक्ष का तात्पर्य विश्वविद्यालय अथवा डीम्ड विश्वविद्यालयों हेतु कुलपति अथवा किसी संस्था का निदेशक, कॉलेज का प्राचार्य सम्बन्धित का कार्यकारी अध्यक्ष है।
- ज "फ़ेशर" से तात्पर्य वह छात्र है जिसका प्रवेश किसी संस्था में हो गया है तथा उस संस्था में उसकी पढ़ाई का प्रथम वर्ष चल रहा है।

- अ संस्था का तात्पर्य वह उच्चतर शिक्षण संस्था है जो चाहे विश्वविद्यालय हो डीम्ड विश्वविद्यालय हो, कॉलेज अथवा राष्ट्रीय महत्व की कोई संस्थान हो जिसकी रचना संसद के अधिनियम के अनुसार की गई हो। इसमें 12 वर्ष स्कूल की शिक्षा के बाद की शिक्षा दी जाती हो कोई आवश्यक नहीं है कि उसमें चरम सीमा तक उपाधि दी जाती हो। स्नातक/स्नातकोत्तर तथा उच्चतर स्तर अथवा विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र की।
- ब एन.ए.ए.सी. का तात्पर्य आयोग द्वारा अधिनियम की 12(सी.सी.सी.) के अनुसार स्थापित नेशनल एकेडमिक एंड ऐफिडिटेशन काउंसिल है।
- ट राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग सेल का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा विधि के अनुसार अथवा केन्द्र सरकार की सलाह पर रैगिंग रोकने के लिए बनाया गया निकाय है। जिसका कार्यक्षेत्र राज्य तक होगा।
- 2 शब्द तथा अभिव्यक्ति को यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम अथवा अधिनियम के सामान्य खण्ड 1887 वही अर्थ होगा जो उसमें दिया गया है।

5. संस्था स्तर पर रैगिंग निषेध के उपाय—

- क कोई भी संस्था अथवा उसका कोई भाग, उसके तत्वों सहित केवल विभागों तक नहीं उसकी संघ तक ईकाई, कॉलेज, शिक्षण केन्द्र, उसके भू-गृह चाहे वे शैक्षिक, आवासीय खेल के मैदान अथवा जलपान गृह आदि चाहे वे विश्वविद्यालय परिसर में हो अथवा बाहर, सभी प्रकार के परिवहन, या निजी सभी में रैगिंग रोकने हेतु इन विनियमों के अनुसार तथा अन्य सभी आवश्यक उपाय करेंगे। रिपोर्ट होने पर रैगिंग की किसी भी घटना को दबाया नहीं जाएगा।
- ख सभी संस्थाएं रैगिंग के प्रचार, रैगिंग में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध इन विनियम के अनुसार कार्रवाई करेंगे।
6. संस्था स्तर पर रैगिंग रोकने के उपाय
- 5.1 छात्रों के प्रवेश अथवा पंजीकरण के संदर्भ में संस्था निम्नलिखित कदम उठाए।
- क संस्था द्वारा जारी इलेक्ट्रानिक दृश्य, श्रव्य अथवा प्रिन्ट मीडिया के छात्र को

- प्रवेश संबंधी घोषणा में यही बताया जाए कि संस्था में रैगिंग पूर्णतः निषेध है। यदि कोई रैगिंग करने अथवा उसके प्रचार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दोषी पाया गया अथवा रैगिंग प्रचार के षडयंत्र में दोषी पाया गया तो उसे इन विनियम तथा देश के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा।
- ख प्रवेश की पुस्तिका के निर्देश पुस्तक तथा विवरण पत्रिका चाहे वे इलेक्ट्रॉनिक हो अथवा मुद्रित उनमें ये विनियम विस्तार से छापे जाएँ। प्रवेश पुस्तिका का निर्देश पुस्तिका विवरण पत्रिका में यह भी मुद्रित किया जाए कि रैगिंग होने या संस्था के अध्यक्ष इसके साथ संस्थाध्यक्ष, संकाय सदस्य रैगिंग विरोधी समिति के सदस्यों, रैगिंग विरोधी दस्तों के सदस्यों अथवा जिले के अधिकारियों, वार्डनों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के दूरभाष नम्बर प्रवेश पुस्तिका, निर्देश पुस्तिका अथवा विवरण पत्रिका में विस्तार से छापे जाएँ।
- ग जहाँ कोई संस्था किसी विश्वविद्यालय से संबंध है वहाँ विश्वविद्यालय यह निश्चित कर ले कि प्रवेश पुस्तिका, निर्देश पुस्तिका यह विवरण पत्रिका प्रकाशित करें तो यह विनियम के विनियम 6.1 के खण्ड (ए) और खण्ड (बी) का अनुपालन करें।
- घ प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र, नामांकन अथवा पंजीकरण में एक शपथ पत्र आवश्यक रूप से अंग्रेजी और हिन्दी/अभ्यर्थी की ज्ञात किसी एक प्रादेशिक भाषा में इन विनियम के संलग्नक 1 के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए तथा हस्ताक्षर किया जाए कि उसने किसी अधिनियम के नियमों के पढ़ लिया है तथा इन विनियम के नियमों तथा विनियम के नियमों तथा विधि को समझ लिया है तथा वह रैगिंग निषेध तथा इसके लिए निर्धारित दंड को जानता/जानती है। वह यह घोषणा करता/करती है कि उसे किसी संस्था द्वारा निष्कासित/निकाला नहीं गया है। साथ ही वह रैगिंग संबंधी किसी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा/होगी और यदि वह रैगिंग करने अथवा रैगिंग के दुष्प्रेरण का दोषी पाया/पायी गई तो उसे इन विनियम तथा विधि के अनुसार दंडित किया जा सकता है और वह दंड केवल निष्कासन तक सीमिति नहीं होगा।
- ङ प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र, नामांकन अथवा पंजीकरण में एक शपथ पत्र अंग्रेजी

और हिन्दी तथा किसी एक प्रादेशिक भाषा या हिन्दी भाषा में इन विनियमों के साथ संलग्नक हैं। अभ्यर्थी के माता-पिता अभिभावक की ओर से दिया जाए कि उन्होंने रैगिंग के अधिनियम को पढ़ लिया है तथा समझ लिया है तथा रैगिंग रोकने संबंधित अन्य कानून को वो जानते हैं तथा इसके लिए निर्धारित दंड को जानते हैं। वे घोषणा करते हैं कि उनका वार्ड किसी संस्था द्वारा निष्कासित नहीं किया गया है और न ही निकाला गया है तथा उनका वार्ड रैगिंग से सम्बन्धित किसी कार्य में प्रत्यक्ष/परोक्ष अथवा रैगिंग के दुष्प्रेरण में भाग नहीं लेगा और यदि वह इसका दोषी पाया गया तो उनको इन विनियम तथा कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। यह दंड केवल निष्कासन तक सीमित नहीं होगा।

- च प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र के साथ स्कूल लीविंग/स्थानांतरण प्रमाण-पत्र/प्रवास प्रमाण-पत्र/चरित्र प्रमाण पत्र हो जिसमें छात्र के व्यक्तिगत तथा समाजिक व्यवहार की जानकारी दी गई हो ताकि संस्था इसके बाद उस पर नजर रख सके।
- छ संस्था के/संस्था द्वारा व्यवस्थित व्यवस्था किए गए छात्रावास की प्रार्थना करने वाले छात्र को प्रार्थना पत्र के साथ एक अतिरिक्त शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र पर उसके माता/पिता/अभिभावक के भी हस्ताक्षर होंगे।
- ज किसी भी संस्था में शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व संस्था अध्यक्ष विभिन्न अधिकारियों/अभिकरणों जैसे छात्रपाल (वार्डन) छात्र प्रतिनिधि, छात्रों के माता-पिता अभिभावक, जिला प्रशासन पुलिस आदि की मीटिंग आयोजित करे तथा रैगिंग रोकने के उपयों और उसमें संलिप्त अथवा उसका दुष्परिणाम करने वालों को चिन्हित कर दण्डित करने पर विचार-विमर्श हेतु उसे सम्बोधित करें।
- झ समुदाय विशेष रूप से छात्रों को रैगिंग के अमानवीय प्रभाव के संदर्भ में जागृत करने हेतु तथा संस्था उसके प्रति रवैये से अवगत कराने हेतु बड़े पोस्टर (वरीयता से बहुरंगी) नियम विधि तथा दंड हेतु छात्रावास, विभागों तथा अन्य भवनों के सूचना पट्ट पर लगाया जाए। उनमें से कुछ पोस्टर स्थायी रूप के हों जिन स्थानों पर छात्र एकत्र होते हैं वहां रैगिंग का आघात किए

- जाने योग्य स्थानों पर विशेष रूप से ऐसे पोस्टर लगाए जाएँ।
- ज संस्था मीडिया से यह अनुरोध करे कि वह रैगिंग रोकने के नियमों का प्रचार-प्रसार करे। संस्था के रोकने और उसमें लिप्त पाए जाने पर बिना भेद-भाव एवं शय के दण्डित करने के नियम प्रचार करें।
- ट संस्था द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को समझाया जाए तथा असुरक्षित स्थानों पर दृष्टि रखी जाए। संस्था द्वारा परिसर में विषम समय तथा शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए तथा रैगिंग किए जाने योग्य स्थानों पर दृष्टि रखी जाए। पुलिस, रैगिंग विरोधी सचल दल तथा स्वयं सेवी (यदि कोई हो) व्यक्तियों से इसमें सहायता ली जाए।
- ठ संस्था अवकाश के समय को नए शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ से पूर्व रैगिंग के विरुद्ध संगोष्ठी, पोस्टर, पत्रिका, नुक्कड़ नाटक आदि के द्वारा प्रचार करें।
- ड संस्था के विभिन्न तंत्र संकाय/विभाग/इकाई आदि।
- ढ संस्था के संकाय/विभाग/इकाई आदि छात्रों की विशेष आवश्यकताओं का पूर्वानुमान कर निवारण करें तथा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व रैगिंग निषेध संबंधी अधिनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विधिवत् प्रबन्ध करें।
- ण प्रत्येक संस्था अकादमिक सत्र प्रारम्भ होने से पहले पेशेवर काउंसिलरों की सेवा अथवा सहायता ले और वे शैक्षिक वर्ष प्रारम्भ होने के बाद भी नए तथा अन्य छात्रों की काउंसिलिंग के लिए उपलब्ध हों।
- त संस्थाध्यक्ष स्थानीय पुलिस तथा अधिकारियों को वित्तीय आधार पर प्रबन्ध किए गए छात्रावास तथा निवास हेतु प्रयोग किये जा रहे भवन के संबन्ध में विस्तृत जानकारी दें। संस्थाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करें कि रैगिंग विरोधी दल ऐसे स्थानों पर रैगिंग रोकने हेतु चौकसी रखें।
- 6.2 छात्रों का प्रवेश, नामांकन अथवा पंजीकरण होने पर निम्नलिखित कदम उठाए, जिसका नाम इस प्रकार है—
- क संस्था में प्रवेश दिए गए प्रत्येक छात्र को एक मुद्रित पर्णिका दी जाए जिसमें यह बताया गया हो कि उसे विभिन्न उद्देश्यों हेतु किससे निर्देशन प्राप्त करना

है। इसमें विभिन्न अधिकारियों के दूरभाष नं० तथा पते भी दिए जाएँ ताकि आवश्यकता पड़ने पर छात्र किसी भी संबंधित व्यक्ति से तुरन्त संपर्क करें। इन विनियम में संदर्भित रैगिंग विरोधी हैल्पलाईन, वार्डन, संस्थाध्यक्ष तथा रैगिंग विरोधी समिति तथा दल के सदस्यों तथा संबंधित जिले तथा पुलिस के अधिकारियों के पते और दूरभाष नं० विशेष रूप से समाहित किए जाएँ।

ख संस्था इन विनियम के विनियम 6.2 खण्ड (ए) में निर्देश दिए गये हैं। प्रबंधक को नए छात्रों को दी जानेवाली पर्णिका द्वारा स्पष्ट करें तथा उन्हें अन्य छात्रों से भलीभाँति परिचित कराने हेतु कार्य करें।

ग इन विनियमों के विनियम 6.2 खण्ड (ए) में निर्देशित पर्णिका द्वारा नए छात्रों को संस्था के बोनाफाइड स्टूडेंट के रूप में उनके अधिकार भी बताए जाएँ। उन्हें यह भी बताया जाए कि वे अपनी इच्छा के बिना किसी का कोई कार्य न करें चाहे उनके लिए उनके वरिष्ठ छात्रों ने कहा हो तथा रैगिंग के प्रयास के सूचना तुरन्त रैगिंग विरोधी दल, वार्डन अथवा संस्थाध्यक्ष को दे दें।

घ इन विनियमों के विनियम 6.2 खण्ड (ए) में निर्देशित पर्णिका में संस्था में मनाए जानेवाले विभिन्न कार्यक्रमों तथा गतिविधियों की तिथि दी हो ताकि नए छात्र संस्था के शैक्षिक परिवेश एवं वातावरण से परिचित हो सकें।

ङ वरिष्ठ छात्रों के आने पर संस्थान प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह के बाद जैसा भी हो अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करें जिनका नाम — (i) संयुक्त सैसेटाइजेशन प्रोग्राम और वरिष्ठ और कनिष्ठ छात्रों की काउंसिलिंग व्यावसायिक कनाउन्सर के साथ खण्ड — 6.1 नियम के विनियम के अनुसार करे (ii) नये और पुराने छात्रों को संयुक्त अभिविन्यास कार्यक्रम को संस्था तथा रैगिंग विरोधी समिति सम्बोधित करे (iii) संकाय सदस्यों की उपस्थिति में नये और पुराने छात्रों के परिचय हेतु अधिकाधिक, सांस्कृतिक खेल तथा अन्य प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की जाये (iv) छात्रावास में वार्डन सभी छात्रों को सम्बोधित करे तथा अपने दो (2) कनिष्ठ सहयोगियों से कुछ समय तक सहयोग देने हेतु निवेदन करे (v) जहाँ तक संभव हो संकाय-सदस्य हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के साथ भोजन भी करे ताकि नये छात्रों में आत्मविश्वास

- का भाव उत्पन्न हो।
- च संस्था समुचित समितियों का गठन करे। कोर्स इंचार्ज, वार्डन तथा कुछ वरिष्ठ छात्र इन समितियों के सदस्य हों। यह समिति नये और पुराने छात्रों के बीच सम्बंध सुदृढ़ बनाने में सहयोग दे।
- छ नये अथवा अन्य छात्र चाहे वे रैगिंग के भोगी हों अथवा रैगिंग होते हुए उन्होंने दोषी बने देखा हो उन्हें ऐसी घटनाओं की सूचना देने हेतु उत्साहित किया जाए ताकि उनकी पहचान सुरक्षित रखी जाए और ऐसी घटनाओं की सूचना देने वालों को किसी दुष्परिणाम से बचाया जाए।
- ज संस्था में आने पर नये छात्रों के प्रत्येक बैच को छोटे-छोटे वर्गों में बांट दिया जाए और ऐसा प्रत्येक वर्ग किसी एक संकाय सदस्य को दे दिया जाए जो स्वयं वर्ग ग्रुप के सभी सदस्यों से परिचित हो और यह देखे कि नये छात्रों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो यदि हो तो उसका समाधान करने में उचित सहायता करे।
- झ इस प्रकार की समिति के संकाय सदस्य का यह दायित्व होगा कि वार्डनों को सहयोग दे तथा छात्रावास में औचक निरीक्षण करते रहें। जहाँ संकाय सदस्य की अपने अधीन छात्रों की डायरी मन्टेन करें।
- ञ नये छात्रों को अलग छात्रावास में रखा जाये और जहाँ इस प्रकार की सुविधायें न हों वहाँ संस्था यह सुनिश्चित करे कि नये छात्रों को दिये गये निवास स्थानों पर वार्डन तथा सुरक्षा गार्ड और कर्मचारी कड़ी निगरानी रखें।
- ट संस्था 24 घंटे छात्रावास परिसर में रैगिंग रोकने के लिए कड़ी नजर रखने का प्रबन्ध करे।
- ठ नये छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों का यह दायित्व होगा कि रैगिंग से सम्बन्धित सूचना संस्था-अध्यक्ष को प्रदान करें।
- ड प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र जो संस्था में पढ़ रहा हो। वह और उसके माता-पिता/अभिभावक प्रवेश के समय निर्देशित शपथ पत्र दे जैसा कि विनियम के विनियम 6.1 खण्ड (डी) (ई) और (जी) के अनुसार दिया जाना। प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में चाहिए।

- द प्रत्येक संस्था विनियम (6.2) खण्ड -- एल के सन्दर्भ अनुसार प्रत्येक छात्र से शपथ पत्र ले और उनका उचित रिकार्ड रखे। प्रतिलिपियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखे ताकि जब आवश्यकता हो कमीशन अथवा कोई संकलित अथवा संस्था अथवा सम्बन्धित विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य सक्षम व्यक्ति अथवा/संघटन द्वारा उन्हें प्राप्त किया जा सके।
- ण प्रत्येक छात्र/छात्रा अपने पंजीकरण के समय संस्था को अपनी पढ़ाई करते समय निवास स्थान की सूचना दे यदि उसका निवास स्थान तय नहीं किया है या वह अपने निवास बदलना चाहता/चाहती है तो उसका निश्चय होती ही विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाए और विशेष रूप से निजी खर्च पर व्यक्ति किये गये भवनों अथवा छात्रावासों की जहां वह रह रहा है/रही है।
- ण आयोग शपथ पत्रों के आधार पर एक उचित आंकड़ा बनाये रखे जो प्रत्येक छात्र और उसके माता/पिता/अभिभावक द्वारा संस्था को उपलब्ध कराया गया हो। इस प्रकार का आंकड़ा रैगिंग की शिकायतों तथा उसके बाद की गयी कार्यवाही का रिकार्ड भी रखे।
- त आयोग द्वारा आंकड़ा गैर सरकारी निकाय जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया गया हो को उपलब्ध कराया जाये इससे आम जनता में विश्वास तथा समिति के आदेश का अनुपालन न करने की सूचना दी जा सके।
- थ प्रत्येक शैक्षिक वर्ष पूर्ण होने पर संस्थाध्यक्ष प्रथम वर्ष पूर्ण करनेवाले छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों को रैगिंग से सम्बन्धित विधि और जानकारी से सम्बन्धित पत्र भेजें तथा उनसे अनुरोध करें कि नए शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में वापस आने पर उनके स्वयं बालक रैगिंग से सम्बन्धित किसी गतिविधि में भाग न लें।

- 6.3 प्रत्येक संस्था निम्नलिखित नामों से समितियाँ गठित करें।
- क प्रत्येक संस्था एक समिति बनाए जिसे रैगिंग विरोधी समिति (एंटी रैगिंग कमेटी) कहा जाए। समिति की अध्यक्षता संस्थाध्यक्ष करें तथा समिति के सदस्यों को वे ही नामांकित करें। इसमें पुलिस तथा नागरिक प्रशासन के प्रतिनिधि भी हो। स्थानीय मीडिया युवा गतिविधियों से जुड़े गैर सरकारी संघटक संकाय सदस्यों के प्रतिनिधि, माता-पिता में से प्रतिनिधि, नए तथा पुराने छात्रों के प्रतिनिधि, शिक्षणेत्र कर्मचारी तथा विभिन्न वर्गों से प्रतिनिधि समिति में से लिंग के आधार पर इस समिति में स्त्री पुरुष दोनों हों।
- ख रैगिंग विरोधी समिति का कर्तव्य होगा कि वह इन विनियम प्रावधान तथा रैगिंग से सम्बन्धित कानून का अनुपालन कराए तथा रैगिंग विरोधी दल के रैगिंग रोकने सम्बन्धी कार्यों को भी देखे।
- ग प्रत्येक संस्था एक छोटी समिति का भी गठन करे जिसे रैगिंग विरोधी (एंटी रैगिंग स्क्वैड) नाम से जाना जाए। इसे भी संस्थाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए। यह समिति सज्ज रहने तथा हर समय पैटरॉलिंग और गतिशील बनी रहने हेतु तत्पर रहे।
- रैगिंग विरोधी दल/स्क्वैड में कैम्पस के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। इसमें परिसर से बाहर के व्यक्ति नहीं होंगे।
- घ रैगिंग विरोधी दल का यह दायित्व होगा कि वह छात्रावास तथा रैगिंग की दृष्टि से संवेदनशील अन्य स्थानों का घटना की औचक निरीक्षण करें।
- ङ रैगिंग विरोधी दल का यह दायित्व होगा कि वह संस्थाध्यक्ष अथवा अन्य किसी संकाय सदस्य अथवा किसी कर्मचारी अथवा किसी छात्र अथवा किसी माता-पिता अथवा अभिभावक द्वारा सूचित की गई रैगिंग की घटना की जाँच घटना स्थल पर जाकर करे तथा जाँच की रिपोर्ट संस्तुति सहित रैगिंग विरोधी समिति को विनियम 9.1 उपखण्ड (ए) के अनुसार कार्रवाई हेतु सौंपे।

रैगिंग विरोधी दल इस प्रकार की जाँच निष्पक्ष एवं पारदर्शी विधि से करे तथा सामान्य न्याय का पालन किया जाए। रैगिंग के दोषी पाए जानेवाले

- छात्र/छात्रों तथा गवाहों को पूरा अवसर देने तथा तथ्य एवं प्रमाण आदि देखने के बाद इसकी सूचना प्रेषित की जाए।
- 6.3 प्रत्येक संस्था शैक्षिक वर्ष पूर्ण होने पर इन विनियम के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु एक मॉनिटरिंग सेल बनाए जिसमें नए छात्रों को मॉनेटर करनेवाले स्वयंसेवी छात्र हों। नए छात्रों पर एक मॉनेटर होना चाहिए।
- छ प्रत्येक विश्वविद्यालय, एक समिति का गठन करे जिसे रैगिंग के मॉनिटरिंग सेल के रूप में जाना जाए, जो उस संस्था अथवा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेजों में इन विनियम के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु सहयोग दें। मॉनिटरिंग सेल संस्थाध्यक्षों रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दल से रैगिंग गतिविधियों की सूचना प्राप्त कर सकता है। वह जिलाधिकारी को अध्यक्षता में गठित/जनपद स्तरीय रैगिंग विरोधी समिति के सम्पर्क में रहे।
- ज मॉनिटरिंग सेल; संस्था द्वारा किए जा रहे रैगिंग विरोधी उपायों का भी मूल्यांकन करेगी। माता-पिता/अभिभावकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में दिए गए शपथ पत्र तथा रैगिंग के नियम तोड़ने पर दण्डित किए जाने हेतु उनकी सहमति की भी जांच करेगा। यह दोषियों को दण्डित किए जाने हेतु उसकी मुख्य भूमिका होगी। रैगिंग विरोधी उपायों के कार्यान्वयन में भी इसकी मुख्य भूमिका होगी।
- 6.4 **प्रत्येक संस्था निम्नलिखित उपाय भी करे, जिनका नाम हो—**
- क प्रत्येक छात्रावास अथवा स्थान जहाँ छात्र रहते हैं। संस्था के उस भाग में पूर्णकालिक वार्डन हों जिसकी नियुक्ति संस्था द्वारा अर्हता के नियमानुसार की जाय जो अनुशासन बनाये रखें तथा छात्रावास में रैगिंग की घटनाओं को रोकने के साथ ही युवाओं से कक्षा के बाहर काउंसलिंग और सम्बंध बनाये रखे। वह छात्रावास में रहे या छात्रावास के अत्यन्त निकट रहे।

- ख वार्डन हर समय उपलब्ध हो। दूरभाष तथा संचार के अन्य साधनों से हर समय सम्पर्क किया जा सके। वार्डन को संस्था द्वारा मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जाये जिसके नम्बर की जानकारी छात्रावास में रह रहे सभी छात्रों को हो।
- ग संस्था द्वारा वार्डन तथा रैगिंग रोकने से सम्बन्धित अन्य अधिकारियों के अधिकार बढ़ाने का विचार किया जा सकता है। छात्रावास में नियुक्त सुरक्षाकर्मी सीधे वार्डनों के नियंत्रण में हों तथा वार्डन द्वारा उनके कार्य का मूल्यांकन किया जाए
- घ इन विनियमों के विनियम 6.1 उपखण्ड (ओ) के अनुसार प्रवेश के समय पेशेवर काउंसिलर रखे जायें जो नये और अन्य छात्र जो अपने आने वाले जीवन की तैयारी हेतु विशेष रूप छात्रावास में रहने से सम्बन्धित काउन्सिलिंग चाहते हो उनहें काउंसिलिंग करें। ऐसे काउन्सिलिंग सत्रों से माता-पिता तथा शिक्षकों को भी जोड़ा जायें।
- ङ संस्था रैगिंग विरोधी उपायों का व्यापक काउन्सिलिंग सत्र, कार्यशाला, पेंटिंग द्वारा यह कार्य किया जा सकता है।
- च संस्था के संकाय सदस्य उसका शिक्षणेतर कर्मचारी, जो केवल प्रशासनिक पद तक सीमित नहीं है, सुरक्षा गार्डस तथा संस्था के अन्दर सेवा करनेवाले कर्मचारियों को रैगिंग तथा उसके दुष्परिणाम के प्रति संवेदनशील बनाया जाए।
- छ संस्था/शिक्षण एवं शिक्षणेतर प्रत्येक कर्मचारी से संविदा पर रखे गए प्रत्येक श्रमिक से चाहे वे कैंटीन के कर्मचारी हों अथवा सुरक्षा गार्ड हों या सफाई वाले कर्मचारी हों सबसे एक अनुबन्ध ले कि वे अपनी जानकारी में आनेवाले रैगिंग की घटना की जानकारी तुरन्त सक्षम अधिकारियों को देंगे।
- ज संस्था द्वारा सेवा कार्य की नियमावली में रैगिंग की सूचना देनेवाले कर्मचारियों को अनुशंसा पत्र देने का नियम बनाए तथा उसे उनके सेवा रिकॉर्ड में रखा जाए।

- झ संस्था द्वारा कैटीन और मैस के कर्मचारियों, चाहे वे संस्था के कर्मचारी हों अथवा निजी सेवा देने वाले हो को निर्देशित किया जाए कि वे अपने क्षेत्र में कड़ी नजर रखें तथा रैगिंग की कोई भी घटना होने पर उसको जानकारी तुरन्त संस्थाध्यक्ष रैगिंग विरोधी समिति के सदस्यों अथवा वार्डन को दें।
- ञ शिक्षा की किसी भी स्तर की उपाधि देनेवाली संस्था यह देख ले कि उसके पाठ्यक्रम में रैगिंग विरोधी कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाए। मानव अधिकारों की रक्षा पर बल दिया जाए। विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में रैगिंग की संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला जाए। प्रत्येक शिक्षक काउन्सिलिंग के स्थिति से निबटने का ढंग आना चाहिए।
- ट प्रथम वर्ष नए विद्यार्थियों की ओर हर पन्द्रह दिन में गुमनाम बेतरतीब सर्वेक्षण कि जाएँ। यह देखने के लिए कि संस्था में रैगिंग नहीं हो रही है। सर्वेक्षण की रूपरेखा संस्था स्वयं निश्चित करे। संस्था द्वारा छात्र को दिए जानेवाले विश्वविद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में छात्र के सामान्य चरित्र और व्यवहार के अतिरिक्त यह भी दिया जाए कि क्या छात्र कभी रैगिंग सम्बन्धी अपराध में संलिप्त रहा है। क्या छात्र ने कोई हिंसक अथवा दूसरे को हानि पहुँचाने वाला अपराध किया है।
- ड इन विनियमों विभिन्न अधिकारियों सदस्यों तथा समितियों के अधिकार बताए गए हैं। इसके साथ ही सभी वर्गों के अधिकारियों संकाय के सदस्यों तथा कर्मचारियों सहित चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी जो भी संस्था की सेवा कर रहा है उसका यह सामूहिक दायित्व होगा कि वह रैगिंग की घटनाओं को रोके।
- ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाध्यक्ष अथवा अन्य संस्था का अध्यक्ष सत्र के प्रारम्भिक तीन महीने तक रैगिंग के आदेश के अनुपालन तथा रैगिंग विरोधी उपायों की जानकारी से सम्बन्धित इन विनियम के अधीन साप्ताहिक रिपोर्ट उस विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा जिसके द्वारा वह संस्था रिकॉग्नाइज की गई हैं। उसे दें।
- ढ प्रत्येक विश्वविद्यालय को कुलपति महोदय विश्वविद्यालय तथा रैगिंग की देखरेख करनेवाले सेल की रिपोर्ट प्रत्येक पन्द्रह दिन बाद राज्य स्तरीय देख रेख करने

वाले सेल को दे।

7 संस्थाध्यक्ष द्वारा की जानेवाली कार्रवाई—

- I. रैगिंग विरोधी दल अथवा सम्बन्धित किसी के भी द्वारा रैगिंग की सूचना प्राप्त होने पर संस्थाध्यक्ष तुरन्त सुनिश्चित करें कि क्या कोई अवैध घटना हुई है और यदि हुई है तो वह स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत रैगिंग विरोधी समिति से सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराए अथवा रैगिंग से सम्बन्धित विधि के अनुसार संस्तुति दे। रैगिंग के अंतर्गत निम्नलिखित अपराध आते हैं।
- II. रैगिंग हेतु उकसाना
- III. रैगिंग का आपराधिक षड्यंत्र
- IV. रैगिंग के समय अवैध ढंग से एकत्र होना तथा उत्पात करना
- V. रैगिंग के समय जनता को बाधित करना
- VI. रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना
- VII. शरीर को चोट पहुँचाना
- VIII. गलत ढंग से रोकना
- IX. आपराधिक बल प्रयोग
- X. प्रहार करना, मौन सम्बन्धी अपराध अथवा अप्राकृतिक अपराध
- XI. बलात् ग्रहण
- XII. आपराधिक ढंग से बिना अधिकार दूसरे के स्थान में प्रवेश करना
- XIII. सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध
- XIV. आपराधिक धमकी
- XV. मुसीबत में फँसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना
- XVI. उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरुद्ध करने हेतु धमकाना
- XVII. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना
- XVIII. रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध
रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध यह भी उल्लेख किया जाता है।

संस्थाध्यक्ष रैगिंग की घटना की सूचना तुरन्त जिला स्तरीय रैगिंग विरोधी समिति तथा सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी को दें।

यह भी उल्लेख किया जाता कि संस्था इन विनियम के खण्ड 9 के अधीन अपनी जाँच और उपाय पुलिस तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कारवाई की प्रतीक्षा किए बिना प्रारम्भ कर दे और घटना के एक सप्ताह के भीतर औपचारिक कारवाई पूरी कर ली जाए।

8 आयोग और परिषद के कर्तव्य एवं दायित्व

8.1 आयोग रैगिंग से सम्बन्धित घटनाओं की शीघ्र सूचना हेतु निम्नलिखित कार्य करेगा—

क आयोग धन निर्धारित करेगा तथा एक टॉल फ्री रैगिंग विरोधी सहायता लाइन बनाएगा जो 24 घंटे खुली रहेगी जिसका छात्र रैगिंग से सम्बन्धित घटनाओं के निवारण हेतु प्रयोग कर सकते हैं।

ख रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन पर प्राप्त किया गया संदेश तुरन्त संस्थाध्यक्ष, छात्रावास के वार्डन सम्बद्ध विश्वविद्यालय नोडल अधिकारी को प्रसारित किया जाएगा। सम्बद्ध जिले के अधिकारियों यदि आवश्यकता हुई तो जिला अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को दी जाएगी तथा वेबसाइट पर डाल दी जाएगी ताकि मीडिया तथा सामान्य जनता उसका विश्लेषण करे।

ग संस्थाध्यक्ष को एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर मिली सूचना पर त्वरित कार्रवाई इन विनियम के उपखण्ड (बी) के अनुसार करनी होगी।

घ छात्र अथवा किसी भी व्यक्ति को रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन पर संदेश देने हेतु संस्था मोबाइल और फोन के बे-रोक-टोक प्रयोग की छात्रावास तथा परिसर, कक्षाएँ, संगोष्ठी कक्ष पुस्तकालय आदि के अतिरिक्त सभी स्थानों पर प्रयोग की अनुमति के अतिरिक्त सभी स्थानों पर प्रयोग की अनुमति देगा।

ड रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन तथा अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों, संस्थाध्यक्षों संकाय के सदस्यों, रैगिंग विरोधी समिति के सदस्यों तथा रैगिंग विरोधी दल, जिले के अधिकारियों, हॉस्टल के वार्डनों तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों, फोन नम्बर

तथा पते छात्रों को उपलब्ध कराए जाएँ ताकि आकस्मिकी में वे उनका प्रयोग कर सकें।

च आयोग छात्रों तथा उसके माता-पिता/अभिभावक द्वारा दिए गए शपथ पत्रों के आधार पर आंकड़ा रखेगा। यह आंकड़ा रैगिंग की शिकायतों तथा उस पर की गई कार्रवाई के रिकार्ड के रूप में कार्य करेगा।

छ आयोग इस आंकड़े को केन्द्र सरकार द्वारा नामित एवं गैर सरकारी संघटन को उपलब्ध कराएगा। इससे आम जनता में विश्वास बढ़ेगा इन विनियम के अनुपालन न करने की सूचना भी आयोग केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत समितियों को उपलब्ध कराएगा।

8.2 आयोग नियम के अनुसार निम्नलिखित कदम उठाएगा—

क आयोग संस्था हेतु यह आवश्यक करेगा कि वह अपनी विवरणिका में केन्द्र सरकार के निर्देश अथवा राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति के रैगिंग निषेध सम्बन्धी निर्देश और उसके परिणाम समाहित करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो यह माना जाएगा कि वे शिक्षा का स्तर गिर रहे हैं। तथा इसके लिए उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

ख आयोग यह प्रमाणित करेगा कि इन विनियमों के अनुसार छात्रों तथा उनके माता-पिता/अभिभावक से शपथ पत्र संस्था द्वारा प्राप्त किया जा रहा है।

ग आयोग द्वारा संस्था को दी जा रही किसी प्रकार की विशेष अथवा सामान्य किसी प्रकार की आर्थिक सहायता अथवा अनुदान के युटिलाइजेशन प्रमाण पत्र में एक शर्त यह लगाई जाएगी कि संस्था द्वारा रैगिंग निषेध सम्बन्धी विनियम एवं उपायों का अनुपालन किया जा रहा है।

घ रैगिंग की किसी भी घटना का संस्था के बैंक अथवा एन.ए.ए.सी. अथवा किसी अन्य सक्षम एजेंसी द्वारा दी जानेवाले बैंकिंग और ग्रेडिंग पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है।

ङ आयोग उन संस्थाओं को अतिरिक्त अनुदान दे सकता है अथवा अधिनियम खण्ड 12 बी के लिए अर्ह मान सकता है। जहाँ रैगिंग की घटनाएँ नहीं होंगी।

च जहाँ रैगिंग की घटनाएँ नहीं होंगी। आयोग रैगिंग रोकने के लिए एक इंटर

कौंसिल कमेटी बनाएगा जिसमें की भिन्न परिषदों के प्रतिनिधि होंगे। गैर सरकारी एजेंसी आयोग द्वारा रखे जा रहे आंकड़े को देखने के लिए उपखंड (जी) अधिनियम 8.1 के और इस प्रकार के निकाय उच्चतर शिक्षा में रैगिंग विरोधी उपायों को देखने तथा सहयोग देने हेतु तथा समय-समय पर संस्तुतियाँ देने हेतु और प्रत्येक वर्ष के छः महीने में इसकी कम से कम एक बैठक होगी। आयोग एक रैगिंग विरोधी सेल आयोग में बनाएगा। जो रैगिंग से सम्बन्धित सूचनाएँ एकत्र करने तथा उसपर दृष्टि रखने में सचिव की सहायता करेगा। राज्य स्तरीय दृष्टि रखने वाले सेल को ताकि रैगिंग को रोकने के उपायों पर सुचारु रूप से कार्य हो सकें। यह सेल गैर सरकारी संघटन जो रैगिंग रोकने से सम्बन्धित होंगे, को आंकड़े देख रेख में सहायता देगा। इसकी संरचना अधिनियम 8.1 के खण्ड (जी) के अधीन की जाएगी।

9 रैगिंग की घटनाओं पर प्रशासनिक कार्रवाई—

9.1 किसी छात्र को रैगिंग का शोषी पाए जाने पर संस्था द्वारा निम्नलिखित विधि अनुसार दण्ड दिया जाएगा।

क रैगिंग विरोधी समिति उचित दण्ड के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेगी अथवा रैगिंग की घटना के स्वरूप एवं गम्भीरता को देखते हुए रैगिंग विरोधी दल दण्ड हेतु अपनी संस्तुति देगा।

ख रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दल द्वारा निर्धारित किए गए अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए निम्नलिखित में कोई एक अथवा अनेक दण्ड देगी।


- I. कक्षा में उपस्थित होने तथा शैक्षिक अधिकारियों से निलम्बन
- II छात्रवृत्ति/छात्र अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभों को रोकना/वंचित करना
- III किसी टैस्ट/परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वंचित करना
- IV. परीक्षाफल रोकना
- V. किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मीट, खेल, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना।
- VI. छात्रावास से निष्कासित करना

- VII. प्रवेश रद्द करना
- VIII. संस्था से 04 सत्रों तक के लिए लिए निष्कासन करना।
- IX. संस्था से निष्कासित और परिणाम रूवरूप किसी भी संस्था में निश्चित अवधि तक निष्कासन करना। जब रैगिंग करने अथवा रैगिंग करने के लिए भड़काने वाले व्यक्तियों की पहचान न हो सके संस्था सामूहिक दण्ड का आश्रय ले।
- ग रैगिंग विरोधी समिति द्वारा दिए गए दण्ड के विरुद्ध अपील (प्रार्थना) निम्नलिखित से की जाएगी।
- I. किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्था होने पर कुलपति से।
 - II. विश्वविद्यालय का आदेश होने पर कुलाधिपति से
 - III. संसद के अधिनियम के अनुसार निर्मित राष्ट्रीय महत्व की संस्था होने पर उसके चेयनमेन अथवा चांसलर अथवा स्थिति के अनुसार
- 9.2 यदि किसी विश्वविद्यालय के अधीन/सम्बद्ध कोई संस्था (जो उसके विधान में सम्बद्ध अथवा उसके द्वारा मान्यता प्राप्त हो) इनमें से किसी नियम विनियम के अनुपालन में असफल रहती है तथा रैगिंग को प्रभावशाली ढंग से रोकने में असफल रहता है तथा विश्वविद्यालय उस पर निम्नलिखित में से कोई एक अथवा किसी समूहकार दण्ड लगा सकता है—
- I. सम्बद्धता/रेकगजिशन या उसे दिए गए अन्य विशेष अधिकार वापस लेना
 - II. इस प्रकार की संस्था को चल रहे किसी शैक्षिक प्रोग्राम में डिग्री अथवा डिप्लोमा में भाग लेने से रोकना।
 - III. विश्वविद्यालय द्वारा उसे दिए जा रहे अनुदान को वापस लेना, यदि कोई हो।
 - IV. विश्वविद्यालय द्वारा संस्था के माध्यम से दिए जा रहे किसी अनुदान को रोकना
 - V. विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आनेवाला कोई अन्य दण्ड
- 9.3 जहाँ नियुक्ति देने वाले अधिकारी का विचार है कि संस्था को किसी कर्मचारी द्वारा रैगिंग की सूचना देने में ढील बरती गई है। रैगिंग की सूचना देने में त्वरित कार्रवाई नहीं की है। रैगिंग की घटना अथवा घटनाएँ रोकने के लिए नहीं की है। इन विनियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई नहीं की है। रैगिंग की उस अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

यदि इस प्रकार की ढील संस्थाध्यक्ष के स्तर पर हुई है तो संस्थाध्यक्ष की नियुक्ति करनेवाले अधिकारी द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।

- 9.4 कोई भी संस्था जो रैगिंग रोकने इन विनियम के अनुसार कार्रवाई नहीं करेगा अथवा दोषियों को दण्डित नहीं करता तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसके विरुद्ध निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अनेक कार्रवाई करेगा।
- I. अधिनियम के खण्ड 12 बी के अन्तर्गत दिए जानेवाले अनुदान को रोकना।
 - II. दिया जा रहा कोई अनुदान वापस लेना।
 - III. आयोग द्वारा दी जानेवाली सामान्य अथवा किसी विशेष आसिस्टेंस प्रोग्राम हेतु संस्था को अयोग घोषित करना।
 - IV. सामान्य जनता अभ्यर्थियों को समाचार पत्र, मीडिया, आयोग की बैबसाइट आदि द्वारा यह बताना कि संस्था में लघुतम शैक्षिक स्तर उपलब्ध नहीं है।
 - V. इसी प्रकार की अन्य कार्रवाई करना तथा इसी प्रकार से संस्था को तब तक दंडित करना जब तक कि वह रैगिंग रोकने के लक्ष्य को प्राप्त न कर ले

अयोग द्वारा किसी संस्थान के विरुद्ध इस अधिनियम के अनुसार की गई कार्रवाई में सभी समितियाँ सहयोग देंगी।


(डॉ. आर. के. चौहान) 2009
सचिव 6
17

संलग्नक 1

अभ्यर्थी का शपथ प्रमाणपत्र

1. अभ्यर्थी/छात्र का घोषणा पत्र मैं पुत्र/पुत्री.....ने श्री/श्रीमती/सुश्री.....ने रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केंद्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है। मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।
2. मैंने मुख्यरूप से विनियम 3 को पढ़ लिया है समझा लिया है। और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या माने हैं।
3. मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है। अगर मैं किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता हूँ या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता हूँ तो प्रशासन मेरे खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है।
4. मैं निश्चयत पूर्वक यह प्रयत्न करूँगा कि
 - क) मैं किसी की रैगिंग जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है उसमें भाग नहीं लूँगा/लूँगी
 - ख) मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में लूँगा/लूँगी जो कि रैगिंग के धारा 3 विनियम के अंतर्गत आता हो।
4. मैं किसी भी प्रकार की रैगिंग में भाग नहीं लूँगा/लूँगी अथवा किसी भी प्रकार से रैगिंग का प्रचार नहीं करूँगा/करूँगी
5. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/पाया गयी तो मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
6. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और ऐसा पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर.....दिनमहीना.....वर्ष.....

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

शपथ प्रमाणपत्र

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात् पाया गया कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई न कोई तथ्य गलत है। शपथ पत्र में किसी तरह के तथ्य को न ही छिपाया है न ही गलत बयान दिया है।
सत्यापित.....स्थान.....दिनमहीना.....वर्ष.....

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थिति में शपथ पत्र में दिए गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए।

शपथ आयुक्त

संलग्नक -II

माता-पिता/अभिभावक का शपथ प्रमाण-पत्र

1. मैं पिता/माता/अभिभावक
.....ने रैगिंग निषेध के विधि तथा उच्चतम न्यायालय के निर्देश को केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम-2009 को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।
2. मैंने खासतौर से विनियम 3 को पढ़ लिया है समझा लिया है। और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या माने हैं।
3. मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है। अगर मैं किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता हूँ या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता हूँ तो प्रशासन मेरे खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है।
4. मैं निश्चयत पूर्वक यह प्रयत्न करूँगा कि
क) मैं किसी तरह के रैगिंग जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है उसमें भाग नहीं लूँगा/लूँगी
ख) मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में लूँगा/लूँगी जो कि रैगिंग के धारा 3 विनियम के अंतर्गत आता हो।
5. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/पाया गयी तो मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
6. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और ऐसा पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर दिन..... महीना वर्ष.....

हस्ताक्षर

नाम, पता, दूरभाष नं.

शपथ प्रमाण-पत्र

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात् पाया गया कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई न कोई तथ्य गलत है। शपथ पत्र में किसी तरह के तथ्य को न ही छिपाया है न ही गलत बयान दिया है।।
सत्यापित.....स्थान..... दिन महीना..... वर्ष.....

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थिति में शपथ पत्र में दिए गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए।

शपथ आयुक्त

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 5th June 2009

No. N-15/13/14/8/2008-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the director General has fixed the 1st May, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :—

Centre	Areas Comprising the Revenue Villages of Theni District
Uthamapalayam Uthamapalayam Taluk, Theni District.	Revenue Villages of Uthamapalayam (South), Uthamapalayam (North), Theni District, Rayappanpatti, Mallingapuram, Kohilapuram, Kombai (East), Kombai (West) and Hanumanthan Patti of Uthamapalayam Taluk of Theni District.

R. C. SHARMA
Joint Director (P & D)

The 10th June 2009

No. N-15/13/14/6/2008-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :—

Centre	Areas Comprising the following Areas Revenue Villages of Theni District.
Cumbum Uthamapalayam Taluk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cumbum Municipal Limits of Uthamapalayam Taluk. 2. Revenue villages of Kamayakoundantatti, Narayanathevanpatti (South), Narayanathevanpatti (North) Uthamapuram and C. Pudupatti of Uthamapalayam Taluk of Theni District.

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/14/2/2009-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :—

Centre	Areas Comprising the Revenue Villages of
Karaikudi Sub-Urbs Devakottai Taluk, Sivagangai	Perattukottai
District	

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/10/2/2008-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the director General has fixed the 1st May, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Orissa Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Orissa namely :—

"The Revenue villages of Narendrapur, Sibapur, Kurunti, Khadaga Prasad, Tulasidiha & Nimidha Under the Tahsil of Dhenkanal in the District of Dhenkanal in the State of Orissa."

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/14/10/2008-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :—

Centre	Areas Comprising the following Revenue Villages of the District :—
Pudukkottai area in the District	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maravanmadam 2. Kootadunkadu 3. Allikulara 4. Kumaragiri 5. South Silukkanpatti 6. ServaikkaJamadam 7. Perurani 8. Senthilampannai

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

The 12th June 2009

No. N-15/13/14/20/2008-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely :—

"All the areas falling within the limits of Revenue Villages of Veljerla-I, II, III of Farooqnagar Mandal and Papireddyguda Keshampeta Mandal in Mahaboobaagar District in Andhra Pradesh".

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/14/7/2008-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :—

Centre	Areas comprising the Revenue villages of
Chinnamanur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chinnamanur Municipal Limits of Uthamapalayam Taluk. 2. The Revenue Villages of Poolananthapuram, Karkunkatankulam, Chinnavelapuram, Muthalapuram, Markayankottai, Pulikuthi, Kutchanur, Odaipatti in Uthamapalayam Taluk of Theni District.

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
UGC REGULATIONS ON CURBING THE MENACE OF RAGGING IN
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS, 2009.

(under Section 26 (1)(g) of the University Grants Commission Act, 1956)

New Delhi-110002, the 17th June 2009

F.1-16/2007(CPP-II)

PREAMBLE.

In view of the directions of the Hon'ble Supreme Court in the matter of "University of Kerala v/s. Council, Principals, Colleges and others" in SLP no. 24295 of 2006 dated 16.05.2007 and that dated 8.05.2009 in Civil Appeal number 887 of 2009, and in consideration of the determination of the Central Government and the University Grants Commission to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging including any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student, or indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student or asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student, with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student, in all higher education institutions in the country, and thereby, to provide for the healthy development, physically and psychologically, of all students, the University Grants Commission, in consultation with the Councils, brings forth this Regulation.

In exercise of the powers conferred by Clause (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, the University Grants Commission hereby makes the following Regulations, namely;

1. Title, commencement and applicability.-

1.1 These regulations shall be called the "UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009".

1.2 They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

1.3 They shall apply to all the institutions coming within the definition of an University under sub-section (f) of section (2) of the University Grants Commission Act, 1956, and to all institutions deemed to be a university under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, to all other higher educational institutions, or elements of such universities or institutions, including its departments, constituent units and all the premises, whether being academic, residential, playgrounds, canteen, or other such premises of such universities, deemed universities and higher educational institutions, whether located within the campus or outside, and to all means of transportation of students, whether public or private, accessed by students for the pursuit of studies in such universities, deemed universities and higher educational institutions.

2. Objectives.-

To prohibit any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student, or indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student or asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student, with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student; and thereby, to eliminate ragging in all its forms from universities, deemed universities and other higher educational institutions in the country by prohibiting it

under these Regulations, preventing its occurrence and punishing those who indulge in ragging as provided for in these Regulations and the appropriate law in force.

3. What constitutes Ragging.— Ragging constitutes one or more of any of the following acts:

- a. any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student;
- b. indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship, physical or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student;
- c. asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student;
- d. any act by a senior student that prevents, disrupts or disturbs the regular academic activity of any other student or a fresher;
- e. exploiting the services of a fresher or any other student for completing the academic tasks assigned to an individual or a group of students.
- f. any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a fresher or any other student by students;
- g. any act of physical abuse including all variants of it: sexual abuse, homosexual assaults, stripping, forcing obscene and lewd acts, gestures, causing bodily harm or any other danger to health or person;
- h. any act or abuse by spoken words, emails, post, public insults which would also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from actively or passively participating in the discomfiture to fresher or any other student ;
- i. any act that affects the mental health and self-confidence of a fresher or any other student

with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student.

4. Definitions:-

- 1) In these regulations unless the context otherwise requires,-
- a) "Act" means, the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
 - b) "Academic year" means the period from the commencement of admission of students in any course of study in the institution up to the completion of academic requirements for that particular year.
 - c) "Anti-Ragging Helpline" means the Helpline established under clause (a) of Regulation 8.1 of these Regulations.
 - d) "Commission" means the University Grants Commission;
 - e) "Council" means a body so constituted by an Act of Parliament or an Act of any State Legislature for setting, or co-ordinating or maintaining standards in the relevant areas of higher education, such as the All India Council for Technical Education (AICTE), the Bar Council of India (BCI), the Dental Council of India (DCI), the Distance Education Council (DEC), the Indian Council of Agricultural Research (ICAR), the Indian Nursing Council (INC), the Medical Council of India (MCI), the National Council for Teacher Education (NCTE), the Pharmacy Council of India (PCI), etc. and the State Higher Education Councils.
 - f) "District Level Anti-Ragging Committee" means the Committee, headed by the District Magistrate, constituted by the State Government, for the control and elimination of ragging in institutions within the jurisdiction of the district.
 - g) "Head of the institution" means the Vice-Chancellor in case of a university or a deemed to be university, the Principal or the Director or such other designation as the executive head of the institution or the college is referred.
 - h) "Fresher" means a student who has been admitted to an institution and who is undergoing his/her first year of study in such institution.
 - i) "Institution" means a higher educational institution including, but not limited to an university, a deemed to be university, a college, an institute, an institution of national importance set up by an Act of Parliament or a constituent unit of such institution, imparting higher education beyond 12 years of schooling leading to, but not necessarily culminating in, a degree (graduate, postgraduate and/or higher level) and/or to a university diploma.

j) "NAAC" means the National Academic and Accreditation Council established by the Commission under section 12(ccc) of the Act;

k) "State Level Monitoring Cell" means the body constituted by the State Government for the control and elimination of ragging in institutions within the jurisdiction of the State, established under a State Law or on the advice of the Central Government, as the case may be.

(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act or in the General Clauses Act, 1897, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the General Clauses Act, 1897, as the case may be.

5. Measures for prohibition of ragging at the institution level:-

a) No institution or any part of it thereof, including its elements, including, but not limited to, the departments, constituent units, colleges, centres of studies and all its premises, whether academic, residential, playgrounds, or canteen, whether located within the campus or outside, and in all means of transportation of students, whether public or private, accessed by students for the pursuit of studies in such institutions, shall permit or condone any reported incident of ragging in any form; and all institutions shall take all necessary and required measures, including but not limited to the provisions of these Regulations, to achieve the objective of eliminating ragging, within the institution or outside,

b) All institutions shall take action in accordance with these Regulations against those found guilty of ragging and/or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

6 Measures for prevention of ragging at the institution level.-

6.1 An institution shall take the following steps in regard to admission or registration of students; namely,

a) Every public declaration of intent by any institution, in any electronic, audio-visual or print or any other media, for admission of students to any course of study shall expressly provide that ragging is totally prohibited in the institution,

and anyone found guilty of ragging and/or abetting ragging, whether actively or passively, or being a part of a conspiracy to promote ragging, is liable to be punished in accordance with these Regulations as well as under the provisions of any penal law for the time being in force.

- b) The brochure of admission/instruction booklet or the prospectus, whether in print or electronic format, shall prominently print these Regulations in full.

Provided that the institution shall also draw attention to any law concerning ragging and its consequences, as may be applicable to the institution publishing such brochure of admission/instruction booklet or the prospectus.

Provided further that the telephone numbers of the Anti-Ragging Helpline and all the important functionaries in the institution, including but not limited to the Head of the institution, faculty members, members of the Anti-Ragging Committees and Anti-Ragging Squads, District and Sub-Divisional authorities, Wardens of hostels, and other functionaries or authorities where relevant, shall be published in the brochure of admission/instruction booklet or the prospectus.

- c) Where an institution is affiliated to a University and publishes a brochure of admission/instruction booklet or a prospectus, the affiliating university shall ensure that the affiliated institution shall comply with the provisions of clause (a) and clause (b) of Regulation 6.1 of these Regulations.

- d) The application form for admission, enrolment or registration shall contain an affidavit, mandatorily in English and in Hindi and/or in one of the regional languages known to the applicant, as provided in the English language in Annexure I to these Regulations, to be filled up and signed by the applicant to the effect that he/she has read and understood the provisions of these Regulations as well as the provisions of any other law for the time being in force, and is aware of the prohibition of ragging and the punishments prescribed, both under penal laws as well as under these Regulations and also affirm to the effect that he/she has not been expelled and/or debarred by any institution and further aver that he/she would not indulge, actively or passively, in the act or abet the act of ragging and if found guilty of ragging and/or abetting ragging, is liable to be proceeded against under these Regulations or under any penal law or any

other law for the time being in force and such action would include but is not limited to debarment or expulsion of such student.

- e) The application form for admission, enrolment or registration shall contain an affidavit, mandatorily in English and in Hindi and/or in one of the regional languages known to the parents/guardians of the applicant, as provided in the English language in Annexure I to these Regulations, to be filled up and signed by the parents/guardians of the applicant to the effect that he/she has read and understood the provisions of these Regulations as well as the provisions of any other law for the time being in force, and is aware of the prohibition of ragging and the punishments prescribed, both under penal laws as well as under these Regulations and also affirm to the effect that his/her ward has not been expelled and/or debarred by any institution and further aver that his/her ward would not indulge, actively or passively, in the act or abet the act of ragging and if found guilty of ragging and/or abetting ragging, his/her ward is liable to be proceeded against under these Regulations or under any penal law or any other law for the time being in force and such action would include but is not limited to debarment or expulsion of his/her ward.
- f) The application for admission shall be accompanied by a document in the form of, or annexed to, the School Leaving Certificate/Transfer Certificate/Migration Certificate/Character Certificate reporting on the inter-personal/social behavioural pattern of the applicant, to be issued by the school or institution last attended by the applicant, so that the institution can thereafter keep watch on the applicant, if admitted, whose behaviour has been commented in such document.
- g) A student seeking admission to a hostel forming part of the institution, or seeking to reside in any temporary premises not forming part of the institution, including a private commercially managed lodge or hostel, shall have to submit additional affidavits countersigned by his/her parents/guardians in the form prescribed in Annexure I and Annexure II to these Regulations respectively along with his/her application.
- h) Before the commencement of the academic session in any institution, the Head of the Institution shall convene and address a meeting of various functionaries/agencies, such as Hostel Wardens, representatives of students,

- parents/ guardians, faculty, district administration including the police, to discuss the measures to be taken to prevent ragging in the institution and steps to be taken to identify those indulging in or abetting ragging and punish them.
- i) The institution shall, to make the community at large and the students in particular aware of the dehumanizing effect of ragging, and the approach of the institution towards those indulging in ragging, prominently display posters depicting the provisions of penal law applicable to incidents of ragging, and the provisions of these Regulations and also any other law for the time being in force, and the punishments thereof, shall be prominently displayed on Notice Boards of all departments, hostels and other buildings as well as at places, where students normally gather and at places, known to be vulnerable to occurrences of ragging incidents.
 - j) The institution shall request the media to give adequate publicity to the law prohibiting ragging and the negative aspects of ragging and the institution's resolve to ban ragging and punish those found guilty without fear or favour.
 - k) The institution shall identify, properly illuminate and keep a close watch on all locations known to be vulnerable to occurrences of ragging incidents.
 - l) The institution shall tighten security in its premises, especially at vulnerable places and intense policing by Anti-Ragging Squad, referred to in these Regulations and volunteers, if any, shall be resorted to at such points at odd hours during the first few months of the academic session.
 - m) The institution shall utilize the vacation period before the start of the new academic year to launch a publicity campaign against ragging through posters, leaflets and such other means, as may be desirable or required, to promote the objectives of these Regulations.
 - n) The faculties/departments/units of the institution shall have induction arrangements, including those which anticipate, identify and plan to meet any special needs of any specific section of students, in place well in advance of the beginning of the academic year with an aim to promote the objectives of this Regulation.
 - o) Every institution shall engage or seek the assistance of professional counsellors before the commencement of the academic session, to be available

when required by the institution, for the purposes of offering counselling to freshers and to other students after the commencement of the academic year.

- p) The head of the institution shall provide information to the local police and local authorities, the details of every privately commercially managed hostels or lodges used for residential purposes by students enrolled in the institution and the head of the institution shall also ensure that the Anti-Ragging Squad shall ensure vigil in such locations to prevent the occurrence of ragging therein.

6.2 An institution shall, on admission or enrolment or registration of students, take the following steps, namely;

- a) Every fresh student admitted to the institution shall be given a printed leaflet detailing to whom he/she has to turn to for help and guidance for various purposes including addresses and telephone numbers, so as to enable the student to contact the concerned person at any time, if and when required, of the Anti-Ragging Helpline referred to in these Regulations, Wardens, Head of the institution, all members of the anti-ragging squads and committees, relevant district and police authorities.
- b) The institution, through the leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall explain to the freshers, the arrangements made for their induction and orientation which promote efficient and effective means of integrating them fully as students with those already admitted to the institution in earlier years.
- c) The leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall inform the freshers about their rights as bona fide students of the institution and clearly instructing them that they should desist from doing anything, with or against their will, even if ordered to by the seniors students, and that any attempt of ragging shall be promptly reported to the Anti-ragging Squad or to the Warden or to the Head of the institution, as the case may be.
- d) The leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall contain a calendar of events and activities laid down by the institution to facilitate and complement familiarization of freshers with the academic environment of the institution.

- e) The institution shall, on the arrival of senior students after the first week or after the second week, as the case may be, schedule orientation programmes as follows, namely; (i) joint sensitization programme and counselling of both freshers and senior students by a professional counsellor, referred to in clause (o) of Regulation 6.1 of these Regulations; (ii) joint orientation programme of freshers and seniors to be addressed by the Head of the institution and the anti-ragging committee; (iii) organization on a large scale of cultural, sports and other activities to provide a platform for the freshers and seniors to interact in the presence of faculty members; (iv) in the hostel, the warden should address all students; and may request two junior colleagues from the college faculty to assist the warden by becoming resident tutors for a temporary duration. (v) as far as possible faculty members should dine with the hostel residents in their respective hostels to instil a feeling of confidence among the freshers.
- f) The institution shall set up appropriate committees, including the course-in-charge, student advisor, Wardens and some senior students as its members, to actively monitor, promote and regulate healthy interaction between the freshers, junior students and senior students.
- g) Freshers or any other student(s), whether being victims, or witnesses, in any incident of ragging, shall be encouraged to report such occurrence, and the identity of such informants shall be protected and shall not be subject to any adverse consequence only for the reason for having reported such incidents.
- h) Each batch of freshers, on arrival at the institution, shall be divided into small groups and each such group shall be assigned to a member of the faculty, who shall interact individually with each member of the group every day for ascertaining the problems or difficulties, if any, faced by the fresher in the institution and shall extend necessary help to the fresher in overcoming the same.
- i) It shall be the responsibility of the member of the faculty assigned to the group of freshers, to coordinate with the Wardens of the hostels and to make surprise visits to the rooms in such hostels, where a member or members of the group are lodged; and such member of faculty shall maintain a diary of his/her interaction with the freshers under his/her charge.

- 39
- j) Freshers shall be lodged, as far as may be, in a separate hostel block, and where such facilities are not available, the institution shall ensure that access of seniors to accommodation allotted to freshers is strictly monitored by wardens, security guards and other staff of the institution.
 - k) A round the clock vigil against ragging in the hostel premises, in order to prevent ragging in the hostels after the classes are over, shall be ensured by the institution.
 - l) It shall be the responsibility of the parents/guardians of freshers to promptly bring any instance of ragging to the notice of the Head of the Institution.
 - m) Every student studying in the institution and his/her parents/guardians shall provide the specific affidavits required under clauses (d), (e) and (g) of Regulation 6.1 of these Regulations at the time of admission or registration, as the case may be, during each academic year.
 - n) Every institution shall obtain the affidavit from every student as referred to above in clause (m) of Regulation 6.2 and maintain a proper record of the same and to ensure its safe upkeep thereof, including maintaining the copies of the affidavit in an electronic form, to be accessed easily when required either by the Commission or any of the Councils or by the institution or by the affiliating University or by any other person or organisation authorised to do so.
 - o) Every student at the time of his/her registration shall inform the institution about his/her place of residence while pursuing the course of study, and in case the student has not decided his/her place of residence or intends to change the same, the details of his place of residence shall be provided immediately on deciding the same; and specifically in regard to a private commercially managed lodge or hostel where he/she has taken up residence.
 - p) The Head of the institution shall, on the basis of the information provided by the student under clause (c) of Regulation 6.2, apportion sectors to be assigned to members of the faculty, so that such member of faculty can maintain vigil and report any incident of ragging outside the campus or en route while commuting to the institution using any means of transportation of students, whether public or private.

q) The Head of the institution shall, at the end of each academic year, send a letter to the parents/guardians of the students who are completing their first year in the institution, informing them about these Regulations and any law for the time being in force prohibiting ragging and the punishments thereof as well as punishments prescribed under the penal laws, and appealing to them to impress upon their wards to desist from indulging in ragging on their return to the institution at the beginning of the academic session next.

6.3 Every institution shall constitute the following bodies; namely,

- a) Every institution shall constitute a Committee to be known as the Anti-Ragging Committee to be nominated and headed by the Head of the institution, and consisting of representatives of civil and police administration, local media, Non Government Organizations involved in youth activities, representatives of faculty members, representatives of parents, representatives of students belonging to the freshers' category as well as senior students, non-teaching staff; and shall have a diverse mix of membership in terms of levels as well as gender.
- b) It shall be the duty of the Anti-Ragging Committee to ensure compliance with the provisions of these Regulations as well as the provisions of any law for the time being in force concerning ragging; and also to monitor and oversee the performance of the Anti-Ragging Squad in prevention of ragging in the institution.
- c) Every institution shall also constitute a smaller body to be known as the Anti-Ragging Squad to be nominated by the Head of the Institution with such representation as may be considered necessary for maintaining vigil, oversight and patrolling functions and shall remain mobile, alert and active at all times.

Provided that the Anti-Ragging Squad shall have representation of various members of the campus community and shall have no outside representation.

- d) It shall be the duty of the Anti-Ragging Squad to be called upon to make surprise raids on hostels, and other places vulnerable to incidents of, and having the potential of, ragging and shall be empowered to inspect such places.
- e) It shall also be the duty of the Anti-Ragging Squad to conduct an on-the-spot enquiry into any incident of ragging referred to it by the Head of the institution

or any member of the faculty or any member of the staff or any student or any parent or guardian or any employee of a service provider or by any other person, as the case may be; and the enquiry report along with recommendations shall be submitted to the Anti-Ragging Committee for action under clause (a) of Regulation 9.1.

Provided that the Anti-Ragging Squad shall conduct such enquiry observing a fair and transparent procedure and the principles of natural justice and after giving adequate opportunity to the student or students accused of ragging and other witnesses to place before it the facts, documents and views concerning the incident of ragging, and considering such other relevant information as may be required.

- f) Every institution shall, at the end of each academic year, in order to promote the objectives of these Regulations, constitute a Mentoring Cell consisting of students volunteering to be Mentors for freshers, in the succeeding academic year; and there shall be as many levels or tiers of Mentors as the number of batches in the institution, at the rate of one Mentor for six freshers and one Mentor of a higher level for six Mentors of the lower level.
- g) Every University shall constitute a body to be known as Monitoring Cell on Ragging, which shall coordinate with the affiliated colleges and institutions under the domain of the University to achieve the objectives of these Regulations; and the Monitoring Cell shall call for reports from the Heads of institutions in regard to the activities of the Anti-Ragging Committees, Anti - Ragging Squads, and the Mentoring Cells at the institutions, and it shall also keep itself abreast of the decisions of the District level Anti-Ragging Committee headed by the District Magistrate.
- h) The Monitoring Cell shall also review the efforts made by institutions to publicize anti-ragging measures, soliciting of affidavits from parents/guardians and from students, each academic year, to abstain from ragging activities or willingness to be penalized for violations; and shall function as the prime mover for initiating action, on the part of the appropriate authorities of the university for amending the Statutes or Ordinances or Bye-laws to facilitate the implementation of anti-ragging measures at the level of the institution.

- 6.4 Every institution shall take the following other measures, namely;
- a) Each hostel or a place where groups of students reside, forming part of the institution, shall have a full-time Warden, to be appointed by the institution as per the eligibility criteria laid down for the post reflecting both the command and control aspects of maintaining discipline and preventing incidents of ragging within the hostel, as well as the softer skills of counselling and communicating with the youth outside the class-room situation; and who shall reside within the hostel, or at the very least, in the close vicinity thereof.
 - b) The Warden shall be accessible at all hours and be available on telephone and other modes of communication, and for the purpose the Warden shall be provided with a mobile phone by the institution, the number of which shall be publicised among all students residing in the hostel.
 - c) The institution shall review and suitably enhance the powers of Wardens; and the security personnel posted in hostels shall be under the direct control of the Warden and their performance shall be assessed by them.
 - d) The professional counsellors referred to under clause (o) of Regulation 6.1 of these Regulations shall, at the time of admission, counsel freshers and/or any other student(s) desiring counselling, in order to prepare them for the life ahead, particularly in regard to the life in hostels and to the extent possible, also involve parents and teachers in the counselling sessions.
 - e) The institution shall undertake measures for extensive publicity against ragging by means of audio-visual aids, counselling sessions, workshops, painting and design competitions among students and such other measures, as it may deem fit.
 - f) In order to enable a student or any person to communicate with the Anti-Ragging Helpline, every institution shall permit unrestricted access to mobile phones and public phones in hostels and campuses, other than in class-rooms, seminar halls, library, and in such other places that the institution may deem it necessary to restrict the use of phones.
 - g) The faculty of the institution and its non-teaching staff, which includes but is not limited to the administrative staff, contract employees, security guards

and employees of service providers providing services within the institution, shall be sensitized towards the ills of ragging, its prevention and the consequences thereof.

h) The institution shall obtain an undertaking from every employee of the institution including all teaching and non-teaching members of staff, contract labour employed in the premises either for running canteen or as watch and ward staff or for cleaning or maintenance of the buildings/lawns and employees of service providers providing services within the institution, that he/she would report promptly any case of ragging which comes to his/her notice.

i) The institution shall make a provision in the service rules of its employees for issuing certificates of appreciation to such members of the staff who report incidents of ragging, which will form part of their service record.

j) The institution shall give necessary instructions to the employees of the canteens and messing, whether that of the institution or that of a service provider providing this service, or their employers, as the case may be, to keep a strict vigil in the area of their work and to report the incidents of ragging to the Head of the institution or members of the Anti-Ragging Squad or members of the Anti-Ragging Committee or the Wardens, as may be required.

k) All Universities awarding a degree in education at any level, shall be required to ensure that institutions imparting instruction in such courses or conducting training programme for teachers include inputs relating to anti-ragging and the appreciation of the relevant human rights, as well as inputs on topics regarding sensitization against corporal punishments and checking of bullying amongst students, so that every teacher is equipped to handle at least the rudiments of the counselling approach.

l) Discreet random surveys shall be conducted amongst the freshers every fortnight during the first three months of the academic year to verify and cross-check whether the institution is indeed free of ragging or not and for the purpose the institution may design its own methodology of conducting such surveys.

m) The institution shall cause to have an entry, apart from those relating to general conduct and behaviour, made in the Migration/Transfer Certificate issued to the student while leaving the institution, as to whether the student has been

punished for committing or abetting an act of ragging, as also whether the student has displayed persistent violent or aggressive behaviour or any inclination to harm others, during his course of study in the institution.

n) Notwithstanding anything contained in these Regulations with regard to obligations and responsibilities pertaining to the authorities or members of bodies prescribed above, it shall be the general collective responsibility of all levels and sections of authorities or functionaries including members of the faculty and employees of the institution, whether regular or temporary, and employees of service providers providing service within the institution, to prevent or to act promptly against the occurrence of ragging or any incident of ragging which comes to their notice.

o) The Heads of institutions affiliated to a University or a constituent of the University, as the case may be, shall, during the first three months of an academic year, submit a weekly report on the status of compliance with Anti-Ragging measures under these Regulations, and a monthly report on such status thereafter, to the Vice-Chancellor of the University to which the institution is affiliated to or recognized by.

p) The Vice Chancellor of each University, shall submit fortnightly reports of the University, including those of the Monitoring Cell on Ragging in case of an affiliating university, to the State Level Monitoring Cell.

7. Action to be taken by the Head of the institution.- On receipt of the recommendation of the Anti Ragging Squad or on receipt of any information concerning any reported incident of ragging, the Head of institution shall immediately determine if a case under the penal laws is made out and if so, either on his own or through a member of the Anti-Ragging Committee authorised by him in this behalf, proceed to file a First Information Report (FIR), within twenty four hours of receipt of such information or recommendation, with the police and local authorities, under the appropriate penal provisions relating to one or more of the following, namely;

- i. Abetment to ragging;
- ii. Criminal conspiracy to rag;
- iii. Unlawful assembly and rioting while ragging;

- iv. Public nuisance created during ragging;
- v. Violation of decency and morals through ragging;
- vi. Injury to body, causing hurt or grievous hurt;
- vii. Wrongful restraint;
- viii. Wrongful confinement;
- ix. Use of criminal force;
- x. Assault as well as sexual offences or unnatural offences;
- xi. Extortion;
- xii. Criminal trespass;
- xiii. Offences against property;
- xiv. Criminal intimidation;
- xv. Attempts to commit any or all of the above mentioned offences against the victim(s);
- xvi. Threat to commit any or all of the above mentioned offences against the victim(s);
- xvii. Physical or psychological humiliation;
- xviii. All other offences following from the definition of "Ragging".

Provided that the Head of the institution shall forthwith report the occurrence of the incident of ragging to the District Level Anti-Ragging Committee and the Nodal officer of the affiliating University, if the Institution is an affiliated institution.

Provided further that the institution shall also continue with its own enquiry initiated under clause 9 of these Regulations and other measures without waiting for action on the part of the police/local authorities and such remedial action shall be initiated and completed immediately and in no case later than a period of seven days of the reported occurrence of the incident of ragging.

8. Duties and Responsibilities of the Commission and the Councils.-

8.1 The Commission shall, with regard to providing facilitating communication of information regarding incidents of ragging in any institution, take the following steps, namely;

- a) The Commission shall establish, fund and operate, a toll-free Anti-Ragging Helpline, operational round the clock, which could be accessed by students in distress owing to ragging related incidents.
- b) Any distress message received at the Anti-Ragging Helpline shall be simultaneously relayed to the Head of the Institution, the Warden of the Hostels, the Nodal Officer of the affiliating University, if the incident reported has taken place in an institution affiliated to a University, the concerned District authorities and if so required, the District Magistrate, and the Superintendent of Police, and shall also be web enabled so as to be in the public domain simultaneously for the media and citizens to access it.
- c) The Head of the Institution shall be obliged to act immediately in response to the information received from the Anti-Ragging Helpline as at sub-clause (b) of this clause.
- d) The telephone numbers of the Anti-Ragging Helpline and all the important functionaries in every institution, Heads of institutions, faculty members, members of the anti-ragging committees and anti ragging squads, district and sub-divisional authorities and state authorities, Wardens of hostels, and other functionaries or authorities where relevant, shall be widely disseminated for access or to seek help in emergencies.
- e) The Commission shall maintain an appropriate data base to be created out of affidavits, affirmed by each student and his/her parents/guardians and stored electronically by the institution, either on its or through an agency to be designated by it; and such database shall also function as a record of ragging complaints received, and the status of the action taken thereon.
- f) The Commission shall make available the database to a non-governmental agency to be nominated by the Central Government, to build confidence in the public and also to provide information of non compliance with these Regulations to the Councils and to such bodies as may be authorised by the Commission or by the Central Government.

8.2 The Commission shall take the following regulatory steps, namely;

- a) The Commission shall make it mandatory for the institutions to incorporate in their prospectus, the directions of the Central Government or the State Level Monitoring Committee with regard to prohibition and consequences of ragging, and that non-compliance with these Regulations and directions so provided, shall be considered as lowering of academic standards by the institution, therefore making it liable for appropriate action.
- b) The Commission shall verify that the institutions strictly comply with the requirement of getting the affidavits from the students and their parents/guardians as envisaged under these Regulations.
- c) The Commission shall include a specific condition in the Utilization Certificate, in respect of any financial assistance or grants-in-aid to any institution under any of the general or special schemes of the Commission, that the institution has complied with the anti-ragging measures.
- d) Any incident of ragging in an institution shall adversely affect its accreditation, ranking or grading by NAAC or by any other authorised accreditation agencies while assessing the institution for accreditation, ranking or grading purposes.
- e) The Commission may accord priority in financial grants-in-aid to those institutions, otherwise eligible to receive grants under section 12B of the Act, which report a blemishless record in terms of there being no reported incident of ragging.
- f) The Commission shall constitute an Inter-Council Committee, consisting of representatives of the various Councils, the Non-Governmental agency responsible for monitoring the database maintained by the Commission under clause (g) of Regulation 8.1 and such other bodies in higher education, to coordinate and monitor the anti-ragging measures in institutions across the country and to make recommendations from time to time; and shall meet at least once in six months each year.
- g) The Commission shall institute an Anti-Ragging Cell within the Commission as an institutional mechanism to provide secretarial support for collection of information and monitoring, and to coordinate with the State Level Monitoring Cell and University level Committees for effective implementation of anti-ragging measures, and the Cell shall also coordinate with the Non-Governmental agency

responsible for monitoring the database maintained by the Commission appointed under clause (g) of Regulation 8.1.

9. Administrative action in the event of ragging.-

9.1 The institution shall punish a student found guilty of ragging after following the procedure and in the manner prescribed hereinunder:

- a) The Anti-Ragging Committee of the institution shall take an appropriate decision, in regard to punishment or otherwise, depending on the facts of each incident of ragging and nature and gravity of the incident of ragging established in the recommendations of the Anti-Ragging Squad.
- b) The Anti-Ragging Committee may, depending on the nature and gravity of the guilt established by the Anti-Ragging Squad, award, to those found guilty, one or more of the following punishments, namely;
 - i. Suspension from attending classes and academic privileges.
 - ii. Withholding/ withdrawing scholarship/ fellowship and other benefits.
 - iii. Debarring from appearing in any test/ examination or other evaluation process.
 - iv. Withholding results.
 - v. Debarring from representing the institution in any regional, national or international meet, tournament, youth festival, etc.
 - vi. Suspension/ expulsion from the hostel.
 - vii. Cancellation of admission.
 - viii. Rustication from the institution for period ranging from one to four semesters.
 - ix. Expulsion from the institution and consequent debarring from admission to any other institution for a specified period.

Provided that where the persons committing or abetting the act of ragging are not identified, the institution shall resort to collective punishment.

- c) An appeal against the order of punishment by the Anti-Ragging Committee shall lie,
 - i. in case of an order of an institution, affiliated to or constituent part, of a University, to the Vice-Chancellor of the University;

- ii. In case of an order of a University, to its Chancellor.
- iii. In case of an institution of national importance created by an Act of Parliament, to the Chairman or Chancellor of the institution, as the case may be.

9.2 Where an institution, being constituent of, affiliated to or recognized by a University, fails to comply with any of the provisions of these Regulations or fails to curb ragging effectively, such University may take any one or more of the following actions, namely;

- i. Withdrawal of affiliation/recognition or other privileges conferred.
- ii. Prohibiting such institution from presenting any student or students then undergoing any programme of study therein for the award of any degree/diploma of the University.

Provided that where an institution is prohibited from presenting its student or students, the Commission shall make suitable arrangements for the other students so as to ensure that such students are able to pursue their academic studies.

- iii. Withholding grants allocated to it by the university, if any
- iv. Withholding any grants channelised through the university to the institution.
- v. Any other appropriate penalty within the powers of the university.

9.3 Where in the opinion of the appointing authority, a lapse is attributable to any member of the faculty or staff of the institution, in the matter of reporting or taking prompt action to prevent an incident of ragging or who display an apathetic or insensitive attitude towards complaints of ragging, or who fail to take timely steps, whether required under these Regulations or otherwise, to prevent an incident or incidents of ragging, then such authority shall initiate departmental disciplinary action, in accordance with the prescribed procedure of the institution, against such member of the faculty or staff.

Provided that where such lapse is attributable to the Head of the institution, the authority designated to appoint such Head shall take such departmental disciplinary

action; and such action shall be without prejudice to any action that may be taken under the penal laws for abetment of ragging for failure to take timely steps in the prevention of ragging or punishing any student found guilty of ragging.

9.4 The Commission shall, in respect of any institution that fails to take adequate steps to prevent ragging or fails to act in accordance with these Regulations or fails to punish perpetrators or incidents of ragging suitably, take one or more of the following measures, namely;

- i. Withdrawal of declaration of fitness to receive grants under section 12B of the Act.
- ii. Withholding any grant allocated.
- iii. Declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programmes of the Commission.
- iv. Informing the general public, including potential candidates for admission, through a notice displayed prominently in the newspapers or other suitable media and posted on the website of the Commission, declaring that the institution does not possess the minimum academic standards.
- v. Taking such other action within its powers as it may deem fit and impose such other penalties as may be provided in the Act for such duration of time as the institution complies with the provisions of these Regulations.

Provided that the action taken under this clause by the Commission against any institution shall be shared with all Councils.


(Dr. R.K. Chauhan)
Secretary

ANNEXURE I
AFFIDAVIT BY THE STUDENT

I, _____ (*full name of student with admission/registration/enrolment number*)
s/o d/o Mr./Mrs./Ms. _____, having
been admitted to _____ (*name of the institution*), have
received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher
Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") carefully read and
fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to
what constitutes ragging.

3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and
am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against
me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part
of a conspiracy to promote ragging.

4) I hereby solemnly aver and undertake that

a) I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as
ragging under clause 3 of the Regulations.

b) I will not participate in or abet or propagate through any act of
commission or omission that may be constituted as ragging under clause
3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment
according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action
that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in
force.

6) I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in
any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part
of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is
found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this ___ day of _____ month of _____ year.

Signature of deponent

Name:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no
part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at (place) on this the (day) of (month), (year).

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the (day) of (month),
(year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

ANNEXURE II
AFFIDAVIT BY PARENT/GUARDIAN

I, Mr./Mrs./Ms. _____ (*full name of parent/guardian*) father/mother/guardian of _____ (*full name of student with admission/registration/enrolment number*) _____, having been admitted to _____ (*name of the institution*), have received a copy of the UGC

Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations"), carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.

3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4) I hereby solemnly aver and undertake that

a) My ward will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force.

6) I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, the admission of my ward is liable to be cancelled.

Declared this ____ day of _____ month of _____ year.

Signature of deponent

Name:

Address:

Telephone/ Mobile No.:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at (place) on this the (day) of (month), (year).

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the (day) of (month), (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042023-245095
CG-DL-E-11042023-245095

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233]
No. 233]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 11, 2023/चैत्र 21, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 11, 2023/CHAITRA 21, 1945

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023

F.1-13/2022(CPP-II).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2019 के अधिक्रमण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, नामतः:-

1. संक्षिप्त नाम, विनियोग और प्रारंभ:

- (क) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 कहा जाएगा।
- (ख) वे ऐसे सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों पर लागू होंगे, जिन्हें किसी केंद्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के तहत स्थापित या निगमित गया हो और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) के तहत मान्यता-प्राप्त सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों तथा ऐसे सभी सम विश्वविद्यालय संस्थानों पर लागू होंगे जिन्हें तत्संबंध की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो।

(ग) वे शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. उद्देश्य:

किसी संस्थान में पहले से ही नामांकित छात्रों और साथ ही ऐसे संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक छात्रोंकी कतिपय शिकायतों के निवारण के लिए अवसर प्रदान करना और उसके लिए एक तंत्र स्थापित करना।

3. परिभाषा:

(1) जब तक कि इन विनियमों केसंदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (क) "अधिनियम" का अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) से है;
- (ख) "पीडित छात्र" से अभिप्राय किसी ऐसे छात्र से है जिसे इन विनियमों के तहत परिभाषित शिकायतों के संबंध में किसी मामले अथवा तत्संबंधी किसी मामले में कोई शिकायत हो।
- (ग) "महाविद्यालय" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 12ए की उपधारा (1) के खंड (ख) में इस प्रकार से परिभाषित किसी संस्थान से है।
- (घ) "आयोग" से अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है।
- (ङ) "घोषित प्रवेश नीति" का अभिप्राय संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए संस्थान की विवरणिका में प्रकाशित की गई किसी ऐसी नीति से है, जिसमें उसके अंतर्गत आने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल हैं।
- (च) "शिकायत" का अभिप्राय, और इसमें निम्नवत् के संबंध में किसी पीडितछात्र द्वारा की गई शिकायत (शिकायतें) शामिल हैं, नामतः:
 - i. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के अनुरूप निर्धारित की गई योग्यता के विपरीत प्रवेश दिया जाना;
 - ii. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के तहत प्रक्रिया में अनियमितताएं;
 - iii. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के अनुरूप प्रवेश देने से इंकार किया जाना;
 - iv. इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप, संस्थान द्वारा विवरणिका का प्रकाशन न किया जाना;
 - v. संस्थान द्वारा विवरणिका में ऐसी कोई जानकारी देना जोकि झूठी या भ्रामक होऔर तथ्यों पर आधारित न हो;
 - vi. किसी छात्र द्वारा ऐसे संस्थान में प्रवेश लेने के प्रयोजन से जमा किए गए किसी दस्तावेज जोकि उपाधि, डिप्लोमा या किसी अन्य पुरस्कार के रूप में हो,उसको अपने पास रख लेना या वापस करने से इंकार करना ताकि ऐसे किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम के संबंध में छात्र को किसी शुल्क अथवा शुल्कों का भुगतान करने हेतु तैयार किया जा सके अथवा मजबूर किया जा सके जिसमें छात्र अध्ययन नहीं करना चाहता हो;
 - vii. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति में निर्धारित राशि से अधिक धनराशि की मांग करना।
 - viii. छात्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रवेश में सीटों के आरक्षण के संबंध में वर्तमान में लागू किसी कानून का संस्थान द्वारा उल्लंघन किया जाना;

- ix. ऐसे किसी संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के तहत अथवा आयोग द्वारा विहित किन्हीं शर्तों, यदि कोई हो तो, के तहत किसी भी छात्र हेतु ग्राह्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता का भुगतान नहीं किया जाना अथवा विलम्ब से भुगतान किया जाना;
 - x. संस्थान के शैक्षणिक कैलेंडर में अथवा आयोग द्वारा विहित ऐसे किसी कैलेंडर में विनिर्दिष्ट अनुसूची से इतर परीक्षाओं के आयोजन में अथवा परीक्षा के परिणामों की घोषणा में विलम्ब करना;
 - xi. विवरणिका में यथा उल्लिखित अथवा संस्थान द्वारा लागू किसी कानून के किसी उपबंध के तहत यथा अपेक्षित छात्रों की सुविधा प्रदान करने में संस्थान द्वारा विफल रहना;
 - xii. छात्रों के मूल्यांकन के लिए संस्थान द्वारा अपनाई गई गैर-पारदर्शी अथवा अनुचित पद्धतियां;
 - xiii. ऐसे किसी छात्र को शुल्क के प्रतिदाय में विलंब करना, अथवा इंकार करना जो कि विवरणिका में उल्लिखित समय के भीतर, बशर्ते यह समय-समय पर आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन हो, नामांकन वापस लेता है;
 - xiv. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक अथवा दिव्यांग श्रेणियों के छात्रों से कथित भेदभाव की शिकायत;
 - xv. प्रवेश दिए जाने के समय जैसा भरोसा दिलाया गया था अथवा प्रदान किया जाना अपेक्षित था के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं किया जाना;
 - xvi. छात्र के उत्पीड़न के अन्य मामलों के अलावा जिन पर वर्तमान में लागू किसी कानून के दंडात्मक उपबंधों के तहत कार्रवाई की जानी हो, छात्र का उत्पीड़न किया जाना अथवा उसे निशाना बनाया जाना।
 - xvii. संस्थान के कानूनों, अध्यादेशों, नियमों, विनियमों, या दिशा-निर्देशों के विपरीत कोई कार्रवाई किया जाना अथवा शुरू किया जाना; तथा
 - xviii. आयोग और/अथवा संबंधित नियामक निकाय द्वारा बनाए गए/जारी किए गए नियमों और/या दिशा-निर्देशों के विपरीत कोई भी कार्रवाई किया जाना अथवा शुरू किया जाना।
- (छ) "संस्थान" से तात्पर्य विश्वविद्यालय से है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (एफ) में परिभाषित है, एक संस्थान जिसे अधिनियम 3 के तहत विश्वविद्यालय माना गया है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12ए (1) (बी) में परिभाषित एक महाविद्यालय से है।
- (ज) "लोकपाल" का अभिप्राय इन विनियमों के तहत नियुक्त लोकपाल से है।
- (झ) "विवरणिका" का अभिप्राय और इसमें ऐसा कोई प्रकाशन शामिल है, चाहे वह मुद्रित स्वरूप में अथवा अन्यथा हो, जिसे जनसाधारण (जिसमें ऐसे संस्थान में प्रवेश पाने के इच्छुकों सहित) को एक संस्था से संबंधित निष्पक्ष और पारदर्शी जानकारी प्रदान करने के लिए ऐसे संस्थान अथवा किसी प्राधिकरण अथवा ऐसे संस्थान द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया हो;
- (ञ) "छात्र" से अभिप्राय किसी ऐसे संस्थान जिसमें यह विनियम लागू होते हैं, में किसी भी माध्यम से अर्थात् औपचारिक/मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल)/ऑनलाइन से नामांकित किसी व्यक्ति अथवा नामांकित होने के लिए प्रवेश प्राप्ति के इच्छुक से हैं;

- (ट) "छात्र शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी)" का अभिप्राय एक संस्थान के स्तर पर इन विनियमों के तहत गठित एक समिति से है; तथा
- (ठ) "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 2 की खंड (च) में यथा परिभाषित किसी विश्वविद्यालय से है अथवा जहां संदर्भ के अनुसार, तत्संबंध की धारा 3 के तहत इस प्रकार घोषित कोई सम विश्वविद्यालय संस्थान से है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में उनके लिए निर्धारित किए गए हैं।

4. विवरणिका का अनिवार्य प्रकाशन, इसकी विषयवस्तु तथा मूल्य निर्धारण

- (1) प्रत्येक संस्थान, अपने पाठ्यक्रम या अध्ययन के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश आरंभ करने की तिथि से कम से कम साठ दिन की समाप्ति से पूर्व अपनी वेबसाइट पर एक विवरणिका प्रकाशित और/अथवा अपलोड करेगा, जिसमें इस तरह के संस्थान में प्रवेश लेने के इच्छुक व्यक्तियों और आम जनता की जानकारी के लिए निम्नवत् जानकारी अंतर्विष्ट होगी, यथा;
- (क) प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन के कार्यक्रम के लिए, शिक्षण के घंटों, व्यावहारिक सत्रों और अन्य कार्य के साथ-साथ अध्ययन के कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों की सूची सहित उपयुक्त सांविधिक प्राधिकरण अथवा संस्थान, जैसा भी मामला हो, द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम की व्यापक रूपरेखा;
- (ख) जिस शिक्षा वर्ष हेतु प्रवेश दिए जाने का प्रस्ताव हो, उसके प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन के कार्यक्रम के संबंध में उपयुक्त सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सीटों की संख्या;
- (ग) संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विशेष पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन कार्यक्रम में छात्र के रूप में प्रवेश के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा सहित शैक्षिक योग्यता और पात्रता की शर्तें;
- (घ) इस प्रकार के प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया, जिसमें प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के लिए परीक्षा या इम्तहान के विवरण के संबंध में सभी संगत जानकारी और प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क की राशि शामिल है;
- (ङ) किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम में अध्ययन करने के लिए ऐसे संस्थान में भर्ती किए गए छात्रों द्वारा देय शुल्क, जमा राशियों और अन्य प्रभारों के प्रत्येक घटक और ऐसे भुगतानों की अन्य निबंधन और शर्तें;
- (च) शास्ति लगाए जाने और संग्रहण किए जाने हेतु नियम/विनियम, विनिर्दिष्ट शीर्ष अथवा श्रेणियां, लगाए जाने वाली शास्ति की न्यूनतम और अधिकतम राशि;
- (छ) ऐसे संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों द्वारा यदि पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम के पूरा होने से पहले अथवा के बाद दाखिला छोड़ दिया जाता है तो छात्रोंको प्रतिदाय किए जाने वाले शिक्षण शुल्क और अन्य प्रभारों का प्रतिशत तथा समय सीमा जिसके भीतर तथा पद्धति जिससे छात्रोंको ऐसा प्रतिदाय किया जाएगा;
- (ज) उनकी शैक्षिक योग्यता शिक्षण संकाय का विवरण, उनकी नियुक्ति का स्वरूप (नियमित/अभ्यागत/अतिथि) और उसके प्रत्येक सदस्य के शिक्षण अनुभव के साथ;
- (झ) भौतिक और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे और छात्रावास तथा इसके शुल्क, पुस्तकालय, चिकित्सालय अथवा उद्योग, जहां छात्रोंको व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना हो, सहित अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी और विशेषरूप से छात्रों द्वारा संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने पर प्राप्त होने वाली सुविधाओं का ब्यौरा अंतर्विष्ट हो;

- (ज) संस्थान के परिसर के भीतर अथवा बाहर छात्रों द्वारा अनुशासन बनाए रखने के संबंध में सभी संगत निदेश और विशेषरूप से किसी छात्र अथवा छात्रों की रैगिंग निषिद्ध करने संबंधी ऐसे अनुशासन को बनाए रखने और उनका उल्लंघन किए जाने के परिणामों और संगत सांविधिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में तैयार किए गए किसी विनियम के उपबंधों का उल्लंघन किए जाने के परिणामों का ब्योरा अंतर्विष्ट होगा; तथा
- (ट) आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य जानकारी:
बशर्ते प्रत्येक संस्थान इस विनियम के खंड (क) से (ट) में उल्लिखित जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित/अपलोड करेगा और विभिन्न समाचार-पत्रों और अन्य मीडिया के माध्यम से प्रमुखता से प्रदर्शित करते हुए विज्ञापनों के माध्यम से इच्छुक छात्रों और आम जनता का ध्यान वेबसाइट पर इस तरह के प्रकाशन की ओर दिलाया जाएगा।
2. प्रत्येक संस्थान अपनी विवरणिका की प्रत्येक मुद्रित प्रति का मूल्य निर्धारित करेगा, जोकि विवरणिका के प्रकाशन और वितरण की उचित लागत से अधिक नहीं होगी और विवरणिका के प्रकाशन, वितरण या बिक्री से कोई लाभ अर्जित नहीं किया जायेगा।

5. छात्र शिकायत निवारण समितियां (एसजीआरसी)

- (i) संस्थान से संबंधित किसी पीड़ित छात्र की किसी भी शिकायत छात्र शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) के अध्यक्ष को संबोधित की जाएगी।
- (ii) प्रत्येक संस्थान छात्रों की शिकायतों पर विचार करने के लिए निम्नलिखित संरचना के साथ उतनी संख्या में छात्रों की शिकायत निवारण समितियों (एसजीआरसी) का गठन करेगा, जितने कि आवश्यकता हो सकती है, नमतः
- क) एक प्रोफेसर – अध्यक्ष
- ख) संस्थान के चार प्रोफेसर/वरिष्ठ संकाय सदस्य- सदस्य के रूप में।
- ग) शैक्षिक योग्यता/खेल-कूद में उत्कृष्टता/सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर नामित किए जाने वाले छात्रों में से एक प्रतिनिधि- विशेष आमंत्रित।
- घ) अध्यक्ष अथवा कम से कम एक सदस्य का महिला होना चाहिए तथा कम से कम एक सदस्य अथवा अध्यक्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए।
- ङ) अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- च) विशेष आमंत्रित सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।
- छ) बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित लेकिन विशेष आमंत्रित व्यक्ति को छोड़ कर तीन का होगा।
- ज) एसजीआरसी अपने समक्ष आने वाली शिकायतों पर विचार करते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा।
- झ) एसजीआरसी अपनी रिपोर्ट सिफारिशों के साथ, यदि कोई हो, संबंधित संस्था के सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा और उसकी एक प्रति पीड़ित छात्र को, अधिमानतः शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 15 कार्य दिवसों की अवधि के अंदर भेजेगा।
- ञ) छात्रों की शिकायत निवारण समिति के निर्णय से पीड़ित कोई भी छात्र इस प्रकार के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है।

6. लोकपाल की नियुक्ति, सेवाकाल, पद से हटाया जाना और सेवा की शर्तें:

- (i) प्रत्येक विश्वविद्यालय इन विनियमों के तहत विश्वविद्यालय के छात्रों और महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से जुड़े संस्थानों के छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए लोकपाल की नियुक्ति करेगा।

- (ii) एसजीआरसी के निर्णयों के विरुद्ध की गई अपीलों को सुनने और उन पर निर्णय लेने के लिए लोकपाल के रूप में नामित एक या अधिक अंशकालिक पदाधिकारी होंगे।
- (iii) लोकपाल सेवानिवृत्त कुलपति या सेवानिवृत्त प्रोफेसर (जिन्होंने अधिष्ठाता (डीन)/विभाग प्रमुख के रूप में काम किया हो) होंगे और उनके पास राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालयों/राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों/सम विश्वविद्यालयों या पूर्व जिले में न्यायाधीश के रूप में 10 वर्ष का अनुभव रहा हो।
- (iv) लोकपालनियुक्ति के समय, नियुक्ति से पहले एक वर्ष के दौरानया लोकपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, संस्थान के साथ हितों के टकराव में नहीं होंगे जहाँ उनके व्यक्तिगत संबंध, पेशेवर संबद्धता या वित्तीय हित समझौता कर सकते हैं या उचित रूप से संस्थान के प्रति निर्णय की स्वतंत्रता से समझौता करने के लिए प्रतीत हो सकते हैं।
- (v) लोकपाल को पद ग्रहण करने की तिथि सेतीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाएगाऔर एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
- (vi) सुनवाई का संचालन करने के लिएलोकपाल को संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रति दिनप्रति बैठक के अधार पर शुल्क का भुगतान किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, वे यात्रा पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।
- (vii) कदाचार या दुर्व्यवहार के सिद्ध आरोपों पर विश्वविद्यालय लोकपाल को पद से हटा सकता है।
- (viii) लोकपाल को हटाने का कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि इस संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जांच नहीं कर ली जाती है, जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के पद से नीचे के पद का व्यक्ति ना हो, और जिसमें लोकपाल को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो।

7. लोकपाल के कार्यकरण:

- (i) लोकपाल, छात्र द्वारा इन विनियमों के तहत उपबंधित सभी विकल्पों को अपनाने के पश्चात् ही पीडितछात्र की अपील की सुनवाई करेंगे।
- (ii) यद्यपि, परीक्षा के संचालन में अथवा मूल्यांकन की प्रक्रिया में गड़बड़ी के मुद्दों को लोकपाल को संदर्भित किया जा सकता है, तथापि, लोकपाल द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन अथवा अंको को पुनः योग करने हेतु कोई अपील अथवा आवेदन पर लोकपाल द्वारा सुनवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि भेदभाव की किसी विशिष्ट घटना के परिणामों को प्रभावित करने वाली किसी विशिष्ट अनियमितता को इंगित नहीं किया जाता है।
- (iii) लोकपाल, कथित रूप से किए गए भेदभाव की शिकायतों की सुनवाई करने के लिएन्याय मित्र के रूप में किसी भी व्यक्ति की सहायता प्राप्त कर सकता है।
- (iv) लोकपाल पीडितछात्र (छात्रों)से अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान करनेके लिए सभी प्रयास करेंगे।

8. लोकपाल तथा छात्र शिकायत निवारण समितियों द्वारा शिकायतों के निवारण हेतु प्रक्रिया

- (i) प्रत्येक संस्थान,इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर एक ऑनलाइनपोर्टल तैयार करेगा, जहां कोई भी पीडितछात्र अपनी शिकायत के निवारण के लिए आवेदन कर सकता है।

- (ii) ऑनलाइन शिकायत प्राप्त होने पर संस्थान, ऑनलाइन शिकायत की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियों सहित शिकायत को उपर्युक्त छात्र शिकायत निवारण समिति को भेजेगा।
- (iii) छात्र शिकायत समिति, जैसा भी मामला हो, शिकायत की सुनवाई के लिए एक तिथि निर्धारित करेगी जिसकी जानकारी संस्थान और पीड़ित छात्र को दी जाएगी।
- (iv) पीड़ित छात्र या तो व्यक्तिगत रूप से पेश हो सकता है अथवा अपना पक्ष रखने के लिए अपने किसी प्रतिनिधि को अधिकृत कर सकता है।
- (v) छात्र शिकायत निवारण समिति द्वारा समाधान नहीं की गई शिकायतों को इन विनियमों में उपबंधित समयवधि के भीतर लोकपाल को भेजा जाएगा।
- (vi) संस्थान, शिकायतों के शीघ्र निपटान हेतु लोकपाल अथवा छात्र शिकायत निवारण समिति (समितियों), जैसा भी मामला हो, का सहयोग करेंगे।
- (vii) लोकपाल, संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, कार्यवाही के समापन पर, तत्संबंधी कारणों के साथ, इस प्रकार का आदेश पारित करेगा, जैसा कि शिकायत के निवारण के लिए उपयुक्त समझा जा सकता है और ऐसी राहत प्रदान कर सकता है जो पीड़ित छात्र के लिए उपयुक्त हो सकती है।
- (viii) संस्थान के साथ ही साथ पीड़ित छात्र को लोकपाल के हस्ताक्षर के तहत जारी की गई आदेश की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
- (ix) संस्थान, लोकपाल की सिफारिशों का अनुपालन करेगा।
- (x) जहां शिकायत झूठी या तुच्छ पाई जाती है उस स्थिति में लोकपाल शिकायतकर्ता के विरुद्ध उपर्युक्त कार्रवाई किए जाने की सिफारिश कर सकता है।

9. लोकपाल और छात्र शिकायत निवारण समितियों के संबंध में जानकारी:

संस्थान अपनी वेबसाइट और अपनी विवरणिका में स्पष्ट रूप से इसके क्षेत्राधिकार में आने वाली छात्र शिकायत निवारण समिति(समितियों) तथा अपील किए जाने के प्रयोजनार्थ लोकपाल के संबंध में सभी संगत जानकारीयां उपलब्ध कराएगा।

10. अनुपालन नहीं किए जाने के परिणाम

आयोग, किसी भी संस्थान के संबंध में, जो जानबूझकर इन विनियमों का उल्लंघन करते हैं अथवा बार-बार लोकपाल या छात्र शिकायत निवारण समितियों की सिफारिश का पालन करने में विफल रहते हैं, जैसा भी मामला हो, जब तक संस्थान आयोग की संतुष्टि तक इन विनियमों का अनुपालन नहीं करता है, तब तक संस्थान के विरुद्ध निम्नवत् एक या एक से अधिक कार्यवाहियां की जा सकती हैं,

- क) अधिनियम की धारा 12बी के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्तता की घोषणा को वापस लेना;
- ख) संस्थान को आवंटित किसी अनुदान को रोका जा सकता है;
- ग) आयोग के किसी भी सामान्य अथवा विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत किसी भी सहायता को प्राप्त करने हेतु विचार किए जाने के लिए संस्थान को अयोग्य घोषित करना;
- घ) संस्थान को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए ऑनलाइन/मुक्त ओर दूरस्थ शिक्षा माध्यम से पाठ्यक्रम की पेशकश करने के लिए अयोग्य घोषित करना;
- ङ) ऑनलाइन/ मुक्त ओर दूरस्थ शिक्षा माध्यम से पाठ्यक्रमों की पेशकश करने की स्वीकृति को वापस लेना/रोकना/निलंबित करना;

- च) उपयुक्त मीडिया में प्रमुखता से प्रदर्शित कर और आयोग की वेबसाइट पर पोस्ट कर प्रवेश हेतु संभावित अभ्यर्थियों सहित जनसाधारण को सूचित करना तथा इस बाबत घोषणा करना कि संस्थान में शिकायतों के निवारण के लिए न्यूनतम मानक मौजूद नहीं हैं;
- छ) महाविद्यालय के मामले में, संबद्धता को वापस लेने के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय को सिफारिश करना;
- ज) सम विश्वविद्यालय संस्थान के मामले में ऐसी कार्रवाई करना, जो आवश्यक, उचित एवं उपयुक्त हो;
- झ) सम विश्वविद्यालय संस्थान के मामले में सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषणा को वापस लिए जाने के लिए, यदि आवश्यक हो तो, केंद्र सरकार को सिफारिश करना;
- ञ) राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित अथवा निर्गमित विश्वविद्यालय के मामले में राज्य सरकार को आवश्यक एवं उचित कार्रवाई करने की सिफारिश करना;
- ट) गैर अनुपालना के लिए संस्थान के प्रति ऐसी कार्रवाई करना जो आवश्यक एवं उपयुक्त समझी जाए।

बशर्ते इन विनियमों के अंतर्गत आयोग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि संस्थान को अपनी स्थिति को स्पष्ट करने एवं उसके पक्ष को सुने जाने का अवसर नहीं दिया गया हो।

11. इन विनियमों में उल्लिखित कोई भी शर्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रोंकी शिकायत निवारण) विनियम, 2019 के प्रावधानोंके अंतर्गत नियुक्त किसी पदधारी लोकपाल के कार्यकाल की अवधि के दौरान उसके पद पर बने रहने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी; कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् लोकपाल की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) के विनियम, 2023 के अनुरूप की जाएगी।

प्रा. मनिष र. जोशी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./13/2023-24]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2023

University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023

F.1-13/2022 (CPP-II).— In exercise of the powers conferred under clause (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), and in supersession of the University Grants Commission (Redress of Grievances of Students) Regulations, 2019, the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely -

1. SHORT TITLE, APPLICATION, AND COMMENCEMENT:

- (a) These regulations shall be called as the University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023.
- (b) They shall apply to all higher education institutions, whether established or incorporated by or under a Central Act or a State Act, and every institution recognized by the University Grants Commission under clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and to all institutions deemed to be a University declared as such under Section 3 therein and to all higher education institutions affiliated to a University.
- (c) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. OBJECTIVE

To provide opportunities for redressal of certain grievances of students already enrolled in any institution, as well as those seeking admission to such institutions, and a mechanism thereto.

3. DEFINITION:

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires-

- (a) “Act” means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
- (b) “aggrieved student” means a student, who has any complaint in the matters relating to or connected with the grievances defined under these regulations.
- (c) “college” means any institution, so defined in clause (b) of sub-section (1) of section 12A of the Act.
- (d) “Commission” means the University Grants Commission established under section 4 of the UGC Act, 1956.
- (e) “declared admission policy” means such policy, including the process there under, for admission to a course or program of study as may be offered by the institution by publication in the prospectus of the institution.
- (f) “grievance” means, and includes, complaint(s) made by an aggrieved student in respect of the following, namely:
 - i. admission contrary to merit determined in accordance with the declared admission policy of the institution;
 - ii. irregularity in the process under the declared admission policy of the institution;
 - iii. refusal to admit in accordance with the declared admission policy of the institution;
 - iv. non-publication of a prospectus by the institution, in accordance with the provisions of these regulations;
 - v. publication by the institution of any information in the prospectus, which is false or misleading, and not based on facts;
 - vi. withholding of, or refusal to return, any document in the form of certificates of degree, diploma or any other award or other document deposited by a student for the purpose of seeking admission in such institution, with a view to induce or compel such student to pay any fee or fees in respect of any course or program of study which such student does not intend to pursue;
 - vii. demand of money in excess of that specified to be charged in the declared admission policy of the institution;
 - viii. violation, by the institution, of any law for the time being in force in regard to reservation of seats in admission to different category of students;
 - ix. non-payment or delay in payment of scholarships or financial aid admissible to any student under the declared admission policy of such institution, or under the conditions, if any, prescribed by the Commission;
 - x. delay by the institution in the conduct of examinations, or declaration of results, beyond the schedule specified in the academic calendar of the institution, or in such calendar prescribed by the Commission;
 - xi. failure by the institution to provide student amenities as set out in the prospectus, or is required to be extended by the institution under any provisions of law for the time being in force;
 - xii. non-transparent or unfair practices adopted by the institution for the evaluation of students;
 - xiii. delay in, or denial of, the refund of fees due to a student who withdraws admission within the time mentioned in the prospectus, subject to guidelines, if any, issued by the Commission, from time to time;
 - xiv. complaints of alleged discrimination of students from the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Women, Minorities or persons with disabilities categories;
 - xv. denial of quality education as promised at the time of admission or required to be provided;
 - xvi. harassment or victimization of a student, other than cases of harassment, which are to be proceeded against under the penal provisions of any law for the time being in force;
 - xvii. any action initiated/taken contrary to the statutes, ordinances, rules, regulations, or guidelines of the institution; and
 - xviii. any action initiated/taken contrary to the regulations and/or guidelines made/issued by the Commission and/or the regulatory body concerned.

- (g) “Institution” means a university as defined in sub-section (f) of Section 2 of the UGC Act, an institution declared as institution deemed to be university under Section 3 of the Act, and a college as defined under section 12A (1) (b) of the University Grants Commission Act, 1956.
- (h) “Ombudsperson” means the Ombudsperson appointed under these regulations;
- (i) “Prospectus” means and includes any publication, whether in print or otherwise, issued for providing fair and transparent information, relating to an institution, to the general public (including to those seeking admission in such institution) by such institution or any authority or person authorized by such institution to do so;
- (j) “Student” means a person enrolled, or seeking admission to be enrolled, in any institution, to which these regulations apply, through any mode i.e., Formal / Open and Distance Learning (ODL) / Online;
- (k) “Students’ Grievance Redressal Committee (SGRC)” means a committee constituted under these regulations, at the level of an institution; and
- (l) “University” means a University so defined in clause (f) of section 2 of the Act or, where the context may be, an institution deemed to be University declared as such under Section 3 thereof.
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the University Grants Commission Act, 1956 shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

4. MANDATORY PUBLICATION OF PROSPECTUS, ITS CONTENTS, AND PRICING:

- (1) Every institution, shall publish and/or upload on its website, before expiry of at least sixty days prior to the date of the commencement of the admission to any of its courses or programs of study, a prospectus containing the following for the information of persons intending to seek admission to such institution and the general public, namely:
- (a) the list of programs of study and courses offered along with the broad outlines of the syllabus specified by the appropriate statutory authority or by the institution, as the case may be, for every course or program of study, including teaching hours, practical sessions and other assignments;
- (b) the number of seats approved by the appropriate statutory authority in respect of each course or program of study for the academic year for which admission is proposed to be made;
- (c) the conditions of educational qualifications and eligibility including the minimum and maximum age limit of persons for admission as a student in a particular course or program of study, specified by the institution;
- (d) the process of selection of eligible candidates applying for such admission, including all relevant information in regard to the details of test or examination for selecting such candidates for admission to each course or program of study and the amount of fee prescribed for the admission test;
- (e) each component of the fee, deposits and other charges payable by the students admitted to such institution for pursuing a course or program of study, and the other terms and conditions of such payment;
- (f) rules/regulations for imposition and collection of any fines in specified heads or categories, minimum and maximum fines may be imposed;
- (g) the percentage of tuition fee and other charges refundable to a student admitted in such institution in case such student withdraws from such institution before or after completion of course or program of study and the time within and the manner in which such refund shall be made to that student;
- (h) details of the teaching faculty, including their educational qualifications, along with their type of appointment (Regular/visiting/guest) and teaching experience of every member thereof;
- (i) information with regard to physical and academic infrastructure and other facilities including hostel accommodation and its fee, library, hospital, or industry wherein the practical training is to be imparted to the students and in particular the amenities accessible by students on being admitted to the institution;
- (j) all relevant instructions in regard to maintaining the discipline by students within or outside the campus of the institution, and, in particular such discipline relating to the prohibition of ragging of any student or students and the consequences thereof and for violating the provisions of any regulation in this behalf made by the relevant statutory regulatory authority; and
- (k) Any other information as may be specified by the Commission.

Provided that an institution shall publish/upload information referred to in clauses (a) to (k) of this regulation, on its website, and the attention of prospective students and the general public shall be drawn to such publication being on the website through advertisements displayed prominently indifferent newspapers and through other media.

- (2) Every institution shall fix the price of each printed copy of the prospectus, being not more than the reasonable cost of its publication and distribution and no profit be made out of the publication, distribution, or sale of prospectus.

5. STUDENT GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES (SGRC):

- (i) A complaint from an aggrieved student relating to the institution shall be addressed to the Chairperson, Students' Grievance Redressal Committee (SGRC).
- (ii) Every Institution shall constitute such number of Students' Grievance Redressal Committees (SGRC), as may be required to consider grievances of the students, with the following composition, namely:
 - a) A Professor - Chairperson
 - b) Four Professors/Senior Faculty Members of the Institution as Members.
 - c) A representative from among students to be nominated on academic merit/excellence in sports/performance in co-curricular activities-Special Invitee.
- (iii) Atleast one member or the Chairperson shall be a woman and atleast one member or the Chairperson shall be from SC/ST/OBC category.
- (iv) The term of the chairperson and members shall be for a period of two years.
- (v) The term of the special invitee shall be one year.
- (vi) The quorum for the meeting including the Chairperson, but excluding the special invitee, shall be three.
- (vii) In considering the grievances before it, the SGRC shall follow principles of natural justice.
- (viii) The SGRC shall send its report with recommendations, if any, to the competent authority of the institution concerned and a copy thereof to the aggrieved student, preferably within a period of 15 working days from the date of receipt of the complaint.
- (ix) Any student aggrieved by the decision of the Students' Grievance Redressal Committee may prefer an appeal to the Ombudsperson, within a period of fifteen days from the date of receipt of such decision.

6. APPOINTMENT, TENURE, REMOVAL AND CONDITIONS OF SERVICES OF OMBUDSPERSON:

- (i) Each University shall appoint Ombudsperson for redressal of grievances of students of the university and colleges/institutions affiliated with the university under these regulations.
- (ii) There shall be one or more part-time functionaries designated as Ombudspersons to hear, and decide on, appeals preferred against the decisions of the SGRCs.
- (iii) The Ombudsperson shall be a retired Vice-Chancellor or a retired Professor (who has worked as Dean/HOD) and has 10 years' experience as a Professor at State/Central Universities/Institutions of National Importance/Deemed to be Universities or a former District Judge.
- (iv) The Ombudsperson shall not, at the time of appointment, during one year before appointment, or in the course of his/her tenure as Ombudsperson, be in conflict of interest with the Institution where his/her personal relationship, professional affiliations or financial interest may compromise or reasonably appear to compromise, the independence of judgment towards the Institution.
- (v) The Ombudsperson shall be appointed for a period of three years or until he/she attains the age of 70 years, whichever is earlier, from the date of assuming office, and shall be eligible for reappointment for another one term.
- (vi) For conducting the hearings, the Ombudsperson shall be paid a sitting fee, per diem, in accordance with the norms fixed by the respective university and shall, in addition, be eligible for reimbursement of the expenditure incurred on conveyance.
- (vii) The University may remove the Ombudsperson from office, on charges of proven misconduct or misbehaviour.
- (viii) No order of removal of Ombudsperson shall be made except after an inquiry made in this regard by a person, not below the rank of a retired judge of the High Court in which a reasonable opportunity of being heard is given to the Ombudsperson.

7. FUNCTIONS OF OMBUDSPERSON:

- (i) The Ombudsperson shall hear appeals from an aggrieved student, only after the student has availed all other remedies provided under these regulations.

- (ii) While issues of malpractices in the conduct of examination or in the process of evaluation may be referred to the Ombudsperson, no appeal or application for revaluation or re-totalling of answer sheets from an examination, shall be entertained by the Ombudsperson unless specific irregularity materially affecting the outcome or specific instance of discrimination is indicated.
- (iii) The Ombudsperson may avail assistance of any person, as amicus curiae, for hearing complaints of alleged discrimination.
- (iv) The Ombudsperson shall make all efforts to resolve the grievances within a period of 30 days of receiving the appeal from the aggrieved student(s).

8. PROCEDURE FOR REDRESSAL OF GRIEVANCES BY OMBUDSPERSONS AND STUDENT GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES:

- (i) Each institution shall, within a period of three months from the date of issue of this notification, have an online portal where any aggrieved student may submit an application seeking redressal of grievance.
- (ii) On receipt of an online complaint, the institution shall refer the complaint to the appropriate Students' Grievance Redressal Committee, along with its comments within 15 days of receipt of complaint on the online portal.
- (iii) The Students' Grievance Redressal Committee, as the case may be, shall fix a date for hearing the complaint which shall be communicated to the institution and the aggrieved student.
- (iv) An aggrieved student may appear either in person or authorize a representative to present the case.
- (v) Grievances not resolved by the Students' Grievance Redressal Committee within the time period provided in these regulations may be referred to the Ombudsperson by the university.
- (vi) Institutions shall extend co-operation to the Ombudsperson or the Student Grievance Redressal Committee(s), in early redressal of grievances.
- (vii) The Ombudsperson shall, after giving reasonable opportunities of being heard to the parties concerned, on the conclusion of proceedings, pass such order, with reasons thereof, as may be deemed fit to redress the grievance and provide such relief as may be appropriate to the aggrieved student
- (viii) The institution, as well as the aggrieved student, shall be provided with copies of the order under the signature of the Ombudsperson.
- (ix) The institution shall comply with the recommendations of the Ombudsperson.
- (x) The Ombudsperson may recommend appropriate action against the complainant, where a complaint is found to be false or frivolous.

9. INFORMATION REGARDING OMBUDSPERSONS AND STUDENT GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES:

An institution shall furnish, prominently, on its website and in its prospectus, all relevant information in respect of the Students' Grievance Redressal Committee(s) coming in its purview, and the Ombudsperson for the purpose of appeals.

10. CONSEQUENCES OF NON-COMPLIANCE:

The Commission shall in respect of any institution, which wilfully contravenes these regulations or repeatedly fails to comply with the recommendation of the Ombudsperson or the Students' Grievance Redressal Committee, as the case may be, proceed to take one or more of the following actions till the institution complies with these Regulations to the satisfaction of the Commission, namely:

- (a) withdrawal of declaration of fitness to receive grants under section 12B of the Act;
- (b) withholding any grant allocated to the Institution;

- (c) declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programs of the Commission;
- (d) declaring the institution ineligible to offer courses through Online/ODL mode for a specified period;
- (e) withdrawing / withholding / suspending the approval for offering courses through Online/ODL mode;
- (f) informing the general public, including potential candidates for admission, through a notice displayed prominently in suitable media and posted on the website of the Commission, declaring that the institution does not possess the minimum standards for redressal of grievances;
- (g) recommend to the affiliating University for withdrawal of affiliation, in case of a college;
- (h) take such action as it may deem necessary, appropriate and fit, in case of an institution deemed to be University;
- (i) recommend to the Central Government, if required, for withdrawal of declaration as institution deemed to be a University, in case of an institution deemed to be University;
- (j) recommend to the State Government to take necessary and appropriate action, in case of a University established or incorporated under a State Act;
- (k) such other action as may be deemed necessary and appropriate against an institution for non-compliance.

Provided that no action shall be taken by the Commission under this regulation, unless the institution has been provided an opportunity of being heard to explain its position.

11. Nothing mentioned herein above in these regulations shall affect the continuance in office, during the currency of the term, of an incumbent Ombudsperson appointed under the provisions of the UGC (Redress of Grievances of Students) Regulations, 2019; where after, the appointment of Ombudsperson shall be made as per University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023.

Prof. MANISH R. JOSHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./13/2023-24]

Guidelines for Internal Complaint Committee



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2016/वैशाख 12, 1938

No. 171]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2016/ VAISAKHA 12, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम 2015

मि. सं. 91-1/2013 (टी. एफ. जी. एस.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) जिसे उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 20 के उप-अनुच्छेद (1) से संयुक्त रूप से पढ़ा जाए उस अधिनियम 26 के अनुच्छेद (1) की धारा (जी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रियान्वयन अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्वारा निम्न विनियम निर्मित कर रहा है, नामतः :-

1. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं समारम्भ:- (1) ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम, 2015 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम भारत वर्ष में सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों पर लागू होंगे।

(3) सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से वे लागू माने जाएँगे।

2. परिभाषाएँ:- इन विनियमों में—बशर्ते विषयवस्तु के अन्तर्गत कुछ अन्यथा जरूरी है:-

(अ) "पीड़ित महिला" से अर्थ है किसी भी आयु वर्ग की एक ऐसी महिला—चाहे वह रोजगार में है या नहीं, किसी कार्य स्थल में कथित तौर से प्रतिवादी द्वारा कोई लैंगिक प्रताड़ना के कार्य का शिकार बनी है;

(ब) "अधिनियम" से अर्थ है कार्य स्थल में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निराकरण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 (2013 का 14);

(स) "परिसर" का अर्थ उस स्थान अथवा भूमि से है जहाँ पर उच्चतर शैक्षिक संस्थान तथा इसकी संबद्ध संस्थागत सुविधाएँ जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, लेक्चर हॉल, आवास, हॉल, शौचालय, छात्र केन्द्र, छात्रावास, भोजन कक्षों, स्टेडियम, वाहन पड़ाव स्थल, उपवनों जैसे स्थल तथा अन्य कुछ सुविधाएँ जैसे स्वास्थ्य केन्द्र, कैन्टीन, बैंक पटल इत्यादि स्थित हैं तथा जिसमें छात्रों द्वारा उच्चशिक्षा के छात्र के रूप में दौरा किया जाता हो—जिस में वह परिवहन शामिल है जो उन्हें उस संस्थान से आने जाने के लिए, उस संस्थान के अलावा क्षेत्रीय भ्रमण हेतु

- (जी) यदि वह एक मानित विश्वविद्यालय संस्थान है तो केन्द्र सरकार को उस मानित विश्वविद्यालय के आहरण की अनुशंसा करना;
- (एच) यदि वह किसी राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अथवा नियमित विश्वविद्यालय है तो उसके इस स्तर को आहरित करने के लिए उपयुक्त राज्य सरकार को सिफारिश करना;
- (आई) जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रावधान किया जाना हो तदनुसार अपने अधिकारों के अनुसार यथोचित रूप से ऐसी समयावधि के लिए दण्ड प्रदान कर सकता है जिस समय तक वह संस्थान इन विनियमों में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है;
- (जे) इन विनियमों के अन्तर्गत आयोग द्वारा उस समय तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि संस्थान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रदत्त सुअवसर के आधार पर उनकी सुनवाई कर ली गई हो;

[विज्ञापन—III/4/असा./53]

जसपाल एस. संधु, सचिव, यूजीसी

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(University Grants Commission)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2016

University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) Regulations, 2015

No. F. 91-1/2013(TFGS).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), read with sub-section (1) of Section 20 of the said Act, the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title, application and commencement.**—(1) These regulations may be called the University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) Regulations, 2015.
 - (2) They shall apply to all higher educational institutions in India.
 - (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**—In these regulations, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "aggrieved woman" means in relation to work place, a woman of any age whether employed or not, who alleges to have been subjected to any act of sexual harassment by the respondent;
 - (b) 'Act' means the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013);
 - (c) "campus" means the location or the land on which a Higher Educational Institution and its related institutional facilities like libraries, laboratories, lecture halls, residences, halls, toilets, student centres, hostels, dining halls, stadiums, parking areas, parks-like settings and other amenities like health centres, canteens, Bank counters, etc., are situated and also includes extended campus and covers within its scope places visited as a student of the HEI including transportation provided for the purpose of commuting to and from the institution, the locations outside the institution on field trips, internships, study tours, excursions, short-term placements, places used for camps, cultural festivals, sports meets and such other activities where a person is participating in the capacity of an employee or a student of the HEI;

- (d) Commission” means the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
- (e) “covered individuals” are persons who have engaged in protected activity such as filing a sexual harassment charge, or who are closely associated with an individual who has engaged in protected activity and such person can be an employee or a fellow student or guardian of the offended person;
- (f) “employee” means a person as defined in the Act and also includes, for the purposes of these Regulations trainee, apprentice (or called by any other name), interns, volunteers, teacher assistants, research assistants, whether employed or not, including those involved in field studies, projects, short-visits and camps;
- (g) “Executive Authority” means the chief executive authority of the HEI, by whatever name called, in which the general administration of the HEI is vested. For public funded institutions the Executive Authority means the Disciplinary Authority as indicated in Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 or its equivalent rules;
- (h) “Higher Educational Institution” (HEI) means a university within the meaning of clause (j) of section 2, a college within the meaning of clause(b) of sub-section (1) of section 12A and an institution deemed to be a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
- (i) “Internal Complaints Committee” (ICC) means Internal Complaints Committee to be constituted by an HEI under sub regulation (1) of regulation 4 of these regulations. Any existing body already functioning with the same objective (like the Gender Sensitization Committee Against Sexual Harassment (GSCASH)) should be reconstituted as the ICC;
- Provided that in the latter case the HEI shall ensure that the constitution of such a Body is as required for ICC under these regulations. Provided further that such a Body shall be bound by the provisions of these regulations;
- (j) “protected activity” includes reasonable opposition to a practice believed to violate sexual harassment laws on behalf of oneself or others such as participation in sexual harassment proceedings, cooperating with an internal investigation or alleged sexual harassment practices or acting as a witness in an investigation by an outside agency or in litigation;
- (k) “sexual harassment” means-
- (i) “An unwanted conduct with sexual undertones if it occurs or which is persistent and which demeans, humiliates or creates a hostile and intimidating environment or is calculated to induce submission by actual or threatened adverse consequences and includes any one or more or all of the following unwelcome acts or behaviour (whether directly or by implication), namely;-
- (a) any unwelcome physical, verbal or non verbal conduct of sexual nature;
- (b) demand or request for sexual favours;
- (c) making sexually coloured remarks
- (d) physical contact and advances; or
- (e) showing pornography”
- (ii) any one (or more than one or all) of the following circumstances, if it occurs or is present in relation or connected with any behaviour that has explicit or implicit sexual undertones-
- (a) implied or explicit promise of preferential treatment as quid pro quo for sexual favours;
- (b) implied or explicit threat of detrimental treatment in the conduct of work;
- (c) implied or explicit threat about the present or future status of the person concerned;
- (d) creating an intimidating offensive or hostile learning environment;
- (e) humiliating treatment likely to affect the health, safety dignity or physical integrity of the person concerned;

- (l) “student” means a person duly admitted and pursuing a programme of study either through regular mode or distance mode, including short-term training programmes in a HEI;
 Provided that a student who is in the process of taking admission in HEIs campus, although not yet admitted, shall be treated, for the purposes of these regulations, as a student of that HEI, where any incident of sexual harassment takes place against such student;
 Provided that a student who is a participant in any of the activities in a HEI other than the HEI where such student is enrolled shall be treated, for the purposes of these regulations, as a student of that HEI where any incident of sexual harassment takes place against such student;
- (m) “third Party Harassment” refers to a situation where sexual harassment occurs as a result of an act or omission by any third party or outsider, who is not an employee or a student of the HEI, but a visitor to the HEI in some other capacity or for some other purpose or reason;
- (n) “victimisation” means any unfavourable treatment meted out to a person with an implicit or explicit intention to obtain sexual favour;
- (o) “workplace” means the campus of a HEI including-
- (a) Any department, organisation, undertaking, establishment, enterprise, institution, office, branch or unit which is established, owned, controlled or wholly or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the appropriate HEIs;
 - (b) Any sports institute, stadium, sports complex or competition or games venue, whether residential or not used for training, sports or other activities relating thereof in HEIs;
 - (c) Any place visited by the employee or student arising out of or during the course of employment or study including transportation provided by the Executive Authority for undertaking such journey for study in HEIs.’

3. Responsibilities of the Higher Educational Institution- (1) Every HEI shall,-

- (a) Wherever required, appropriately subsume the spirit of the above definitions in its policy and regulations on prevention and prohibition of sexual harassment against the employees and the students, and modify its ordinances and rules in consonance with the requirements of the Regulations;
- (b) publicly notify the provisions against sexual harassment and ensure their wide dissemination;
- (c) organise training programmes or as the case may be, workshops for the officers, functionaries, faculty and students, as indicated in the SAKSHAM Report (Measures for Ensuring the Safety of Women and Programmes for Gender Sensitization on Campuses) of the Commission, to sensitize them and ensure knowledge and awareness of the rights, entitlements and responsibilities enshrined in the Act and under these regulations;
- (d) act decisively against all gender based violence perpetrated against employees and students of all sexes recognising that primarily women employees and students and some male students and students of the third gender are vulnerable to many forms of sexual harassment and humiliation and exploitation;
- (e) publicly commit itself to a zero tolerance policy towards sexual harassment;
- (f) reinforce its commitment to creating its campus free from discrimination, harassment, retaliation or sexual assault at all levels;
- (g) create awareness about what constitutes sexual harassment including hostile environment harassment and quid pro quo harassment;
- (h) include in its prospectus and display prominently at conspicuous places or Notice Boards the penalty and consequences of sexual harassment and make all sections of the institutional community aware of the information on the mechanism put in place for redressal of complaints pertaining to sexual

harassment, contact details of members of Internal Complaints Committee , complaints procedure and so on. Any existing body already functioning with the same objective (like the Gender Sensitization Committee Against Sexual Harassment (GSCASH)) should be reconstituted as the ICC; Provided that in the latter case the HEI shall ensure that the constitution of such a Body is as required for ICC under these regulations. Provided further that such a Body shall be bound by the provisions of these regulations;

- (i) inform employees and students of the recourse available to them if they are victims of sexual harassment;
- (j) organise regular orientation or training programmes for the members of the ICC to deal with complaints, steer the process of settlement or conciliation, etc., with sensitivity;
- (k) proactively move to curb all forms of harassment of employees and students whether it is from those in a dominant power or hierarchical relationship within HEIs or owing to intimate partner violence or from peers or from elements outside of the geographical limits of the HEI;
- (l) be responsible to bring those guilty of sexual harassment against its employees and students to book and initiate all proceedings as required by law and also put in place mechanisms and redressal systems like the ICC to curb and prevent sexual harassment on its campus;
- (m) treat sexual harassment as a misconduct under service rules and initiate action for misconduct if the perpetrator is an employee;
- (n) treat sexual harassment as a violation of the disciplinary rules (leading up to rustication and expulsion) if the perpetrator is a student;
- (o) ensure compliance with the provisions of these regulations, including appointment of ICC, within a period of sixty days from the date of publication of these regulations;
- (p) monitor the timely submission of reports by the ICC;
- (q) prepare an annual status report with details on the number of cases filed and their disposal and submit the same to the Commission.

3.2 **Supportive measures.**—(1) The rules, regulations or any such other instrument by which ICC shall function have to be updated and revised from time-to-time, as court judgments and other laws and rules will continue to revise the legal framework within which the Act is to be implemented.

(2) The Executive Authority of the HEIs must mandatorily extend full support to see that the recommendations of the ICC are implemented in a timely manner. All possible institutional resources must be given to the functioning of the ICC, including office and building infrastructure (computers, photocopiers, audio-video, equipment, etc.), staff (typists, counselling and legal services) as, well as a sufficient allocation of financial resources.

(3) Vulnerable groups are particularly prone to harassment and also find it more difficult to complain. Vulnerability can be socially compounded by region, class, caste, sexual orientation, minority identity and by being differently abled. Enabling committees must be sensitive to such vulnerabilities and special needs.

(4) Since research students and doctoral candidates are particularly vulnerable the HEIs must ensure that the guidelines for ethics for Research Supervision are put in place.

(5) All HEIs must conduct a regular and half yearly review of the efficacy and implementation of their anti-sexual harassment policy.

(6) All Academic Staff Colleges (now known as Human Resource Development Centres (HRDCs) and Regional Centres for Capacity Building (RCCBs) must incorporate sessions on gender in their orientation and refresher courses. This should be across disciplines, and preferably mainstreamed using the UGC SAKSHAM Report which provides indicative modules in this regard.

(7) Orientation courses for administrators conducted in HEIs must have a module on gender sensitization and sexual harassment issues. Regular workshops are to be conducted for all sections of the HEI community.

(8) Counselling services must be institutionalised in all HEIs and must have well trained full-time counsellors.

(9) Many HEIs having large campuses have a deficit in lighting and are experienced as unsafe places by the institutional community. Adequate lighting is a necessary aspect of infrastructure and maintenance.

(10) Adequate and well trained security including a good proportion or balance of women security staff is necessary. Security staff must receive gender sensitization training as a part of conditions of appointment.

(11) HEIs must ensure reliable public transport, especially within large campuses between different sections of the HEI, hostels, libraries, laboratories and main buildings, and especially those that do not have good access for day scholars. Lack of safety as well as harassment is exacerbated when employees and students cannot depend on safe public transport. Reliable transport may be considered by HEIs to enable employees and students to work late in libraries, laboratories and to attend programmes in the evenings.

(12) Residential HEIs should accord priority to construction of women's hostels. For the growing population of young women wishing to access higher education, hostel accommodation is desirable in both urban and rural areas and at all levels of higher education which provides a modicum of protection from harassment of all kinds.

(13) Concern for the safety of women students must not be cited to impose discriminatory rules for women in the hostels as compared to male students. Campus safety policies should not result in securitization, such as over monitoring or policing or curtailing the freedom of movement, especially for women employees and students.

(14) Adequate health facilities are equally mandatory for all HEIs. In the case of women this must include gender sensitive doctors and nurses, as well as the services of a gynaecologist.

(15) The Women's Development Cells in colleges shall be revived and funded to be able to carry out the range of activities required for gender sensitization and remain autonomous of the functioning of anti sexual harassment committees and ICCs. At the same time they shall extend their activities to include gender sensitization programmes in consultation with ICCs and help to disseminate anti-sexual harassment policies on campuses on a regular basis. The 'cultural' space and the 'formal academic space' need to collaborate to render these workshops innovative, engaging and non-mechanical.

(16) Hostel Wardens, Provosts, Principals, Vice Chancellors, Legal Officers and other functionaries must be brought within the domain of accountability through amendments in the rules or Ordinances where necessary.

4. Grievance redressal mechanism.—(1) Every Executive Authority shall constitute an Internal Complaints Committee (ICC) with an inbuilt mechanism for gender sensitization against sexual harassment. The ICC shall have the following composition:-

- (a) A Presiding Officer who shall be a woman faculty member employed at a senior level (not below a Professor in case of a university, and not below an Associate Professor or Reader in case of a college) at the educational institution, nominated by the Executive Authority;

Provided that in case a senior level woman employee is not available, the Presiding Officer shall be nominated from other offices or administrative units of the workplace referred to in sub-section 2(o);

Provided further that in case the other offices or administrative units of the workplace do not have a senior level woman employee, the Presiding Officer shall be nominated from any other workplace of the same employer or other department or organization;”

- (b) two faculty members and two non-teaching employees, preferably committed to the cause of women or who have had experience in social work or have legal knowledge, nominated by the Executive Authority;
- (c) Three students, if the matter involves students, who shall be enrolled at the undergraduate, master's, and research scholar levels respectively, elected through transparent democratic procedure;
- (d) one member from amongst non-government organisations or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issues relating to sexual harassment, nominated by the Executive Authority.

(2) At least one-half of the total members of the ICC shall be women.

(3) Persons in senior administrative positions in the HEI, such as Vice- Chancellor, Pro Vice-Chancellors, Rectors, Registrar, Deans, Heads of Departments, etc., shall not be members of ICCs in order to ensure autonomy of their functioning.

(4) The term of office of the members of the ICC shall be for a period of three years. HEIs may also employ a system whereby one –third of the members of the ICC may change every year.

(5) The Member appointed from amongst the non-governmental organizations or associations shall be paid such fees or allowances for holding the proceedings of the Internal Committee, by the Executive Authority as may be prescribed.

(6) Where the Presiding Officer or any member of the Internal Committee:

- (a) contravenes the provisions of section 16 of the Act; or
- (b) has been convicted for an offence or an inquiry into an offence under any law for the time being in force is pending against him; or
- (c) he has been found guilty in any disciplinary proceedings or a disciplinary proceeding is pending against him; or
- (d) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest,

such Presiding Officer or Member, as the case may be, shall be removed from the Committee and the vacancy so created or any casual vacancy shall be filled by fresh nomination in accordance with the provisions of this section.”

5. Responsibilities of Internal Complaints Committee (ICC) - The Internal Complaints Committee shall:

- (a) provide assistance if an employee or a student chooses to file a complaint with the police;

- (b) provide mechanisms of dispute redressal and dialogue to anticipate and address issues through just and fair conciliation without undermining complainant's rights, and minimize the need for purely punitive approaches that lead to further resentment, alienation or violence;
- (c) protect the safety of the complainant by not divulging the person's identity, and provide the mandatory relief by way of sanctioned leave or relaxation of attendance requirement or transfer to another department or supervisor as required during the pendency of the complaint, or also provide for the transfer of the offender;
- (d) ensure that victims or witnesses are not victimised or discriminated against while dealing with complaints of sexual harassment; and
- (e) ensure prohibition of retaliation or adverse action against a covered individual because the employee or the student is engaged in protected activity.

6. The process for making complaint and conducting Inquiry – The ICC shall comply with the procedure prescribed in these Regulations and the Act, for making a complaint and inquiring into the complaint in a time bound manner. The HEI shall provide all necessary facilities to the ICC to conduct the inquiry expeditiously and with required privacy

7. Process of making complaint of sexual harassment - An aggrieved person is required to submit a written complaint to the ICC within three months from the date of the incident and in case of a series of incidents within a period of three months from the date of the last incident.

Provided that where such complaint cannot be made in writing, the Presiding Officer or any Member of the Internal Committee shall render all reasonable assistance to the person for making the complaint in writing;

Provided further that the ICC may, for the reasons to be accorded in the writing, extend the time limit not exceeding three months, if it is satisfied that the circumstances were such which prevented the person from filing a complaint within the said period.”

Friends, relatives, Colleagues, Co-students, Psychologist, or any other associate of the victim may file the complaint in situations where the aggrieved person is unable to make a complaint on account of physical or mental in capacity or death.

8. Process of conducting Inquiry- (1) The ICC shall, upon receipt of the complaint, send one copy of the complaint to the respondent within a period of seven days of such receipt.

(2) Upon receipt of the copy of the complaint, the respondent shall file his or her reply to the complaint along with the list of documents, and names and addresses of witnesses within a period of ten days.

(3) The inquiry has to be completed within a period of ninety days from the receipt of the complaint. The inquiry report, with recommendations, if any, has to be submitted within ten days from the completion of the inquiry to the Executive Authority of the HEI. Copy of the findings or recommendations shall also be served on both parties to the complaint.

(4) **The Executive Authority of the HEI shall act on the recommendations of the committee within a period of thirty days from the receipt of the inquiry report, unless an appeal against the findings is filed within that time by either party.**

(5) An appeal against the findings or /recommendations of the ICC may be filed by either party before the Executive Authority of the HEI within a period of thirty days from the date of the recommendations.

(6) If the Executive Authority of the HEI decides not to act as per the recommendations of the ICC, then it shall record written reasons for the same to be conveyed to ICC and both the parties to the proceedings. If on the other hand it is decided to act as per the recommendations of the ICC, then a show cause notice, answerable within ten days, shall be served on the party against whom action is decided to be taken. The Executive Authority of the HEI shall proceed only after considering the reply or hearing the aggrieved person.

(7) The aggrieved party may seek conciliation in order to settle the matter. No monetary settlement should be made as a basis of conciliation. The HEI shall facilitate a conciliation process through ICC, as the

case may be, once it is sought. The resolution of the conflict to the full satisfaction of the aggrieved party wherever possible, is preferred to purely punitive intervention.

(8) The identities of the aggrieved party or victim or the witness or the offender shall not be made public or kept in the public domain especially during the process of the inquiry.

9. Interim redressal-The HEI may,

- (a) transfer the complainant or the respondent to another section or department to minimise the risks involved in contact or interaction, if such a recommendation is made by the ICC;
- (b) grant leave to the aggrieved with full protection of status and benefits for a period up to three months;
- (c) restrain the respondent from reporting on or evaluating the work or performance or tests or examinations of the complainant;
- (d) ensure that offenders are warned to keep a distance from the aggrieved, and wherever necessary, if there is a definite threat, restrain their entry into the campus;
- (e) take strict measures to provide a conducive environment of safety and protection to the complainant against retaliation and victimisation as a consequence of making a complaint of sexual harassment.

10. Punishment and compensation- (1) Anyone found guilty of sexual harassment shall be punished in accordance with the service rules of the HEI, if the offender is an employee.

(2) Where the respondent is a student, depending upon the severity of the offence, the HEI may,-

- (a) withhold privileges of the student such as access to the library, auditoria, halls of residence, transportation, scholarships, allowances, and identity card;
 - (b) suspend or restrict entry into the campus for a specific period;
 - (c) expel and strike off name from the rolls of the institution, including denial of readmission, if the offence so warrants;
 - (d) award reformatory punishments like mandatory counselling and, or, performance of community services.
- (3) The aggrieved person is entitled to the payment of compensation. The HEI shall issue direction for payment of the compensation recommended by the ICC and accepted by the Executive Authority, which shall be recovered from the offender. The compensation payable shall be determined on the basis of-
- (a) mental trauma, pain, suffering and distress caused to the aggrieved person;
 - (b) the loss of career opportunity due to the incident of sexual harassment;
 - (c) the medical expenses incurred by the victim for physical, psychiatric treatment;
 - (d) the income and status of the alleged perpetrator and victim; and
 - (e) the feasibility of such payment in lump sum or in instalments.

11. Action against frivolous complaint.—To ensure that the provisions for the protection of employees and students from sexual harassment do not get misused, provisions against false or malicious complaints have to be made and publicised within all HEIs. If the ICC concludes that the allegations made were false, malicious or the complaint was made knowing it to be untrue, or forged or misleading information has been provided during the inquiry, the complainant shall be liable to be punished as per the provisions of sub-regulations (1) of regulations 10, if the complainant happens to be an employee and as per sub-regulation (2)

of that regulation, if the complainant happens to be a student. However, the mere inability to substantiate a complaint or provide adequate proof will not attract attention against the complainant. Malicious intent on the part of the complainant shall not be established without an inquiry, in accordance with the procedure prescribed, conducted before any action is recommended.

12. Consequences of non-compliance.—(1) The Commission shall, in respect of any institution that will fully contravenes or repeatedly fails to comply with the obligations and duties laid out for the prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of employees and students, take one or more of the following actions after providing due notice: -

- (a) withdrawal of declaration of fitness to receive grants under section 12B of the University Grants Commission Act, 1956.
 - (b) removing the name of the university or college from the list maintained by the Commission under clause (f) of section 2 of said Act, 1956;
 - (c) withholding any grant allocated to the institution;
 - (d) declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programmes of the Commission;
 - (e) informing the general public, including potential candidates for employment or admission, through a notice displayed prominently in the newspapers or other suitable media and posted on the website of the Commission, declaring that the institution does not provide for a zero tolerance policy against sexual harassment;
 - (f) recommending the affiliating university for withdrawal of affiliation, in case of a college;
 - (g) recommending the Central Government for withdrawal of declaration as an institution deemed to be university, in case of an institution deemed to be university;
 - (h) recommending the appropriate State Government for withdrawal of status as university in case of a university established or incorporated under a State Act.
 - (i) taking such other action within its powers as it may deem fit and impose such other penalties as may be provided in the University Grants Commission Act, 1956 for such duration of time till the institution complies with the provisions of these regulations.
- (2) No action shall be taken by the Commission under these regulations unless the Institution has been given an opportunity to explain its position and an opportunity of being heard has been provided to it.

[Advt.-III/4/Exty./53]

JASPAL S. SANDHU, Secy. UGC



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 18/05/2024

Documents of Clarification 2 for 5.1.4: Circular/Web-Link/Committee report justifying the objective of the metric


(Tridib Santapa Kundu)
Principal
Principal
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

CIRCULAR

Memo No.: DBM/IQAC/Com./01/2018-19

Date: 06/07/2018

For Teaching, Non-Teaching staff and Students' Council Members of the college

This order/circular is being circulated to inform the constitution of the Anti-Ragging Committee, Internal Complaints Committee and Students' Grievance Redressal Committee. These Committees have been formed in accordance with the UGC norms, Department of higher education Govt. of West Bengal/University.

Committees constituted by way of inclusion following members.

Anti-Ragging Committee

Year: 2018-2019

Serial No.	Name of Committee members	Designation	'Representative of'
1	Dr. Sagar Chandra Bandyopadhyay	Teacher-In-Charge	
2	IC, Chittaranjan PS	IC, Chittaranjan	Police administration
3	Mr. Abhoy Mondal	Sampadak, 'Prantabhumi'	Local media
4	Mr. Subhasish Khawash	General Secretary, 'Ujjiban'	NGO
5	Mr. Tirtha Mondal	Assistant Professor	Faculty members
6	Mrs. Mousumi Kundu	Assistant Professor	Faculty members
7	Dr. Jotimay Bag	Assistant Professor	Faculty members
8	Mr. Jiten Bauri	-	Parents
9	Mr. Sunil Mondal	-	Parents
10	Satabdi Rakshit	Student, Dept. of Geography	Fresh students
11	Sujay Murmu	Student, Dept. of Commerce	Fresh students
12	Avik Bose	Student, Dept. of English	Senior students
13	Puja Mondal	Student, Dept. of Bengali	Senior students
14	Sourav Dutta	Student, Dept. of History	Senior students
15	Mrs. Shampa Banerjee Ganguly	Lady attendant	Non -Teaching Staff
16	Mr. Shyamal Raut	Office Staff	Non -Teaching Staff

Kanujee
Teacher-In-charge
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 06/07/2018

Anti-Ragging Committee(Squad)

Year: 2018-2019

Serial No.	Name of Committee members	Designation	'Representative of'
1	Dr. Sagar Chandra Bandyopadhyay	Teacher-In-Charge	
2	Mr. Tirtha Mondal	Assistant Professor	Faculty members
3	Mrs. Mousumi Kundu	Assistant Professor	Faculty members
4	Dr. Jotimay Bag	Assistant Professor	Faculty members
5	Mrs. Shampa Banerjee Ganguly	Lady attendant	Non -Teaching Staff
6	Mr. Shyamal Raut	Office Staff	Non -Teaching Staff

Banerjee

Teacher-In-charge

**Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan**



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 06/07/2018

Students' Grievance Redressal Committee

Year: 2018-2019

Serial No.	Name of Committee members	Designation	Nominated as
1	Dr. Sagar Chandra Bandyopadhyay	Teacher-In-Charge	Chairperson
2	Mr. Apurbo Kumar Roy	Associate Professor of Philosophy	Member
3	Dr. Jotimay Bag	Assistant Professor of Hindi	Member
4	Dr. Mukul Kamle	Assistant Professor of Geography	Member
5	Dr. Koushik Kumar Hati	Assistant Professor of Economics	Member
6	General Secretary, Students' Union	Students' Representative	Member

Kanujee

Teacher-In-charge

Deshabandhu Mahavidyalaya

Chittaranjan



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 06/07/2018

Internal Complaints Committee

Year: 2018-2019

Serial No.	Name of Committee members	Designation	Nominated as
1	Sagarika Nandy	Assistant Professor of Mathematics	Presiding Officer
2	Sanchita Hazra	Assistant Professor of Political Science	Member
3	Mousumi Kundu	Assistant Professor of Chemistry	Member
4	Shampa Banerjee Ganguli	Lady Attendant (NTS)	Member
5	Falguni Karmakar	Social Worker	Member

Teacher-In-charge

**Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan**



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

CIRCULAR

Memo No.: DBM/IQAC/Com./02/2019-20

Date: 08/07/2019

For Teaching, Non-Teaching staff and Students' Council Members of the college

This order/circular is being circulated to inform the constitution of the Anti-Ragging Committee, Internal Complaints Committee and Students' Grievance Redressal Committee. These Committees have been formed in accordance with the UGC norms, Department of higher education Govt. of West Bengal/University.

Committees constituted by way of inclusion following members.

Anti-Ragging Committee

Year: 2019-2020

Serial No.	Name of Committee members	Designation	'Representative of'
1	Dr. Sagar Chandra Bandyopadhyay	Teacher-In-Charge	
2	IC, Chittaranjan PS	IC, Chittaranjan	Police administration
3	Mr. Abhoy Mondal	Sampadak, 'Prantabhumi'	Local media
4	Mr. Subhasish Khawash	General Secretary, 'Ujjiban'	NGO
5	Mr. Tirtha Mondal	Assistant Professor	Faculty members
6	Mrs. Mousumi Kundu	Assistant Professor	Faculty members
7	Dr. Jotimay Bag	Assistant Professor	Faculty members
8	Mr. Jiten Bauri	-	Parents
9	Mr. Sunil Mondal	-	Parents
10	Shraboni Majumder	Student, Dept. of Economics	Fresh students
11	Swarnava Karfa	Student, Dept. of Chemistry	Fresh students
12	Satabdi Rakshit	Student, Dept. of Geography	Senior students
13	Avik Bose	Student, Dept. of English	Senior students
14	Krishna Singh	Student, Dept. of Bengali	Senior students
15	Mrs. Shampa Banerjee Ganguly	Lady attendant	Non -Teaching Staff
16	Mr. Shyamal Raut	Office Staff	Non -Teaching Staff

Banerjee

Teacher-In-charge

**Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan**



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date:07/07/2019

Anti-Ragging Committee(Squad)

Year: 2019-2020

Serial No.	Name of Committee members	Designation	'Representative of'
1	Dr. Sagar Chandra Bandyopadhyay	Teacher-In-Charge	
2	Mr. Tirtha Mondal	Assistant Professor	Faculty members
3	Mrs. Mousumi Kundu	Assistant Professor	Faculty members
4	Dr. Jotimay Bag	Assistant Professor	Faculty members
5	Mrs. Shampa Banerjee Ganguly	Lady attendant	Non -Teaching Staff
6	Mr. Shyamal Raut	Office Staff	Non -Teaching Staff

Banerjee

Teacher-In-charge

Deshabandhu Mahavidyalaya

Chittaranjan



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 08/07/2019

Students' Grievance Redressal Committee

Year: 2019-2020

Serial No.	Name of Committee members	Designation	Nominated as
1	Dr. Sagar Chandra Bandyopadhyay	Teacher-In-Charge	Chairperson
2	Mr. Apurbo Kumar Roy	Associate Professor of Philosophy	Member
3	Dr. Jotimay Bag	Assistant Professor of Hindi	Member
4	Dr. Mukul Kamle	Assistant Professor of Geography	Member
5	Dr. Koushik Kumar Hati	Assistant Professor of Economics	Member
6	General Secretary, Students' Union	Students' Representative	Member

Sanjeev

Teacher-In-charge

**Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan**



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 08/07/2019

Internal Complaints Committee

Year: 2019-2020

Serial No.	Name of Committee members	Designation	Nominated as
1	Sagarika Nandy	Assistant Professor of Mathematics	Presiding Officer
2	Sanchita Hazra	Assistant Professor of Political Science	Member
3	Mousumi Kundu	Assistant Professor of Chemistry	Member
4	Shampa Banerjee Ganguli	Lady Attendant (NTS)	Member
5	Falguni Karmakar	Social Worker	Member

Teacher-In-charge

**Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan**



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

CIRCULAR

Memo No.: DBM/IQAC/Com./03/2020-21

Date: 09/07/2020

For Teaching, Non-Teaching staff and Students' Council Members of the college

This order/circular is being circulated to inform the constitution of the Anti-Ragging Committee, Internal Complaints Committee and Students' Grievance Redressal Committee. These Committees have been formed in accordance with the UGC norms, Department of higher education Govt. of West Bengal/University.

Committees constituted by way of inclusion following members.

Anti-Ragging Committee

Year: 2020-2021

Serial No.	Name of Committee members	Designation	'Representative of'
1	Dr. Sagar Chandra Bandyopadhyay	Teacher-In-Charge	
2	IC, Chittaranjan PS	IC, Chittaranjan	Police administration
3	Mr. Abhoy Mondal	Sampadak, 'Prantabhumi'	Local media
4	Mr. Subhasish Khawash	General Secretary, 'Ujjiban'	NGO
5	Mr. Tirtha Mondal	Assistant Professor	Faculty members
6	Mrs. Mousumi Kundu	Assistant Professor	Faculty members
7	Dr. Jotimay Bag	Assistant Professor	Faculty members
8	Mr. Sagar Karmakar	-	Parents
9	Mr. Sunil Gorai	-	Parents
10	Rupali Hembram	Student, Dept. of Geography	Fresh students
11	Sourav Mondal	Student, Dept. of Economics	Fresh students
12	Avijit Sharma	Student, Dept. of Commerce	Senior students
13	Pratima Dutta	Student, Dept. of Bengali	Senior students
14	Rupam Ghosh	Student, Dept. of Political Science	Senior students
15	Mrs. Shampa Banerjee Ganguly	Lady attendant	Non -Teaching Staff
16	Mr. Shyamal Raut	Office Staff	Non -Teaching Staff

Sourajee
Teacher-in-charge
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 08/07/2020

Anti-Ragging Committee(Squad)

Year: 2020-2021

Serial No.	Name of Committee members	Designation	'Representative of'
1	Dr. Sagar Chandra Bandyopadhyay	Teacher-In-Charge	
2	Mr. Tirtha Mondal	Assistant Professor	Faculty members
3	Mrs. Mousumi Kundu	Assistant Professor	Faculty members
4	Dr. Jotimay Bag	Assistant Professor	Faculty members
5	Mrs. Shampa Banerjee Ganguly	Lady attendant	Non -Teaching Staff
6	Mr. Shyamal Raut	Office Staff	Non -Teaching Staff

Banerjee

Teacher-In-charge

**Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan**



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 09/07/2020

Students' Grievance Redressal Committee

Year: 2020-2021

Serial No.	Name of Committee members	Designation	Nominated as
1	Dr. Sagar Chandra Bandyopadhyay	Teacher-In-Charge	Chairperson
2	Mr. Apurbo Kumar Roy	Associate Professor of Philosophy	Member
3	Dr. Jotimay Bag	Assistant Professor of Hindi	Member
4	Dr. Mukul Kamle	Assistant Professor of Geography	Member
5	Dr. Koushik Kumar Hati	Assistant Professor of Economics	Member
6	General Secretary, Students' Union	Students' Representative	Member

Kanujee

Teacher-In-charge

Deshabandhu Mahavidyalaya

Chittaranjan



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 07/07/2020

Internal Complaints Committee

Year: 2020-2021

Serial No.	Name of Committee members	Designation	Nominated as
1	Sagarika Nandy	Assistant Professor of Mathematics	Presiding Officer
2	Sanchita Hazra	Assistant Professor of Political Science	Member
3	Mousumi Kundu	Assistant Professor of Chemistry	Member
4	Shampa Banerjee Ganguli	Lady Attendant (NTS)	Member
5	Falguni Karmakar	Social Worker	Member

Banerjee

Teacher-In-charge

**Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan**



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

CIRCULAR

Memo No.: DBM/IQAC/Com./04/2020-21

Date: 04/03/2021

For Teaching, Non-Teaching staff and Students' Council Members of the college

This order/circular is being circulated to inform the constitution of the Anti-Ragging Committee, Internal Complaints Committee and Students' Grievance Redressal Committee. These Committees have been formed in accordance with the UGC norms, Department of higher education Govt. of West Bengal/University.

Committees constituted by way of inclusion following members.

Anti-Ragging Committee

Year: 2020-2021(From 1st March, 2021 to 30th June, 2021)

Serial No.	Name of Committee members	Designation	'Representative of'
1	Dr. Tridib Santapa Kundu	Principal	
2	IC, Chittaranjan PS	IC, Chittaranjan	Police administration
3	Mr. Abhoy Mondal	Sampadak, 'Prantabhumi'	Local media
4	Mr. Subhasish Khawash	General Secretary, 'Ujjiban'	NGO
5	Mr. Tirtha Mondal	Assistant Professor	Faculty members
6	Mrs. Mousumi Kundu	Assistant Professor	Faculty members
7	Dr. Jotimay Bag	Assistant Professor	Faculty members
8	Mr. Sagar Karmakar	-	Parents
9	Mr. Sunil Gorai	-	Parents
10	Rupali Hembram	Student, Dept. of Geography	Fresh students
11	Sourav Mondal	Student, Dept. of Economics	Fresh students
12	Avijit Sharma	Student, Dept. of Commerce	Senior students
13	Pratima Dutta	Student, Dept. of Bengali	Senior students
14	Rupam Ghosh	Student, Dept. of Political Science	Senior students
15	Mrs. Shampa Banerjee Ganguly	Lady attendant	Non -Teaching Staff
16	Mr. Shyamal Raut	Office Staff	Non -Teaching Staff


(Tridib Santapa Kundu)
Principal
Principal
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 04/03/2021

Anti-Ragging Committee(Squad)

Year: 2020-2021(From 1st March, 2021 to 30th June, 2021)

Serial No.	Name of Committee members	Designation	'Representative of'
1	Dr. Tridib Santapa Kundu	Principal	
2	Mr. Tirtha Mondal	Assistant Professor	Faculty members
3	Mrs. Mousumi Kundu	Assistant Professor	Faculty members
4	Dr. Jotimay Bag	Assistant Professor	Faculty members
5	Mrs. Shampa Banerjee Ganguly	Lady attendant	Non -Teaching Staff
6	Mr. Shyamal Raut	Office Staff	Non -Teaching Staff


(Tridib Santapa Kundu)
Principal
Principal
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 04/03/2021

Students' Grievance Redressal Committee

Year: 2020-2021(From 1st March,2021 to 30th June,2021)

Serial No.	Name of Committee members	Designation	Nominated as
1	Dr.Tridib Santapa Kundu	Principal	Chairperson
2	Mr. Apurbo Kumar Roy	Associate Professor of Philosophy	Member
3	Dr. Jotimay Bag	Assistant Professor of Hindi	Member
4	Dr. Mukul Kamle	Assistant Professor of Geography	Member
5	Dr. Koushik Kumar Hati	Assistant Professor of Economics	Member
6	General Secretary, Students' Union	Students' Representative	Member


(Tridib Santapa Kundu)
Principal
Principal
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

CIRCULAR

Memo No.: DBM/IQAC/Com./04/2021-22

Date: 08/07/2021

For Teaching, Non-Teaching staff and Students' Council Members of the college


This order/circular is being circulated to inform the constitution of the Anti-Ragging Committee, Internal Complaints Committee and Students' Grievance Redressal Committee. These Committees have been formed in accordance with the UGC norms, Department of higher education Govt. of West Bengal/University.

Committees constituted by way of inclusion following members.

Anti-Ragging Committee

Year: 2021-2022

Serial No.	Name of Committee members	Designation	'Representative of'
1	Dr. Tridib Santapa Kundu	Principal	
2	IC, Chittaranjan PS	IC, Chittaranjan	Police administration
3	Mr. Abhoy Mondal	Sampadak, 'Prantabhumi'	Local media
4	Mr. Subhasish Khawash	General Secretary, 'Ujjiban'	NGO
5	Mr. Tirtha Mondal	Assistant Professor	Faculty members
6	Mrs. Mousumi Kundu	Assistant Professor	Faculty members
7	Dr. Jotimay Bag	Assistant Professor	Faculty members
8	Mr. Badal Mahato	-	Parents
9	Mr. Sagar Karmakar	-	Parents
10	Purnima Bauri	Student, Dept. of History	Fresh students
11	Sougata Ghosh	Student, Dept. of Physics	Fresh students
12	Sourav Mondal	Student, Dept. of Economics	Senior students
13	Shraboni Majumder	Student, Dept. of Economics	Senior students
14	Swarnava Karfa	Student, Dept. of Chemistry	Senior students
15	Mrs. Shampa Banerjee Ganguly	Lady attendant	Non -Teaching Staff
16	Mr. Shyamal Raut	Office Staff	Non -Teaching Staff


(Tridib Santapa Kundu)
Principal
Principal
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 08/07/2021

Anti-Ragging Committee(Squad)

Year: 2021-2022

Serial No.	Name of Committee members	Designation	'Representative of'
1	Dr. Tridib Santapa Kundu	Principal	
2	Mr. Tirtha Mondal	Assistant Professor	Faculty members
3	Mrs. Mousumi Kundu	Assistant Professor	Faculty members
4	Dr. Jotimay Bag	Assistant Professor	Faculty members
5	Mrs. Shampa Banerjee Ganguly	Lady attendant	Non -Teaching Staff
6	Mr. Shyamal Raut	Office Staff	Non -Teaching Staff


(Tridib Santapa Kundu)
Principal
Principal
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 07/07/2021

Students' Grievance Redressal Committee

Year: 2021-2022

Serial No.	Name of Committee members	Designation	Nominated as
1	Dr. Tridib Santapa Kundu	Principal	Chairperson
2	Mr. Apurbo Kumar Roy	Associate Professor of Philosophy	Member
3	Dr. Jotimay Bag	Assistant Professor of Hindi	Member
4	Dr. Mukul Kamle	Assistant Professor of Geography	Member
5	Dr. Koushik Kumar Hati	Assistant Professor of Economics	Member
6	General Secretary, Students' Union	Students' Representative	Member


(Tridib Santapa Kundu)
Principal
Principal
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 08/07/2021

Internal Complaints Committee

Year: 2021-2022

Serial No.	Name of Committee members	Designation	Nominated as
1	Sagarika Nandy	Assistant Professor of Mathematics	Presiding Officer
2	Sanchita Hazra	Assistant Professor of Political Science	Member
3	Mousumi Kundu	Assistant Professor of Chemistry	Member
4	Dr. Mukul Kamle	Assistant Professor of Geography	Member
5	Dr. Shrabani Basu	Assistant Professor of English	Member
6	Shampa Banerjee Ganguli	Lady Attendant (NTS)	Member
7	Falguni Karmakar	Social Worker	Member


(Tridib Santapa Kundu)
Principal
Principal
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

CIRCULAR

Memo No.: DBM/IQAC/Com./05/2022-23

Date: 09/07/2022

For Teaching, Non-Teaching staff and Students' Council Members of the college

This order/circular is being circulated to inform the constitution of the Anti-Ragging Committee, Internal Complaints Committee and Students' Grievance Redressal Committee. The Committees have been formed in accordance with the UGC norms, Department of higher education Govt. of West Bengal/University.

Committees constituted by way of inclusion following members.

Anti-Ragging Committee

Year: 2022-2023

Serial No.	Name of Committee members	Designation	'Representative of'
1	Dr. Tridib Santapa Kundu	Principal	
2	IC, Chittaranjan PS	IC, Chittaranjan	Police administration
3	Mr. Abhoy Mondal	Sampadak, 'Prantabhumi'	Local media
4	Mr. Subhasish Khawash	General Secretary, 'Ujjiban'	NGO
5	Mr. Tirtha Mondal	Assistant Professor	Faculty members
6	Mrs. Mousumi Kundu	Assistant Professor	Faculty members
7	Dr. Jotimay Bag	Assistant Professor	Faculty members
8	Mr. Nirmal Paul	-	Parents
9	Mr. Sagar Karmakar	-	Parents
10	Deepsikha	Student, Dept. of Political Science	Fresh students
11	Avijit Rakshit	Student, Dept. of English	Fresh students
12	Shilpi Dutta	Student, Dept. of Philosophy	Senior students
13	Sourav Mondal	Student, Dept. of Economics	Senior students
14	Rupali Hembram	Student, Dept. of Geography	Senior students
15	Mrs. Shampa Banerjee Ganguly	Lady attendant	Non -Teaching Staff
16	Mr. Shyamal Raut	Office Staff	Non -Teaching Staff


(Tridib Santapa Kundu)
Principal
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 06/07/2022

Anti-Ragging Committee(Squad)

Year: 2022-2023

Serial No.	Name of Committee members	Designation	'Representative of'
1	Dr. Tridib Santapa Kundu	Principal	
2	Mr. Tirtha Mondal	Assistant Professor	Faculty members
3	Mrs. Mousumi Kundu	Assistant Professor	Faculty members
4	Dr. Jotimay Bag	Assistant Professor	Faculty members
5	Mrs. Shampa Banerjee Ganguly	Lady attendant	Non -Teaching Staff
6	Mr. Shyamal Raut	Office Staff	Non -Teaching Staff


(Tridib Santapa Kundu)
Principal
Principal
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 08/07/2022

Students' Grievance Redressal Committee

Year: 2022-2023

Serial No.	Name of Committee members	Designation	Nominated as
1	Dr. Tridib Santapa Kundu	Principal	Chairperson
2	Dr. Apurbo Kumar Roy	Associate Professor of Philosophy	Member
3	Dr. Jotimay Bag	Assistant Professor of Hindi	Member
4	Dr. Mukul Kamle	Assistant Professor of Geography	Member
5	Dr. Koushik Kumar Hati	Assistant Professor of Economics	Member
6	General Secretary, Students' Union	Students' Representative	Member


(Tridib Santapa Kundu)
Principal
Principal
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 09/07/2022

Internal Complaints Committee

Year: 2022-2023

Serial No.	Name of Committee members	Designation	Nominated as
1	Sagarika Nandy	Assistant Professor of Mathematics	Presiding Officer
2	Sanchita Hazra	Assistant Professor of Political Science	Member
3	Mousumi Kundu	Assistant Professor of Geography	Member
4	Dr. Mukul Kamle	Assistant Professor of Geography	Member
5	Dr. Shrabani Basu	Assistant Professor of English	Member
6	Shampa Banerjee Ganguli	Lady Attendant (NTS)	Member
7	Falguni Karmakar	Social Worker	Member
8	Mrs. Rama Saha Som	Legal Advisor	Member


(Tridib Santapa Kundu)
Principal
Principal
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 10.05.2024

Internal Complaints Committee (ICC)

(RELATED TO GENDER AWARENESS, SEXUAL HARASSMENT AND GENDER BASED VIOLENCE AT INSTITUTIONS.)

OVERVIEW AND OBJECTIVES:

In pursuance of the direction of the Honorable Supreme Court in VISHAKA and ORS.v. STATE OF RAJASTHAN and ORS. (JT 1997(7) SC 384), every educational Institute, including Deshabandhu Mahavidyalaya, Chittaranjan had constituted various standing committees to effectively deal with cases of violence against female students, staff, faculty and campus residents. Presently, this cell functions as the "Internal Complaints Committee" as designated under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

The committee undertakes inquiries, adhering to the principles of Natural Justice, with regard to complaints of sexual harassment from aggrieved women staff and students (as defined under the Act, 2013). The complaint is kept totally confidential, and adequate protection is provided to the complainant, whenever necessary. Necessary recommendations are provided to the College Management on the basis of the findings of the inquiry. The Committee also undertakes to sensitize students on issues regarding women's health, gender empowerment, harassment, gender based violence, patriarchy etc.

[Ordinance-XV D for Sexual Harassment - Appendix-A](#)

[UGC \(Prevention, Prohibition & Redressal of Sexual Harassment of Women employees and students in higher education institutions\) Regulations, 2015](#)

Website Link: <https://dbmcrj.ac.in/ICC/>


(Tridib Santapa Kundu)
Principal
Principal
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan

Phone: 0341-2525449
FAX No : 0341-2525449

Website: www.dbmcrj.ac.in
Email: principal@dbmcrj.ac.in



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 10.05.2024

The screenshot shows a web browser window with the URL dbmcrj.ac.in/students'-grievance/. The page header includes the college logo and name, along with navigation links: Home, The College, Administration, Academics, Admission, Library, Events, and Students' Corner. The main heading is "Students' Grievance Redressal Committee". Below it, the text describes the "Students' Grievance Redressal Mechanism", stating that the policy is designed to establish a mechanism for students to voice concerns and challenges. It mentions that the college is equipped with a grievance redressal committee to facilitate this process. The text also lists three committees: Anti-Ragging Committee, Students' Grievance Redressal Committee, and Women's Cell.

Website Link: <https://dbmcrj.ac.in/students'-grievance/>


(Tridib Santapa Kundu)
Principal
Principal
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 10.05.2024

NOTICES

Important Notices

- Exam Notice
UG 3rd Semester Exam Schedule
[Download View](#)
- General Notice
Anti Ragging Declaration
[Download View](#)
- Seminar Notice
Two Day International Seminar
[Download View](#)

FEEDBACK

[Student Satisfaction Survey.](#)

Website Link: <https://dbmcrj.ac.in/anti-ragging/>

Anti-Ragging Committee

Deshabandhu Mahavidyalaya, P.O.- Chittaranjan, Dt- Paschim Bardhaman (W.B.), quite in adherence to its consistent policy of maintenance and promotion of students' interest, takes every possible measure from time to time. Anti -ragging cell is one such positive step in terms of the norms and guidelines set by the University Grants Commission. (Vide UGC Notification ref.no.F.No.14-4/2012(CPP-II) date 07 Dec,2018) The cell has been established with a view to addressing grievances, if any, on the part of the students and resolving them by executing internal mechanism. This facility is an assistance for the College administration.

2023-24

Anti-Ragging Committee Members

Name	Designation	Representative of
Dr. Tridib Santapa Kundu	Principal	-----
Mr. Raju Swarnakar	OC, Chittaranjan PS	Police administration
Mr. Abhoy Mondal	Sampadak, 'Prantabhumi'	Local media
Mr. Subhasish Khawash	General Secretary, 'Ujiban'	NGO
Prof. Tirtha Mondal	Assistant Professor	Faculty members


(Tridib Santapa Kundu)
Principal
Principal
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan

Phone: 0341-2525449
FAX No : 0341-2525449

Website: www.dbmcrj.ac.in
Email: principal@dbmcrj.ac.in



DESHABANDHU MAHAVIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

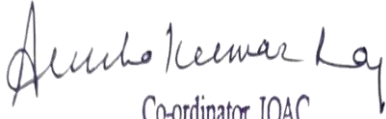
P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331


Date: 06/07/2019

Anti Ragging Committee

Annual Report 2018-2019

No incidents of ragging cases were reported during the year 2018-2019. The situation of the college was under control with well-maintained discipline.


Co-ordinator, IQAC
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan


Teacher-In-charge
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHAVIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

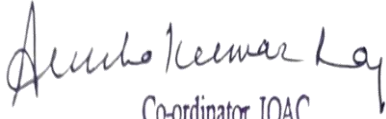
P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331


Date:07/07/2020

Anti Ragging Committee

Annual Report 2019-2020

No incidents of ragging cases were reported during the year 2019-2020. The situation of the college was under control with well-maintained discipline.


Co-ordinator, IQAC
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan


Teacher-In-charge
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHAVIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

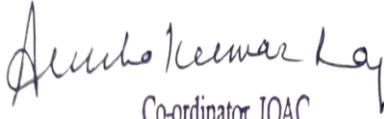
P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 08/07/2021

Anti Ragging Committee

Annual Report 2020-2021

Due to Covid-19 the college was closed of the period 2020-2021. No incidents of ragging cases were reported during the year 2020-2021.


Co-ordinator, IQAC
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan


(Tridib Santapa Kundu)
Principal
Principal
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHAVIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

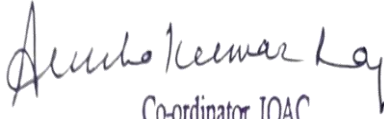
P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331


Date: 08/07/2022

Anti Ragging Committee

Annual Report 2021-2022

No incidents of ragging cases were reported during the year 2021-2022. The situation of the college was under control with well-maintained discipline.


Co-ordinator, IQAC
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan


(Tridib Santapa Kundu)
Principal
Principal
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHAVIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

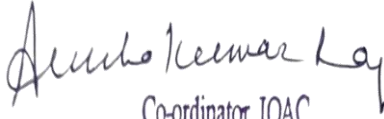
P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 12/07/2023

Anti Ragging Committee

Annual Report 2022-2023

No incidents of ragging cases were reported during the year 2022-2023. The situation of the college was under control with well-maintained discipline.


Co-ordinator, IQAC
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan


(Tridib Santapa Kundu)
Principal
Principal
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHAVIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

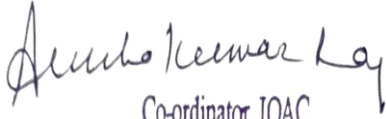
P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331


Date: 09/07/2019

Students' Grievance Redressal Committee

Annual Report 2018-2019

The Students' Grievance Redressal Committee received five complaints from the students during the year 2018-2019 and redressed the same in the above-mentioned period.


Co-ordinator, IQAC
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan


Teacher-In-charge
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

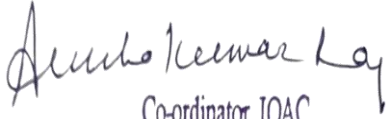
P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331


Date: 08/07/2020

Students' Grievance Redressal Committee

Annual Report 2019-2020

The Students' Grievance Redressal Committee received four complaints from the students during the year 2019-2020 and redressed the same in the above-mentioned period.


Co-ordinator, IQAC
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan


Teacher-In-charge
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHAVIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

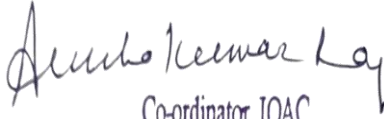
P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 11/07/2021

Students' Grievance Redressal Committee

Annual Report 2020-2021

Due to Covid-19 the college was closed during the year 2020-2021. The Students' Grievance Redressal Committee did not receive any formal complaints from students during the year 2020-2021.


Co-ordinator, IQAC
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan


(Tridib Santapa Kundu)
Principal
Principal
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHAVIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

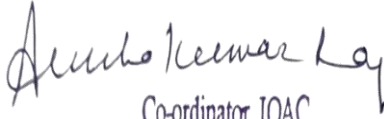
P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 08/07/2022

Students' Grievance Redressal Committee

Annual Report 2021-2022

The Students' Grievance Redressal Committee did not receive any formal complaints from students during the year 2021-2022.


Co-ordinator, IQAC
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan


(Tridib Santapa Kundu)
Principal
Principal
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHAVIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

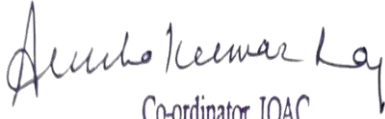
P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 12/07/2023

Students' Grievance Redressal Committee

Annual Report 2022-2023

The Students' Grievance Redressal Committee received six complaints from the students during the year 2022-2023 and redressed the same in the above-mentioned period.


Co-ordinator, IQAC
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan


(Tridib Santapa Kundu)
Principal
Principal
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHAVIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

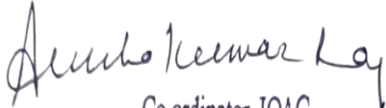
P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 12/07/2019

Complaints/ Grievances received under Anti-Ragging Committee, Internal Complaints Committee and Students' Grievance Redressal Committee

Year: 2018-2019

Serial No.	Name of the Statutory Committee	Complaints/Grievances Received	Complaints/Grievances Redressed
1	Anti-Ragging Committee	NIL	NIL
2	Internal Complaints Committee	NIL	NIL
3	Students' Grievance Redressal Committee	05	05


Co-ordinator, IQAC
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan


Teacher-In-charge
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHAVIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

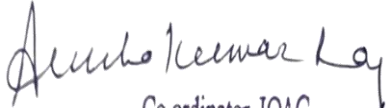
P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

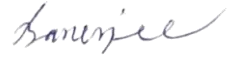
Date: 13/07/2020

Complaints/ Grievances received under Anti-Ragging Committee, Internal Complaints Committee and Students' Grievance Redressal Committee

Year: 2019-2020

Serial No.	Name of the Statutory Committee	Complaints/Grievances Received	Complaints/Grievances Redressed
1	Anti-Ragging Committee	NIL	NIL
2	Internal Complaints Committee	NIL	NIL
3	Students' Grievance Redressal Committee	04	04


Co-ordinator, IQAC
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan


Teacher-In-charge
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHAVIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

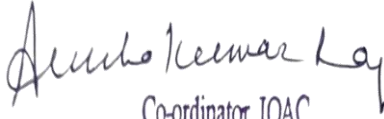
P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 14/07/2021

Complaints/ Grievances received under Anti-Ragging Committee, Internal Complaints Committee and Students' Grievance Redressal Committee

Year: 2020-2021

Serial No.	Name of the Statutory Committee	Complaints/Grievances Received	Complaints/Grievances Redressed
1	Anti-Ragging Committee	NIL	NIL
2	Internal Complaints Committee	NIL	NIL
3	Students' Grievance Redressal Committee	NIL	NIL


Co-ordinator, IQAC
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan


(Tridib Santapa Kundu)
Principal
Principal
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHAVIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

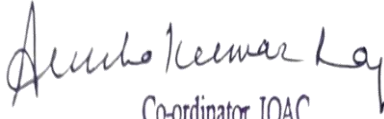
P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 18/07/2022

Complaints/ Grievances received under Anti-Ragging Committee, Internal Complaints Committee and Students' Grievance Redressal Committee

Year: 2021-2022

Serial No.	Name of the Statutory Committee	Complaints/Grievances Received	Complaints/Grievances Redressed
1	Anti-Ragging Committee	NIL	NIL
2	Internal Complaints Committee	NIL	NIL
3	Students' Grievance Redressal Committee	NIL	NIL


Co-ordinator, IQAC
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan


(Tridib Santapa Kundu)
Principal
Principal
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHAVIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

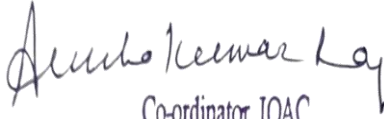
P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 14/07/2023

Complaints/ Grievances received under Anti-Ragging Committee, Internal Complaints Committee and Student's Grievance Redressal Committee

Year: 2022-2023

Serial No.	Name of the Statutory Committee	Complaints/Grievances Received	Complaints/Grievances Redressed
1	Anti-Ragging Committee	NIL	NIL
2	Internal Complaints Committee	02	02
3	Students' Grievance Redressal Committee	06	06


Co-ordinator, IQAC
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan


(Tridib Santapa Kundu)
Principal
Principal
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan

Annual Report 2018-2019 (01/07/2018 to 30/06/2019)

Internal Complaints Committee (ICC)

Report by the Presiding Officer Smt. Sagarika Nandy Date : 02,08,19

As per University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) regulations, 2015, the Internal Complaints Committee has been constituted in Deshabandhu Mahavidyalaya, Chittaranjan.

The members of the current committee are as follows.

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Mrs. Sagarika Nandy, Assistant Professor of Mathematics | Presiding Officer |
| 2. Mrs. Sanchita Hazra, Assistant Professor of Political Science | Member |
| 3. Mrs. Mousumi Kundu, Assistant Professor of Chemistry | Member |
| 4. Mrs. Shampa Banerjee Ganguly, Lady attendant | Member |
| 5. Mrs. Falguni Karmakar, Social Worker | Member |

Cases/Issues

During the session 2018-2019, no cases received regarding sexual harassment of women employees and students in the institution.

Activities

The ICC of the institute has performed different activities to create a secure physical and social environment to prevent any act of sexual harassment.

Received
Sansari
Teacher-In-charge
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan

Sagarika Nandy
Presiding Officer
Presiding Officer
Internal Complaints Committee
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan
Paschim Bardhaman-713331
West Bengal

Annual Report 2019-2020 (01/07/2019 to 30/06/2020)

Internal Complaints Committee (ICC)

Report by the Presiding Officer Smt. Sagarika Nandy Date : 06.07, 2020

As per University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) regulations, 2015, the Internal Complaints Committee has been constituted in Deshabandhu Mahavidyalaya, Chittaranjan.

The members of the current committee are as follows.

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Mrs. Sagarika Nandy, Assistant Professor of Mathematics | Presiding Officer |
| 2. Mrs. Sanchita Hazra, Assistant Professor of Political Science | Member |
| 3. Mrs. Mousumi Kundu, Assistant Professor of Chemistry | Member |
| 4. Mrs. Shampa Banerjee Ganguly, Lady attendant | Member |
| 5. Mrs. Falguni Karmakar, Social Worker | Member |

Cases/Issues

During the session 2019-2020, no cases received regarding sexual harassment of women employees and students in the institution.

Activities

The ICC of the institute has performed different activities to raise awareness on sexual harassment in the campus.

Received
Sanku
Teacher-in-charge
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan

Sagarika Nandy
Presiding Officer

Presiding Officer
Internal Complaints Committee
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan
Paschim Bardhaman-713331
West Bengal

Annual Report 2020-2021 (01/07/2020 to 30/06/2021)

Internal Complaints Committee (ICC)

Report by the Presiding Officer Smt. Sagarika Nandy Date : 03.08.21

As per University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) regulations, 2015, the Internal Complaints Committee has been constituted in Deshabandhu Mahavidyalaya, Chittaranjan.

The members of the current committee are as follows.

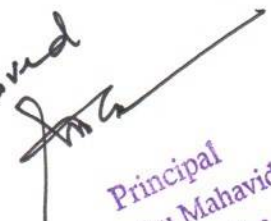
- | | |
|--|-------------------|
| 1. Mrs. Sagarika Nandy, Assistant Professor of Mathematics | Presiding Officer |
| 2. Mrs. Sanchita Hazra, Assistant Professor of Political Science | Member |
| 3. Mrs. Mousumi Kundu, Assistant Professor of Chemistry | Member |
| 4. Mrs. Shampa Banerjee Ganguly, Lady attendant | Member |
| 5. Mrs. Falguni Karmakar, Social Worker | Member |


Cases/Issues

During the session 2020-2021, no cases received regarding sexual harassment of women employees and students in the institution.

Activities

The ICC of the institute has performed different activities to raise awareness on sexual harassment in the campus.

Received

Principal
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan


Sagarika Nandy
Presiding Officer
Presiding Officer
Internal Complaints Committee
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan
Paschim Bardhaman-713331
West Bengal

Annual Report 2021-2022 (01/07/2021 to 30/06/2022)

Internal Complaints Committee (ICC)

Report by the Presiding Officer Smt. Sagarika Nandy Date: 10.07.2022

As per University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) regulations, 2015, the Internal Complaints Committee has been reconstituted in Deshabandhu Mahavidyalaya, Chittaranjan.

The members of the current committee are as follows.

1. Mrs. Sagarika Nandy, Assistant Professor of Mathematics	Presiding Officer
2. Mrs. Sanchita Hazra, Assistant Professor of Political Science	Member
3. Mrs. Mousumi Kundu, Assistant Professor of Chemistry	Member
4. Dr. Mukul Kamle, Assistant Professor of Geography	Member
5. Dr. Shrabani Basu, Assistant Professor of English	Member
6. Mrs. Shampa Banerjee Ganguly, Lady attendant	Member
7. Mrs. Falguni Karmakar, Social Worker	Member

I Cases/Issues

During the session 2021-2022, no cases received regarding sexual harassment of women employees and students in the institution.

II Activities

1.

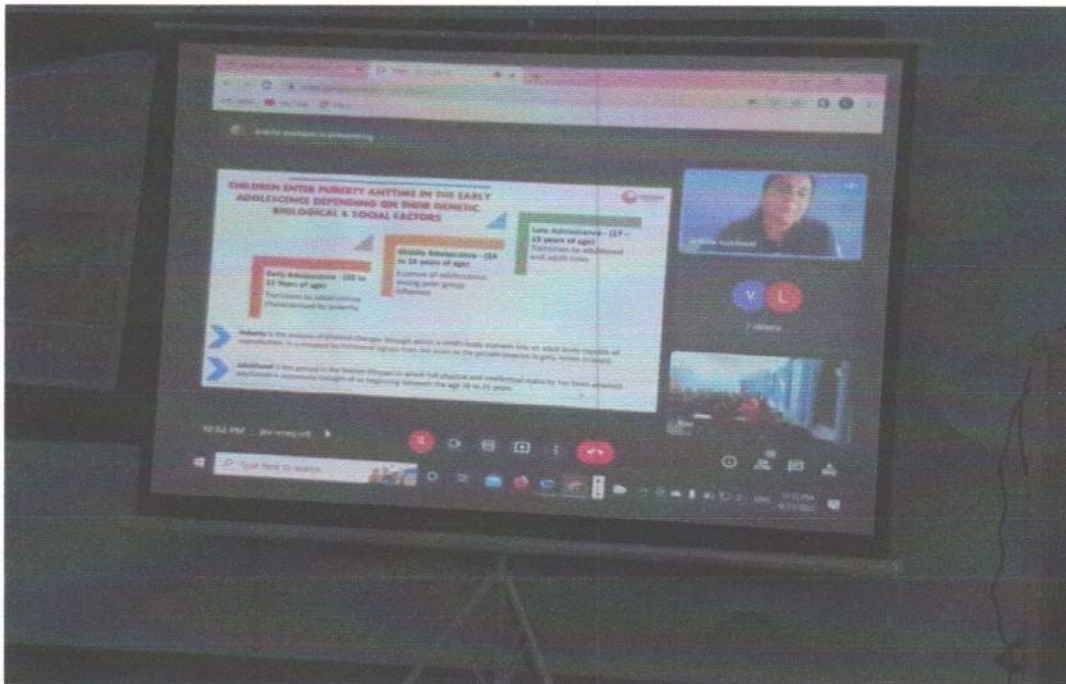
Internal Complaints committee in collaboration with IQAC celebrated International Women's Day on 8th March 2022. In compliance with the essence women's day objective of that year, the Institute organized awareness campaign on gender parity and "breaking the bias".

The chief speaker of the day was Dr. Amrita Banerjee, Assistant Professor of Political Science, Bidhan Chandra College. Along with Dr. Banerjee, Salanpur Panchayat Samiti Chairperson Ms. Falguni Karmakar and Deputy Chairperson Md. Armaan addressed the assembled audience. Eminent teacher and alumnus of the College Ms. Mahua Bardhan and the presiding personnel of the local Self-Help group Ms. Pushpa Das also delivered a few words of awareness and encouragement.



2.

On June 23, 2022 Deshabandhu Mahavidyalaya, Chittaranjan has hosted an awareness seminar on "Menstrual Health and Hygiene." The session was organized under the aegis of the Internal Quality Assurance Cell and the Internal Complaints Committee. Hosted online this program was a collaborative effort with Unicharm India Ltd. Ms. Ankita Sukhwal, a member of the collaborating organization addressed the female students and staff members of the College. Ms. Sukhwal was ably assisted by Ms. Vidya R. of the Global Hunt foundation, an associate of Unicharm. The event was eagerly participated by the female population of the College.



Beside the aforementioned activities, Internal Complaint Committee, Deshabandhu Mahavidyalaya, Chittaranjan continuously give efforts to maintain the harmony in the institute.

Received
[Signature]
 Principal
 Deshabandhu Mahavidyalaya
 Chittaranjan

Sagarika Nandy
Presiding Officer
 Presiding Officer
 Internal Complaints Committee
 Deshabandhu Mahavidyalaya
 Chittaranjan
 Paschim Bardhaman-713331
 West Bengal

Annual Report 2022-2023 (01/07/2022 to 30/06/2023)

Internal Complaints Committee (ICC)

Report by the Presiding Officer Smt. Sagarika Nandy Date : 12, 08, 2023

As per University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) regulations, 2015, the Internal Complaints Committee has been reconstituted in Deshabandhu Mahavidyalaya, Chittaranjan.

The members of the current committee are as follows.

1. Mrs. Sagarika Nandy, Assistant Professor of Mathematics	Presiding Officer
2. Mrs. Sanchita Hazra, Assistant Professor of Political Science	Member
3. Mrs. Mousumi Kundu, Assistant Professor of Chemistry	Member
4. Dr. Mukul Kamle, Assistant Professor of Geography	Member
5. Dr. Shrabani Basu, Assistant Professor of English	Member
6. Mrs. Shampa Banerjee Ganguly, Lady attendant	Member
7. Mrs. Falguni Karmakar, Social Worker	Member
8. Mrs. Rama Saha Som, Legal Advisor	Member

I Cases/Issues

During the session 2022-2023, two complaints were lodged and resolved. The detailed reports were submitted to the competent authority. At present there are no pending cases.

II Activities

On March 24, 2023, Internal Complaints Committee in collaboration with Internal Quality Assurance Cell observed International Women's Day. The International Women's Day observance was to be postponed due to University Examination. The theme of the year was "**DigitALL: Innovation and technology for gender equality**". The programme included a discussion on the theme of this year "DigitALL: Innovation and technology on gender inequality" and some cultural performances. The chief speaker of the day was Prof. Gopa Samanta, Department of Geography, Burdwan University. She had query on whether the student present in the hall-both male and female had any problem due to their gender status. Prof. Samanta in her discussion dealt with the issues of gender inequality at various level of our society. The discussion, an enlightening one, was followed by a question-answer session, which was a quite enriching for the audience.



Beside the aforementioned activities, Internal Complaint Committee, Deshabandhu Mahavidyalaya, Chittaranjan continuously give efforts to maintain the harmony in the institute.

Revised
[Signature]
 Principal
 Deshabandhu Mahavidyalaya
 Chittaranjan

Sagarika Nandy
Presiding Officer
 Presiding Officer
 Internal Complaints Committee
 Deshabandhu Mahavidyalaya
 Chittaranjan
 Paschim Bardhaman-713331
 West Bengal



DESHABANDHU MAHAVIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date:18/05/2024

**Documents of Clarification 3 & 4 of
5.1.4: Minutes of the meetings of
Grievance Committee
(Internal Complaints Committee,
Anti-Ragging Committee & Students'
Grievance Redressal Committee)**


(Tridib Santapa Kundu)
Principal
Principal
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan

Meeting Resolution Book

মিটিং রেজল্যুশন বই
Anti-Ragging Commu

Year :

SREEMA TRADERS, 45 Benialola Lane, Kolkata - 9, Ph.-2219 3865

মিটিং রেজল্যুশন বহি

MEETING RESOLUTION BOOK

মিটিং নং / Meeting No.	
তারিখ / Date	24.08.18.

উপস্থিত সভ্যগণের নাম
NAME OF MEMBERS PRESENT

স্থান / Place	Seminar Hall
সময় / Time	1:30 Pm

- ১। 1. Banerjee
- ২। 2. Tirtha Mondal
- ৩। 3. Mombumi Kundu
- ৪। 4. Jotimay Bay
- ৫। 5. Shampu Bay
- ৬। 6.
- ৭। 7. Shyamalout

- ৮। 8. suman munn
- ৯। 9. Avik Bose
- ১০। 10. Jintan Bhowri
- ১১। 11. Satati Rakshit
- ১২। 12.
- ১৩। 13.
- ১৪। 14.

- ১৫। 15.
- ১৬। 16.
- ১৭। 17.
- ১৮। 18.
- ১৯। 19.
- ২০। 20.
- ২১। 21.

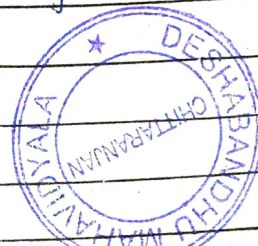
রেজল্যুশন / Resolution Adopted

নং / No.

AS per the advise of the chairman meeting of Anti-Ragging Committee organized on 24.08.2018 at 1:30 Pm in Seminar Hall to discuss various issues pertaining to the department.

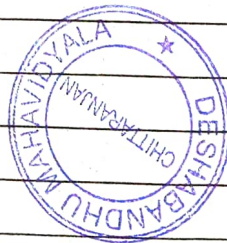
Agenda:

1. Discussion on guidelines of UGC regulations on curbing the menace of Ragging.
2. To workout the modality of Preventive measure.
3. Setting up of Anti-Ragging monitoring cell.
4. Anti-Ragging Campaigning for ragging free campus.
5. Display posters, hoarding, notice at the college campus as instructed under UGC guidelines.
6. Process of redressal of complaints of Ragging.
7. Miscellaneous.



The minutes of the meeting of committee given below:

1. The members of the Committee confirmed of Proceeding of the last meeting held on 22.03.18.
2. To make instruct regarding objectives, Regulations, Punishable ingredients of Ragging and Punishments etc. as conferred by UGC Regulations.
3. To conduct sensitization of Programs seminars Pertaining to Anti-Ragging at the college for all students.
4. To take measures for Prohibition and Prevention of Ragging at the institution level by setting up of Anti-Ragging monitoring cell consisting of juniore and senior students.
5. To make posters and hoardings, notice to be displayed at college campus.
6. There is no single matter complaint from the students, which reflects a ragging free campus.



মিটিং রেজল্যুশন বহি

MEETING RESOLUTION BOOK

মিটিং নং / Meeting No.	
তারিখ / Date	20.02.19.

উপস্থিত সভ্যগণের নাম
NAME OF MEMBERS PRESENT

স্থান / Place	Staff Room
সময় / Time	1.30 PM

- ১। ১. Samir
- ২। ২. Tirtha Mondal
- ৩। ৩.
- ৪। ৪. Mousumi Kundu
- ৫। ৫. Potimay Bay
- ৬। ৬. Shampa Bandyopadhyay
- ৭। ৭. Shyamoli Kundu

- ৮। ৮. Suraj Kumar
- ৯। ৯. Avik Bose
- ১০। ১০. Jiten Bhowmik
- ১১। ১১. Satyaki Rakshit
- ১২। ১২.
- ১৩। ১৩.
- ১৪। ১৪.

- ১৫। ১৫.
- ১৬। ১৬.
- ১৭। ১৭.
- ১৮। ১৮.
- ১৯। ১৯.
- ২০। ২০.
- ২১। ২১.

নং / No.	রেজল্যুশন / Resolution Adopted
	As per the advise of the chairman meeting of Anti-Ragging committee held on 20.02.2019 at 1.30 PM in staff room to discuss various issues pertaining to the department.
	Agenda:
	① Confirmation of the minutes of the previous meeting held on
	② Anti-Ragging awareness cum workshops with first semester students.
	③ online anti-ragging affidavit to be filled in by students with parents undertaking.
	④ The college has taken all measure to take care of students with regard to ragging.
	⑤ Process of redressal of complaints of ragging.
	⑥ To make posters and hoarding, notices to be displayed at the college premises.
	⑦ Miscellaneous.



The minutes of the meeting of committee discussed the following points:

1. The members of the committee confirmed of Proceeding of the last meeting held on 29.08.2018.
2. The committee decided to arranged anti-ragging awareness cum workshops with First semester students.
3. To check and verify the online anti-ragging affidavit to be filled in by students with Parents undertaking of institutional status.
4. To discuss on the Preventive measures to be adopted by the ^{college} authority with to ill-effects of ragging.
5. The committee decided to take appropriate action of redressal of complaints about the issues (if any) related to ragging of the students in college campus.
6. To displayed the posters and notices in related to anti-ragging both within and outside the college campus.



মিটিং রেজল্যুশন বহি

MEETING RESOLUTION BOOK

মিটিং নং / Meeting No.	
তারিখ / Date	19.09.19

উপস্থিত সভ্যগণের নাম
NAME OF MEMBERS PRESENT

স্থান / Place	Staff Room
সময় / Time	1:30 PM

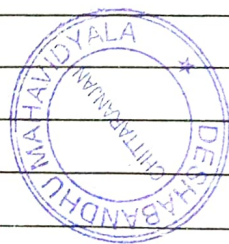
১। 1. Samirice	৮। 8. Swarnava Karfa	১৫। 15.
২। 2. Tirtha Mondal	৯। 9. Avin Bose	১৬। 16.
৩। 3. Jotimay Bag	১০। 10.	১৭। 17.
৪। 4. Mousumi Runder	১১। 11. Krishna Singh	১৮। 18.
৫। 5. Shambor Bag	১২। 12.	১৯। 19.
৬। 6. Sunil Mondal	১৩। 13.	২০। 20.
৭। 7. Shyamal Lant	১৪। 14.	২১। 21.

নং / No.	রেজল্যুশন / Resolution Adopted
	ASPER the advise of the chairman meeting of Anti-Ragging Committee held on 19.09.2019 at 1:30 PM in staff room to discuss various issues pertaining to the department.
	Agenda:
	① Confirmed the Proceeding of the last meeting held on
	2. Discuss on guidelines of UGC Regulations on curbing the menace of Ragging.
	3. Anti-Ragging campaigning for ragging free campus.
	4. TO workout the measures for prohibition and prevention of Ragging at college campus.
	5. Setting up Anti-Ragging monitoring cell.
	6. Display posters, handing, notices at the college campus as instructed under UGC guidelines.
	⑦ Miscellaneous.



The minutes of the meeting of Anti-ragging committee given below:

1. The members of the committee confirmed of Proceeding of the previous meeting held on 20.02.2019.
2. To make instatue regarding objectives, Regulations, Punishable ingredients of Ragging and Punishments etc. as confer-
-red by UGC Regulations.
3. To organise a Seminar cum Workshops Pertaining to Anti-Ragging at the college for all students.
4. To take measures for Prohibition and Prevention of Ragging in ^{the} college campus.
5. To setting up Anti Ragging monitoring cell consisting of ^{both} junior and Senior students.
6. To make Posters and hoarding, notices to be displayed at college premises.



মিটিং রেজল্যুশন বই

MEETING RESOLUTION BOOK

মিটিং নং / Meeting No.	
তারিখ / Date	11.03.20

উপস্থিত সভ্যগণের নাম
NAME OF MEMBERS PRESENT

স্থান / Place	Seminar Hall
সময় / Time	2:30 Pm

- ১। ১. *Zanvirul*
- ২। ২. *Tintha Mondol*
- ৩। ৩. *Mousumi Kundu*
- ৪। ৪. *Botimay Bag*
- ৫। ৫. *Shampa Das*
- ৬। ৬. *Sunil Mondol*
- ৭। ৭. *Shyama Kant*

- ৮। ৮. *Swarna Karfa*
- ৯। ৯. *Arif Boru*
- ১০। ১০.
- ১১। ১১. *Krishna Singh*
- ১২। ১২.
- ১৩। ১৩.
- ১৪। ১৪.

- ১৫। ১৫.
- ১৬। ১৬.
- ১৭। ১৭.
- ১৮। ১৮.
- ১৯। ১৯.
- ২০। ২০.
- ২১। ২১.

নং / No.

রেজল্যুশন / Resolution Adopted

As per the advise of the chairman meeting of anti-ragging committee held on 11.03.2020 at 2.30 Pm in seminar hall to discuss various issues regarding to the department.

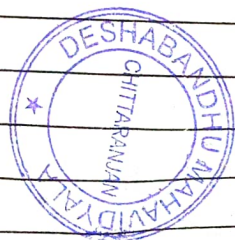
Agenda:

1. Confirmation of the proceeding of the previous meeting held on
2. Discuss on guidelines of UGC regulations on curbing the menace of ragging.
3. To conduct Anti-Ragging awareness cum workshops with first semester students.
4. online Anti-Ragging affidavit to be filled in by students with regard to ragging.
5. Process of redressal of complaints of ragging.
6. Miscellaneous.



The minutes of the meeting of Anti-Ragging Committee given below:-

1. The members of the Committee confirmed of Proceeding of the last meeting held on 19.09.2019.
2. To make instruct regarding objectives, Regulations, Punishable ingredients of Ragging and Punishments etc as conferenced by UGC Regulations.
3. The committee decides to arranged Anti-Ragging awareness cum workshops with first semester students.
4. The institutional states of the online Anti-Ragging affidavit to be filled in by students with Parents undertaking.
5. The committee also decides to take appropriate action of redressal of complaints about the issues (if any) related to ragging of the students in College campus.
6. To displayed the posters and notices in related to Anti-Ragging both within and outside the College campus.



মিটিং রেজল্যুশন বহি

MEETING RESOLUTION BOOK

মিটিং নং / Meeting No.	
তারিখ / Date	09.08.22

উপস্থিত সভ্যগণের নাম
NAME OF MEMBERS PRESENT

স্থান / Place	Seminar Hall
সময় / Time	2:30 Pm

- ১। 1. Tridib Sestapa Kundu
- ২। 2.
- ৩। 3. Jotimay Bag
- ৪। 4. Mousumi Kunder
- ৫। 5. Tirtha Mondal
- ৬। 6. Shampa Banerjee (Ganguly)
- ৭। 7. Shyamal Rout

- ৮। 8.
- ৯। 9. Shilpi Dutta
- ১০। 10. Rupali Hembram
- ১১। 11. Nirma Paul
- ১২। 12.
- ১৩। 13.
- ১৪। 14.

- ১৫। 15.
- ১৬। 16.
- ১৭। 17.
- ১৮। 18.
- ১৯। 19.
- ২০। 20.
- ২১। 21.

নং / No.

রেজল্যুশন / Resolution Adopted

As Per the advise of the chairman meeting of Anti-Ragging committee held on 09.08.2022, at 2: Pm in Seminar Hall to discuss the various issues Pertaining to the department.

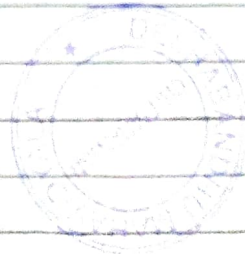
Agenda:

- ① Confirmed the minutes of last meeting held on
2. Discuss on guidelines of UGC regulations on curbing the menace of Ragging.
3. Anti-Ragging campaigning for ragging free campus.
4. To workout the measures for Prohibition and prevention of Ragging at college campus.
5. Setting up Anti-Ragging monitoring cell.
- ⑥ Display posters, hoarding, notices at the college campus as instructed under UGC guidelines.
7. Miscellaneous.



The minutes of meeting of Anti-Ragging committee given below -

1. The members of the committee confirmed of Proceeding of the last meeting held on 11.03.2020
2. To make instruct regarding objectives, Regulations, Punishable ingredients of Ragging and Punishments etc. as conferred by UGC Regulations.
3. To organise a Seminare cum Workshops Pertaining to Anti-Ragging at the college for all students.
4. To take measures for Prohibition and Prevention of Ragging in the college campus.
5. To setting up Anti-Ragging monitoring cell consisting of both juniore and seniore students.
6. To make Posters and Hoarding, notices to displayed at college Premises.



মিটিং রেজল্যুশন বহি

MEETING RESOLUTION BOOK

মিটিং নং / Meeting No.	
তারিখ / Date	05.04.22

উপস্থিত সভ্যগণের নাম
NAME OF MEMBERS PRESENT

স্থান / Place	Seminar Hall
সময় / Time	2:30pm

১। 1. Tridib Sastha Kundu	৮। 8.	১৫। 15.
২। 2. Jotimay Bagg	৯। 9. Shilpi Datta	১৬। 16.
৩। 3. Mousumi Kundu	১০। 10. Rupali Hembzom.	১৭। 17.
৪। 4. Tirtha Mondal	১১। 11. Nirmal Paul	১৮। 18.
৫। 5. Shampa Bajora (pajur)	১২। 12.	১৯। 19.
৬। 6. Shyama Rout.	১৩। 13.	২০। 20.
	১৪। 14.	২১। 21.

নং / No. রেজল্যুশন / Resolution Adopted

As per the advise of the chairman meeting of anti Ragging Committee held on 05.04.2022 at 2:30 p.m in Seminar Hall to discuss the various issues pertaining the department

Agenda :

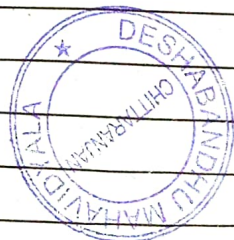
1. Confirmation of the proceeding of the previous meeting held on
2. Discuss on guidelines of the UAC regulations on curbing the menace of ragging.
3. online. Anti-ragging affidavit to be filled in by students with parents Undertaking.
4. Boards of Posters related to anti-ragging displayed in various places in College campus.
5. The college has taken all measures to take care of students with regard to ragging.

6. Misc.



The minutes of the meeting of anti-Ragging Committee given below:

1. The members of the Committee confirmed & Proceeding of the last meeting held on 09.08.2022.
2. The Committee decided to arranged anti-Ragging Awareness cum Workshops with 1st sem. Students.
3. To check and verify the online Anti-Ragging - affidavit to be filled in by students with parents undertakings of institutional status.
4. To discuss on the preventive measures to be adopted by the College authority with to ill-effects of Ragging.
5. The Committee decided to take appropriate action or redressal of complaints about the issues related to ragging of the students in college campus.
6. To displayed the Posters and notices in related to anti-ragging both within and out-side the college Campus.



SAHA
MEETING
RESOLUTION BOOK
মিটিং রেজল্যুশন বই
STUDENTS' GRIEVANCE
REDRESSAL

COMMITTEE 201

মিটিং রেজল্যুশন বহি

MEETING RESOLUTION BOOK

মিটিং নং / Meeting No.	
তারিখ / Date	৩/৪/২০১৪

উপস্থিত সভ্যগণের নাম
NAME OF MEMBERS PRESENT.

স্থান / Place	Principal's office
সময় / Time	৩:৪৫ Pm.

১।১.	Sanjiv	৮। ৪.
১।২.	Debnath	৯। ৯.
১।৩.	Sohmay Bag	১০। ১০.
১।৪.	Shel	১১। ১১.
১।৫.	Mukul Kamee	১২। ১২.
১।৬.		১৩। ১৩.
১।৭.		১৪। ১৪.

১৫। ১৫.
১৬। ১৬.
১৭। ১৭.
১৮। ১৮.
১৯। ১৯.
২০। ২০.
২১। ২১.

নং / No.	রেজল্যুশন / Resolution Adopted
	<u>CIRCULAR.</u> ০৩/০৪/২০১৪

The 1st meeting on Students Grievance Redressal Committee took place on 03/08/2018 at 3:45pm in Principal's Office.
The agenda for the meeting is as follows:-

(i) The students of Bengali Dept (Language Building) raised problem facing in their damaged blackboard.

(ii) More benches in Room No 26

(iii) Wooden chairs in Room 24, 25.

Plan of issues for the above issues.



MINUTES OF THE MEETING.

Principal Sir welcomed all the members. He expressed about students' request for damaged blackboards and benches and wooden chairs and ensured for fast solution. He has agreed to look into the matter effectively.

The meeting concludes unanimously at 4:30 pm



মিটিং রেজল্যুশন বহি

MEETING RESOLUTION BOOK

মিটিং নং / Meeting No.	
তারিখ / Date	4/2/2019

উপস্থিত সভ্যগণের নাম
NAME OF MEMBERS PRESENT.

স্থান / Place	Principal's office
সময় / Time	4.30 pm.

১। ১.	Sanjib	৮। ৪.
১। ২.	Deebolen	৯। ৯.
১। ৩.	Satimay Das	১০। ১০.
১। ৪.	Mukul Kumar	১১। ১১.
১। ৫.		১২। ১২.
১। ৬.	Kheta	১৩। ১৩.
১। ৭.		১৪। ১৪.

১৫। ১৫.
১৬। ১৬.
১৭। ১৭.
১৮। ১৮.
১৯। ১৯.
২০। ২০.
২১। ২১.

নং / No.	রেজল্যুশন / Resolution Adopted	Date: 2/2/19.
	<u>CIRCULAR.</u>	
	A meeting of Students Grievance Redressal Committee is scheduled on 4/2/2019 at 4pm in Principal's Office.	
	The agenda for the meeting is as follows:-	
	Discussion of Grievances recorded:-	
	(i) Students of BBA Dept (Nibedita Building) raised problem facing in toilet regarding water.	
	(ii) Students of BCA Dept (Nibedita Building) reporting problems in their computer maintenance.	
	Plan of actions for the above issues.	



Discussion of Grievances recorded in the last meeting are solved.

Plan of actions for the above issues.

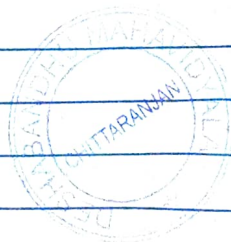
MINUTES OF THE MEETING :-

Principal Sir mentioned that the requests put up by the students should be looked into immediately and the college should make the life of students more comfortable.

Water supply will be enhanced to solve the problem.

Also computer maintenance problem will be solved out.

The meeting concludes ~~with~~ unanimously at 4:45 pm.



মিটিং রেজল্যুশন বহি

MEETING RESOLUTION BOOK

মিটিং নং / Meeting No.	
তারিখ / Date	10/8/2019

উপস্থিত সভ্যগণের নাম
NAME OF MEMBERS PRESENT

স্থান / Place	Principal's office
সময় / Time	9.30 pm

১। ১.	১। ৮.	১৫। ১৫.
২। ২.	২। ৯.	১৬। ১৬.
৩। ৩.	৩। ১০.	১৭। ১৭.
৪। ৪.	৪। ১১.	১৮। ১৮.
৫। ৫.	৫। ১২.	১৯। ১৯.
৬। ৬.	৬। ১৩.	২০। ২০.
৭। ৭.	৭। ১৪.	২১। ২১.

নং / No. ০৪/৪/২০১৯
রেজল্যুশন / Resolution Adopted

CIRCULAR

A meeting of Students Grievance Redressal Committee is scheduled on 10/8/2019 at 9:30 pm in Principal's Office.

The Agenda for the meeting is as follows:-

(i) Students of 3rd sem Hon Pol. Sc. Dept (Old building) raised issues regarding light (Tubelight) in Room No 015.

(ii) Students of Education Dept (Old Building) of reporting problem in library setting/arrangements.

Plan of action for the above issues



MINUTES OF THE MEETING,

10/2/2019.

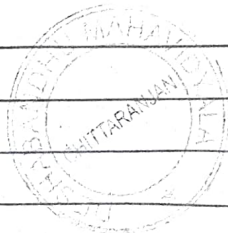
Discussion of Grievances recorded in the last meeting are solved.

After a discussion with the Principal Sir, it is decided that the matter will be considered & very soon the convenience for such matters would be facilitated for the benefit of the students.

4 Tubelights in Room No 15 will be installed.

Library Settings Arrangements ~~will~~ will start soon.

The meeting ended at 4:40 pm.



মিটিং রেজল্যুশন বই
MEETING RESOLUTION BOOK

মিটিং নং / Meeting No.	
তারিখ / Date	12/8/2020

উপস্থিত সভ্যগণের নাম
NAME OF MEMBERS PRESENT

স্থান / Place	Principal's Chamber
সময় / Time	3.45 Pm.

১। ১.	Sankar	৮। ৪.
২। ২.	what	৯। ৯.
৩। ৩.	Botimay Bag	১০। ১০.
৪। ৪.	Mukind Kumar	১১। ১১.
৫। ৫.	Alekh Kumar	১২। ১২.
৬। ৬.		১৩। ১৩.
৭। ৭.		১৪। ১৪.

১৫। ১৫.
১৬। ১৬.
১৭। ১৭.
১৮। ১৮.
১৯। ১৯.
২০। ২০.
২১। ২১.

নং / No.

রেজল্যুশন / Resolution Adopted

Circular

10/8/2020.

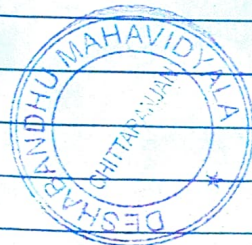
A meeting on Students Grievances Redressal Committee is scheduled on 12/8/2020 at 3:45 pm in Principal's Chamber.

The agenda for the meeting is as follows:-

(i) Students of Sanskrit Dept (Old Building) reporting problems regarding tables.

(ii) White boards necessary in Room 19, 26 (Old Building), former Staffroom (Language Building) etc.

Plan of action for the above issues



12/12/2020

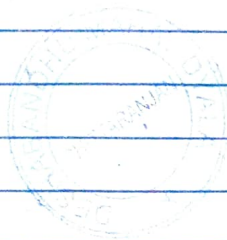
MINUTES OF THE MEETING.

Discussion of Grievances recorded in the last meeting are solved.

Principal Sir welcomed all the members and mentioned that tables and white boards will be supplied in necessary classes in respective buildings (Old and Langhage)

He appreciated others for their effort to make the College a better place for the students.

The meeting ended at 4:45 pm.



মিটিং রেজল্যুশন বহি

MEETING RESOLUTION BOOK

মিটিং নং / Meeting No.	
তারিখ / Date	22/8/2022

উপস্থিত সভ্যগণের নাম
NAME OF MEMBERS PRESENT

স্থান / Place	Principal's Chamber
সময় / Time	4 pm.

- | | | |
|-------|------------------------|---------|
| ১। ১. | Tridibi Sengupta Kundu | ৮। ৮. |
| ২। ২. | Acculohar by | ৯। ৯. |
| ৩। ৩. | Lotimay Bui | ১০। ১০. |
| ৪। ৪. | Mukul Kundu | ১১। ১১. |
| ৫। ৫. | | ১২। ১২. |
| ৬। ৬. | Khair | ১৩। ১৩. |
| ৭। ৭. | | ১৪। ১৪. |

- ১৫। ১৫.
১৬। ১৬.
১৭। ১৭.
১৮। ১৮.
১৯। ১৯.
২০। ২০.
২১। ২১.

নং / No. রেজল্যুশন / Resolution Adopted

CIRCULAR

20/8/2022

A meeting on Students Grievances Redressal Committee is decided to arrange on 22/8/2022 at Chamber of Principal around 4 pm.

The agenda for the meeting is as follows: —

- ① The sound system of the Seminar Hall (old building) is not working properly.
- ② Room no yet to put on the Computer Science room (old building) for identification.

Plan of actions for the above issues



22/8/2022

MINUTES OF THE MEETING.

Discussion of Grievances recorded in the last meeting are solved.

The request for proper sound system of the Seminar Hall (Old Building) has been duly sanctioned by a replacement of new one. Also a room will be soon allotted on Computer Science room (Old Building) for the better convenience of students.

The meeting ended at 4:35 pm.



মিটিং রেজল্যুশন বহি

MEETING RESOLUTION BOOK

মিটিং নং / Meeting No.	
তারিখ / Date	৭/০২/২০২৩

উপস্থিত সভ্যগণের নাম

NAME OF MEMBERS PRESENT

স্থান / Place	Principal's office
সময় / Time	4 P.m.

১। ১.	Tuidis Sontapan Kunder	৮। ৮.
২। ২.	Deeucholch my	৯। ৯.
৩। ৩.	Sotimay Beg	১০। ১০.
৪। ৪.	Khale	১১। ১১.
৫। ৫.	Mukul Kame	১২। ১২.
৬। ৬.		১৩। ১৩.
৭। ৭.		১৪। ১৪.

১৫। ১৫.
১৬। ১৬.
১৭। ১৭.
১৮। ১৮.
১৯। ১৯.
২০। ২০.
২১। ২১.

নং / No.	রেজল্যুশন / Resolution Adopted
	০৭/০২/২৩
	<u>CIRCULAR.</u>
	A meeting on Students Grievances Redressal Committee is scheduled on 9/2/2023 at Principal's Chamber.
	The agenda for the meeting is as follows-
	<ol style="list-style-type: none"> ① Toilet cleaning problem in School of Language Dept. ② Books for Sems 2 to 6 for Dept of English under NEP syllabus (Language Building) ③ A printer in NSS room for Volunteers (Old building) ④ Bigger room instead of former Language Staff room (Language Building)
	Plans of actions for the above issues



09/2/2023

MINUTES OF THE MEETING.

Discussion of Grievances recorded in the last meeting are solved.

Principal Sir heard all the problems enlisted in the Agenda and ensured better sanitation in toilet (School of Language Dept). He also suggests a printer necessary in NSS Room and accommodation of books for Sem II - IV (Under NEP) for Dept of English students.

As per the students' load is concerned, Sir has initiated to take plan to afford bigger room instead of former Language Staffroom.

← The meeting ended at 9:45 pm.



মিটিং রেজল্যুশন বই
MEETING RESOLUTION BOOK

Internal Complaints Committee
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittranjan

Year

B. B KUNDU ENTERPRISE • 62/1, M. G. Road, Kolkata 700 009
Tel : (033) 2241 9407 & (M): 98300 20632

NOTICE

Date - 20.07.2018

A meeting of Internal Complaints Committee will be held on 28.07.2018 at 2.30 PM in the IGAC room. All the members are requested to attend the meeting to consider the following agenda.

1. To discuss the process of creating awareness of the newly admitted students' regarding sexual harassment of women at work place.
2. To review on complaints received in previous year.
3. To prepare the annual report of the ICC for the session 2017-2018.
4. Miscellaneous.

Sagarika Nandy
Presiding Officer
Internal Complaints Committee
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan
Paschim Bardhaman-713331
West Bengal

A meeting of the Internal Complaints Committee was held on 28.07.2018 at 2.30 pm in the IGAC rooms.

The members present;

1. Sagarika Nandy.

2. Mousumi Kunder 28.07.18

3. Shampa Banjee (Chairman)

1. The members of Internal Complaints Committee discussed the rules and regulations regarding sexual harassment of women at work place, as notified by UGC. The students and other stakeholders were requested to inform the committee members for any kind of such incidence in the College premises. The members will take necessary steps to address the same. It was also decided that initiatives should be taken to make the campus, a sexual harassment free campus. Additionally, the presiding officer of ICC will brief the functioning and guidelines regarding sexual harassment of women at work place and students as well.

2. No complaint was received in the last year.

3. The Presiding Officer asked the members to take initiative regarding preparation of annual report.

4. No issue was arisen in the miscellaneous section.

Sagarika Nandy
Presiding Officer
Internal Complaints Committee
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan
Paschim Bardhaman-713331
West Bengal

2

3

4

NOTICE

Date - 04.01.19

A meeting of Internal Complaints Committee will be held on 11.01.2019 at 2.30 pm in the IGTC room. All the members are requested to attend the meeting to consider the following agenda.

Agenda;

1. To confirm the proceedings of the meeting held on 28.07.2018.
2. Discussion to create awareness and continuous sensitization for the students and faculty members.
3. Miscellaneous

Sagarika Nandy

Presiding Officer
Internal Complaints Committee
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan
Paschim Bardhaman-713331
West Bengal

Date: 11.01.2019

A meeting of the Internal Complaints Committee was held on 11.01.2019 at 2.30 PM in the IGAC room.

The members present:

1. Sagorika Nandy

2.

3. Mousumi Kunda 11.01.2019

4. Shampa Banerjee (Ganguly) 11.01.2019

1. The proceedings of the meeting held on 28.07.2018 were read out and duly confirmed.

2. It was decided that the committee members will meet the students' in regular basis to create awareness for safety and security if needed and to make the campus, a sexual harassment free campus.

3. Presiding officer informed the members that the annual report of the session 2017-2018 has already been submitted to the competent authority, Deshabandhu Mahavidyalaya, Chittaranjan.

Sagorika Nandy
Presiding Officer
Internal Complaints Committee
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan
Paschim Bardhaman-713331

NOTICE

Date - 02.08.19

A general meeting of the Internal Complaints Committee will be held on 07.08.2019 at 2.30 pm in the IGAC room. All the members are requested to be present.

Agenda :

1. To confirm the proceedings of the last meeting held on 11.01.2019.
2. To discuss the rules and regulations of UAC regarding sexual harassment with the newly admitted students.
3. To improve the complaint mechanism.
4. Miscellaneous.

Sagarika Nandy

Presiding Officer
Internal Complaints Committee
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan
Paschim Bardhaman-713331
West Bengal

Date ; 07, 08, 2019

A meeting of the Internal Complaints Committee was held on 07, 08, 2019 in the IGAC room,

1. Sagarika Nandy

2.

The members present : 3. Mousumi Kundu 07.08.19

4. Shampa Bera (Ganguly) 07.8.19

1. The Presiding officer read out the proceedings of the meeting held on 11.01.2019 and duly confirmed.

2. The members decided that the rules and regulations of ICC, as notified by UAC, will be informed to the newly admitted students. In this regard a request will be made to the authority to arrange a special session.

3. It was discussed that if any student faced any issue of sexual harassment and disturbance, they will immediately inform their subject related ^{female} faculty members ~~or~~ or others associated with ICC, as per their convenience.

This information will be shared to the students in the special class.

Sagarika Nandy

Presiding Officer
Internal Complaints Committee
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan
Paschim Bardhaman-713331
West Bengal

NOTICE

Date : 18.02.2020

A meeting of the Internal Complaints Committee will be held on 22.02.2020 at 2.30 pm in the IGAC room to discuss the following agenda. All are requested to be present.

Agenda:

1. To confirm the proceedings of the meeting, held on 07.08.2019.
2. Discussion on interacting girl students' in the Campus.

Sagarika Nandy
Presiding Officer
Internal Complaints Committee
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan
Paschim Bardhaman-713331
West Bengal

Date - 22.02.20

The meeting was held on 22.02.2020
at 2.30 pm in the IGAC room.

The members present:

1. Sagarika Nandy

2. Mousemi Kundu 22.02.20

3. Shampa Banerjee (Chairman) 22.02.2020

1. The Proceedings of the last meeting held on 07.08.2019 were read out and duly confirmed.

2. The members decided that they will interact with the girl students of the college in regular basis to monitor the occurrence of sexual harassment related issues or disturbance in the college campus.

Sagarika Nandy

Presiding Officer
Internal Complaints Committee
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan
Paschim Bardhaman-713331
West Bengal

মিটিং রেজল্যুশন বই

MEETING RESOLUTION BOOK

মিটিং -এর ক্রমিক সংখ্যা : / Serial No. of Meeting :

মিটিং এর তারিখ : / Date of Meeting 24.02.22

মিটিং এর স্থান : / Venue of Meeting : Principal's Chamber

মিটিং এর সময় : / Time of Meeting 2.30 pm.

উপস্থিত সভ্যগণের নাম / Name of Members Present

১/1	Sagarika Wandy 24.02.22	১৭/9	১৭/17
২/2	Mousumi Kundu	১০/10	১৮/18
৩/3	Sanelita Hossain 24/02/22	১১/11	১৯/19
৪/4	Shampa Barja 24/02/22	১২/12	২০/20
৫/5	Abekant Kaulo 24.2.22	১৩/13	২১/21
৬/6	Mhaleani B.	১৪/14	২২/22
৭/7		১৫/15	২৩/23
৮/8		১৬/16	২৪/24

ক্রমিক সংখ্যা
Serial No.

রেজল্যুশন / RESOLUTIONS ADOPTED

23.02.2022

NOTICE

This is to inform all members that the Internal Complaints Committee will hold a meeting on February 24, 2022 at 2.30 pm in the Principal's chamber to discuss the upcoming Women's Day Celebration. All members are requested to make themselves available for the said purpose.

Sagarika Wandy
Presiding Officer
Internal Complaints Committee
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chitra
Paschim Bardhaman-713001
West Bengal

The Internal Complaints Committee (ICC), Deshabandhu Mahavidyalaya convened a meeting on January 24, 2022 at 2.30 pm in the Hon'ble Principal's office. The following concerns were discussed and resolved;

- The existing Complaints Box beside the ground floor Notice Board will be repurposed and made functional for the use of students. It was rationalized that a distance from the usual thoroughfare of the college will afford certain degrees of anonymity and privacy for students who mean to voice their opinion or issues.
- It was further decided that an institutional email id, specifically for the use of the ICC will be formed. The Same will also be posted on the college website along with the personal no. of the Presiding Officer and one other member of the cell.
- A detailed discussion on the upcoming International Women's Day, March 8 was held. It was set that two external speakers will be invited for the same; along with Ms. Puspa Das from the local Self Help group. The event will also have students performing and a possible procession with the theme "Walk in Her Shoes".
- It was resolved that the ICC will organize a Gender Sensitization Workshop in near future.
- Dr. Mukul Kamle, Hon'ble member of ICC ^{suggested} raised formation of an NGO for various student welfare activities in the future. It was decided that the possibility will be discussed in the next meeting in the Teachers' Council.

Sagarika Nandy
Presiding Officer
Internal Complaints Committee
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan
Paschim Bardhaman-713331
West Bengal

মিটিং রেজল্যুশন বই

MEETING RESOLUTION BOOK

মিটিং -এর ক্রমিক সংখ্যা : / Serial No. of Meeting :

মিটিং এর তারিখ : / Date of Meeting 21.06.22

মিটিং এর স্থান : / Venue of Meeting : IQAC Room

মিটিং এর সময় : / Time of Meeting 1.30 PM

উপস্থিত সভ্যগণের নাম / Name of Members Present

১/১	Sagarika Nandy 21.06/22	৯/৯	১৭/১৭
২/২		১০/১০	১৮/১৮
৩/৩	Sameer Kumar 21/06/22	১১/১১	১৯/১৯
৪/৪	Shampa Bandyopadhyay 21/06/22	১২/১২	২০/২০
৫/৫	Muskan Banerjee 21/06/22	১৩/১৩	২১/২১
৬/৬		১৪/১৪	২২/২২
৭/৭		১৫/১৫	২৩/২৩
৮/৮		১৬/১৬	২৪/২৪

ক্রমিক সংখ্যা
Serial No.

রেজল্যুশন / RESOLUTIONS ADOPTED

Date: 17.06.2022

NOTICE

A meeting of Internal Complaints Committee of Deshabandhu Mahavidyalaya, Chittaranjan will be held on 21.06.2022 at 1.30 pm in the IQAC room. All the members are requested to attend the meeting to discuss the following agenda.

Agenda:

1. Confirmation of the proceeding of the last meeting
2. Procedure of program on 23.06.2022
3. Miscellaneous

Sagarika Nandy
Presiding Officer
Internal Complaints Committee
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan
Paschim Bardhaman - 713331
West Bengal

- The meeting started with the confirmation of the minutes of the previous meeting.
- It was resolved that the Institute and ICC will collaborate with Global Health Organization to organize a menstrual health and feminine hygiene workshop for the students.
- It was further resolved that the workshop will be hosted online, with the students attending the session in the Seminar Room, with a broadcast screening. It was decided that students with medical conditions may be allowed to attend the session from their home.
- The cell proposed that one of the members Dr. Shrabani Basu, will be coordinating with the resource organization to plan the session.
- In the miscellaneous section, it was reported that a Sanitary Napkin Vending machine has been installed in the washroom adjacent to the Girls' Common Room and that Mrs. Sagarika Nandy, Presiding Officer, ICC has also demonstrated the use of it to the female students.

Sagarika Nandy

Presiding Officer
Internal Complaints Committee
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan
Paschim Bardhaman-713331
West Bengal

মিটিং রেজল্যুশন বই

MEETING RESOLUTION BOOK

মিটিং -এর ক্রমিক সংখ্যা : / Serial No. of Meeting :

মিটিং এর তারিখ : / Date of Meeting 17-03-2023

মিটিং এর স্থান : / Venue of Meeting : Principal's chamber

মিটিং এর সময় : / Time of Meeting 2.30 pm.

উপস্থিত সভ্যগণের নাম / Name of Members Present

১/1	Sagarika Nandy	৯/9	১৭/17
২/2	Mousumi Kundu	১০/10	১৮/18
৩/3	Sandipita Hazra	১১/11	১৯/19
৪/4	Shampani Banerjee	১২/12	২০/20
৫/5	Klukul Kaul	১৩/13	২১/21
৬/6	Mukta B.	১৪/14	২২/22
৭/7		১৫/15	২৩/23
৮/8		১৬/16	২৪/24

ক্রমিক সংখ্যা
Serial No.

রেজল্যুশন / RESOLUTIONS ADOPTED

Date: 14.3.2023

NOTICE

This is to inform all members that the Internal Complaints Committee will hold a meeting on March 17, 2023 at 2:30 pm in the Principal's chamber to discuss the upcoming Women's Day celebration (scheduled March 24, 2023). All members are requested to make themselves available to discuss the following agenda.

Agenda:

1. Confirmation of the proceedings of the last meeting
2. Procedure of program on 24.03.2023
3. Miscellaneous

Sagarika Nandy

Presiding Officer
Internal Complaints Committee
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan
Paschim Bardhaman-713331
West Bengal

ক্রমিক সংখ্যা
Serial No.

রেজল্যুশন / RESOLUTIONS ADOPTED

Resolution 1: All of the previous meeting's resolutions were accepted (dated 21.06.2022), and the requisite steps were taken.

Resolution 2: It was agreed that March 24 will be celebrated as International Women's Day in 2023.

It was suggested that Prof. Gopa Samanta, from Burdwan University, Department of Geography, be invited as the special guest and keynote speaker for the celebration of International Womens' Day, 8th March.

Resolution 3: In the miscellaneous agenda, it was resolved that ICC will soon organize a sexual harassment awareness session for the students of the College.

The members have resolved to encourage the students and other stake holders to come forward, with their complain if they have any such complain relating to sexual harassment, to the committee.

The members have also recorded the fact that no complain of sexual harassment was reported to the committee, during the period of July 2021 to June 2022.

The meeting ended with a formal vote of thanks to all present.

Sagarika Nandy

Presiding Officer
Internal Complaints Committee
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan
Paschim Bardhaman-713331
West Bengal



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 18/05/2024

Documents of Clarification 5 for 5.1.4: Mechanism of Redressal document, Website Screenshot and Link of the same


(Tridib Santapa Kundu)
Principal
Principal
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan



DESHABANDHU MAHA VIDYALAYA, CHITTARANJAN

NAAC Accredited B + College

(Affiliated to Kazi Nazrul University)

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC

P.O. – Chittaranjan, District – Paschim Bardhaman, West Bengal,
India, PIN – 713 331

Date: 10.05.2024

Website Link: <https://dbmcrj.ac.in/students'-grievance/>

The screenshot shows a web browser window displaying the website of Deshabandhu Mahavidyalaya. The page title is "Students' Grievance Redressal Committee". The navigation menu includes Home, The College, Administration, Academics, Admission, Library, Events, and Students' Corner. The main content area is titled "Students' Grievance Redressal Mechanism" and contains a detailed paragraph about the grievance redressal policy. Below the paragraph is a bulleted list of committees: Anti-Ragging Committee, Students' Grievance Redressal Committee, and Women's Cell.

Students' Grievance Redressal Committee

Students' Grievance Redressal Mechanism

The grievance redressal policy is designed to establish a mechanism through which every student is afforded a platform to voice their concerns and challenges. The institution fosters a conducive environment for the submission of complaints or grievances and proactively engages in delivering a satisfactory and prompt resolution to the students' issues. The college is equipped with a grievance redressal committee to facilitate this process. The grievance redressal committee addresses various types of grievances. Five complaint boxes are strategically placed in different buildings and different places, ensuring accessibility and confidentiality. These boxes are systematically opened on a regular basis, with the commitment that student grievances are addressed within a span of seven days. Issues specifically concerning female students are managed by the institution's Women's Cell. This cell operates under the leadership of a distinguished senior female teaching staff. Furthermore, the college has a separate committee to addressing incidents of sexual abuse against female students, female faculty members and female non-teaching staff at the work place according to the guidelines of UGC. One box is installed for internal complaints Committee on the ground floor beside the notice board of the main building. The link to this committee has been provided on the website and complaints regarding sexual harassment at the work place can be emailed to complaints@dbmcrj.ac.in. Additionally, the college has established multiple committees dedicated to scrutinizing and resolving student grievances, thereby ensuring a comprehensive and inclusive approach to grievance redressal.

- Anti-Ragging Committee
- Students' Grievance Redressal Committee
- Women's Cell


(Tridib Santapa Kundu)
Principal
Principal
Deshabandhu Mahavidyalaya
Chittaranjan